भाकपा (माओवादी) ओड़िशा राज्य कमेटी का मुखपत्र

# जनसंग्राम

अंक-5 मई 2015 सहयोग राशि 15रु

## जनता के लिये मरमिटना हिमालय पर्वत से भी महान है

## 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह जोरशोर के साथ मनाओ

## संपादकीय

दुश्मन के लिये लड़ते हुए मरना पंख से भी हलका होता है. वही जनता के लिये लड़ते हुए मरना हिमालय पर्वत से भी महान होता है. इसलिये अमर शहीद मृत्युंजय हैं. वे मां-बाप व परिवार धन्य हैं जिन्होंने जनता के लिये लड़ते हुए बहादुरी के साथ मरने वाले सुपुत्रों, सुपुत्रियों को जन्म दिया. जिन शहीदों ने इस देश की मुक्ति के लिये अपने प्राणों का त्याग किया. दीर्घकालिन लोकयुद्ध को आगे बढ़ाने के लिये जनता को संगठित किया. क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिये फासीवादी सरकार एक तरफ आपरेशन ग्रीनहंट सैनिक हमला चला रही है. तो दूसरी तरफ झूठी सुधार मुहिमें भी चला रही है. इस फासीवादी अभियान का मुहंतोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए तमाम लाल जनयोद्धाओं को हमारी ओड़िशा राज्य कमेटी शत्-शत् नमन करती है. उन शहीदों के सपनों को पूरा करनी की शपथ लेती है. उन शहीदों को लाल सलाम अर्पित करती है.

महान नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान आंदोलन से लेकर आज तक क्रांतिकारी जनयुद्ध में, कृषि क्रांति की राह पर चलते हुए हजारों युवाक-युवतियों, मजदूर किसानों, छात्र-बुद्धिजिवियों ने कुर्बानियां दी हैं. पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जनसंगठनों, क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थकों ने अपने खून से जनयुद्ध की राह को रोशन किया है. हमें कभी भी उन शहीदों की शहादतों को भूलना नहीं चाहिए. अभी वे हमारे साथ भौतिक रूप से नहीं हैं. लेकिन उनका राजनैतिक-सैद्धांतिक-सैनिक व्यवहार, दक्षता हमारे साथ है. हमें उनके व्यवहार दक्षता व आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर शहीदों की राह पर चलते हुए राज्य की व्यापक जनता को संगठित करने का संकल्प ले कर 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह का पालन करेंगे. व्यापक जनता को संगठित करते हुए, आंदोलन को कठिन परिस्थितियों से बहार लाने के लिये खुद का बोल्शेविककरण करते हुए सुधरेंगे. यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजली होगी.

राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार में कई कामरेडों ने अपने अनमोल प्राणों को न्यौछावर किया हैं. इनमें काशिपुर बासंगमालि शहीद कामरेड रवी, लेंज सहित कई कामरेड्स, नियमगिरी शहीद कामरेड सुक्कई, पड़कीपाली घटना में कामरेड्स कोसा, चांदनी (नताशा), पारो, राजबति, बिरसा (लच्छू), रवी, अर्जून व कामरेड सुभाष दादा सहित दो अन्य ग्रामीण शहीद हुए. कामरेड सुक्कू उर्फ मोहन शहीद हुए. राजातालब झूठी मुठभेड़ में माधव सिंग ठाकूर व रमेश साहू को मार डाला, सनभांजीपाली में कामरेड मंजूला शहीद हुई. जोलाराव घटना में कामरेड्स समिरा, अरुणा और अमीला शहीद हुईं. सोनाबेड़ा एरिया कामरेड दिनेश व रिंगझोला में कामरेड मोती शहीद हुई, क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक रैसिंग भूंजिया भी बीमारी से शहीद हुए. इसके अलावा गंधमर्दन में कामरेड रोंडा (धनाजी), संतोष, अजय (सोनू), विजय शहीद हुए. अभी 8 मार्च को कालाहांडी जिला के गोलामुंडा ब्लाक, छुरा पहाड़ पर जुनागढ़ दस्ता डिप्यूटी कमांडर कामरेड मिरिया गोटा (सूरज, सूरेश, शिवलाल) शहीद हुआ. ये सब कामरेड्स जनता की मुक्ति के लिये, आंदोलन को विस्तार

भाकपा (माओवादी) ओड़िशा राज्य कमेटी का मुखपत्र

# जनसंग्राम

अंक 5 - मई 2015

संपादकीय... 28 जुलाई शहीद सप्ताह पर
पेज 02

आदर्श
नक्सलबाड़ी आंदोलन में ओड़िशा का पहला शहीद कामरेड रमेश साहू..
पेज 04

विशेष लेख
भारतीय क्रांति, सब व चुनौति, गणपति
पेज 05

सैद्धांतिक लेक
सिद्धांत – कामरेड स्टालीन
पेज 12

श्रृंखला
भगतसिंग की बात सुनो, माओवाद की राह चुनो
सांप्रदायिक दंगे व उनका इलाज – भगत सिंह
पेज 15

आम बजट समीक्षा
पूंजीपतियों के हित में जनविरोधी बजट
पेज 17

दूसरी पत्रिकाओं से
सब के साथ सब का विकास के नाम पर...पहाट
पेज 20

ज्वलंत मुद्दा
भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक
पेज 24

प्रेस विज्ञप्तियां
पेज 26

डिवीजन से रिपोर्टें
पेज 31

शहीद कामरेड सूरज की जीवनी
पेज 35

**पत्रिका एक संगठनकर्ता भी होती है.**

-लेनिन

'जनसंग्राम' आपकी अपनी पत्रिका है, पढ़िये और पढ़ाइये. हमें अपनी राय, सुझाव व आलोचनाएं भेजिए...

shashipatnayak2014@gmail.com
jansangram2015@gmail.com
www.bannedthought.net
www.icpspwindia.wordpress.com

करने के लिये अपनी जान दिये हैं.

हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी जन आंदोलन को कुचलने, नेतृत्व का सफाया के मकसद से सरकार हजारों-हजार अर्ध सैनिक बलों, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आइटीबीपी, और कोबरा, एसओजी जैसे कमांडो बलों को उतार कर, कार्पेट सैक्युरिटी के तहत नजदीक-नजदीक नये-नये कैंप डाल रही है. भारी कुंबिंग एरिया डामिनेशन अभियानों से जनता पर दभाव बढ़ाकर झूठी सुधार मुहिमों को संचालित कर रही है. अर्ध सैनिक बल अपनी क्रूर छवी सुधारने सिविक एक्शन कार्यक्रम के जरिए जनता को लुभा कर, गुमराह कर आंदोलन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. ताकि आंदोलन को विस्तार होने से रोका जा सके.

दूसरी तरफ रमन सिंग व नवीन पटनायक ने देश की खनिज संपदाओं, प्राकृतिक संसाधनों को कार्पोरेट घरानों, विदेशी कंपनियों को हवाले करने के लिये ही आक्रामक रूप से निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की साम्राज्यवाद परस्त नीतियों को लागू कर रहे है. इसके साथ साथ जनाता के अपने जल-जंगल-जमीन, इज्जत व अधिकार के लिये चल रहे जन आंदोलनों को कुचला जा रहा है. जन संगठनों व जन संघर्षो पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. इतना ही नहीं जन आंदोलन के नेताओं, कार्यकर्ताओं को मारने के लिये लाखों-करोड़ों इनाम घोषित किए जा रहे हैं. बेशर्मि के साथ हत्यारों को लाखों-लाख इनाम दिये जा रहे हैं. यह सरकार द्वारा दी जाने वाली फिरौती नहीं तो और क्या है? मानसिक युद्ध के तहत क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है. क्रांतिकारियों को आत्मसमर्पण कर खुशहाली का झूठा सपना दिखाया जा रहा है. सच्चाई ये है कि सरंडर कर के लोग कुत्ते की जिंदगी जीने पर मजबूर हो रहे हैं. सरंडर करने वालों को जनता पर दमन को बढ़ाने के लिये उनका इस्तेमाल किया जा रहा है. ये सारे हथकंडे आदिवासी विद्रोहों को कुचलने के लिये अंग्रोजों द्वारा अपनाये जाते थे. जो आज भी काले अंग्रेज अपना रहे हैं. इस योजना को जनसंघर्षो के जरिए ध्वस्त करना है.

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव के समय महंगाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, कालाधन विदेशों से वापिस लाने लोकलुभावन नारे दिये थे. लेकिन सत्ता में आने के बाद ही सब कुछ भूल कर सबसे पहले अमेरीकी साम्राज्यवाद के समाने सिर झुक कर परमाणू उर्जा संयंत्र, का करार किया और जापान, सिंगापुर, जर्मनी , फ्रांस जैसे देशों के पूंजीपतियों का घर घर बरकर पूंजी निवेश के लिये निमंत्रण दे रहे है. इसके लिये तर्क दे रहा है कि इस से देश का विकास होगा. क्या इतिहास में कभी किसी साम्राज्यवादी देश ने किसी देश का विकास किया है? नहीं साम्राज्यवाद इतना ही जानता है. कि तमाम सपत्तियों को लूट कर उसे कंगाल बनाना. अमेरिका सहित अन्य साम्राज्यवादियों, दलाल पूंजपतियों को देश को बेचने के लिये सैकड़ो गुप्त एमओयू कर रहा है. नियमगिरी, गंदमर्धान, कोरापुट, काशिपुर, जगतसिंगपुर, सुंदरगढ़ व बस्तर की जनता पर हमेशा विस्थापन की तलवार लटकी रहती है. दंतेवाड़ा के डिलीमिली में मेगा स्टील प्लांट का उद्घाटन कर, बैलाडिला के बाद और एक बड़े विस्थापन का उद्घाटन मोदी ने 9 मई को कर दिया है. यह परियोजना 10 हजार वर्ग किलोमीटर इलाके को प्रभावित करेगी. यह मेगा स्टील प्लांट व दल्ली-रावघाट-जगदलपुर रेल लाईन लाखों आदिवासियों को विस्थापित करने वाली परियोजानाएं हैं. जनता का समस्याओं को हल न कर मोदी पूंजीपतियों, विदेशी कंपनियों की समस्याओं को हल कर रहा है. जनता का विकास नहीं व साम्राज्यवादियों व दलाल पूंजीपतियों, जमींदारों का विकास कर रहा है. किसानों की जमीनों को कार्पोरेटों घरानों को सौंपने के लिये भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया है. लेकिन पूरे देश में किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गयी है, उस पर मोदी का कोई ध्यान नहीं है. किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं. और मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है. भाजपा सत्ता में आनके के बाद ब्राह्मणवादी हिंदू फासिवादियों का देश के कोने कोने में दलित आदिवासियों इसाईयों मुसलमानों और महिलाओं पर हमला, अत्याचार बढ़ गया है. घर वापसि के नाम से दलितों के गला में माला डालकर हिंदू धर्म में शामिल कर ले रहे हैं. इन सबका हल जनयुद्ध की सफलता से ही संभव है.

हमारी पार्टी तमाम किसान-मजदूरों, छात्र-बुद्धीजिवियों, जनवाद प्रेमियों, महिलाओं से अपील करती है कि देश को साम्राज्यवाद-सामंतवाद-दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के चंगुल से आजाद करवाने के लिये माओवादी पार्टी में शामिल हो जाओ. मोदी की जनविरोधी, आदिवासी विरोधी, किसान-मजदूर-कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन खड़ा करें. दलितों, अल्पसंख्यकों पर हो रहे ब्राह्मणवादी फासीवादी संघ परिवार के हमलों के खिलाफ तमाम प्रगतिशील, धार्मिक सद्भाव की ताकतों को संयुक्त मंच पर आकर विरोध करना चाहिए. मोदी की साम्राज्यवाद व पूंजीवाद परस्त नीतियों का पर्दाफाश करते हुए लड़ाकू संघर्षो का निर्माण कीजिये.

**शहीद तुम्हारे सपनों को**
**मंजिल तक पहुंचाएंगे.**

**मोदी सरकार की साम्राज्यवाद परस्त**

**एलपीजी नीतियों का विरोध करेंगे.**

**मोदी के मुखोटे का पर्दाफाश करेंगे.**

**भाकपा (माओवादी) जिंदाबाद.**
**इंकलाब जिंदाबाद**

# कामरेड रमेश साहू

## नक्सलबाड़ी आंदोलन में ओड़िशा का पहला शहीद.

इस लेख का अनुवाद, ओड़िआ में छपी *नक्सलबाड़ी रो 40 बरस* पुस्तक से किया गया है. सं.

चीन के महान नेता कामरेड माओ त्सेतुंग ने चीनी क्रांति के दौरान कहा था कि - हजारों-हजार शहीद अपने प्राणों का बलिदान देकर क्रांति की राहों को अपने लहू से सींच रहे हैं. आइये इस रक्तरंजित लाल झंडे को लेकर क्रांति की राहों पर आगे बढ़ें. इस कथन को लिखने का उद्देश्य है कि आज नक्सलबाड़ी आंदोलन ओड़िशा समेत पूरे देश में फेल चुका है. यह पूरे क्रांतिकारी आंदोलन में एक उल्लेखनिय बात है. पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग जिला, सिलिगुड़ी सब डिविजन में एक छोटा सा गांव था नक्सलबाड़ी. 25 मई 1967 में शुरु हुआ थी वहां से कृषि क्रांति. वहां से फूटी चिंगारी पूरे देश में दावानल बनकर उभरी. इस आंदोलन में जाने कितने ही नर-नारियों नें अपने प्राणों की आहुति दी. ओड़िशा के कई इलाकों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया था.

नक्सलबाड़ी के रास्ते पर चलते हुए पीछले 46 सालों में दर्जनों साथी ओड़िशा में शहीद हुए हैं. इनमें से कामरेड रमेश ओड़िशा के पहले शहीद थे. आंध्रा-ओड़िशा सीमा पर स्थित रंगामाटिआ पहाड़ पर बुकूचिरी गांव है. वहां 22 दिसंबर 1969 के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने कामरेड रमेश सहित अन्य पांच कामरेडों की गोली मार कर हत्या कर दी थी.

ब्रह्मपुर के निकट सोनादेइ गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में कामरेड रमेश का

जन्म हुआ था. हाई स्कूल में पढ़ते समय वे कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन गए थे. बाद में उन्होंने ब्रह्मपुर इंजिनियरिंग कालेज में दाखिला लेकर इंजिनियरिंग की पढ़ाई शुरु की. 1964 में ओड़िशा में हुए छात्र आंदोलन ने ओड़िशा कांग्रेस सरकार की नींव हिला दी थी. उस आंदोलन में कामरेड रमेश की सक्रीय व नेतृत्वकारी भूमिका थी. आमसभाओं में उसके ओजपूर्ण भाषणों ने उनको एक छात्र नेता के तौर पर स्थापित कर दिया था. वे बहुत अच्छे दोस्त और बड़े देशप्रेमी थे. इसके भाषणों में निशाना हमेशा देश में बढ़ता भ्रष्टाचार व महंगाई होती थी. वे कहते थे कि इसका एकमात्र हल है सशस्त्र संघर्ष के जरिए समाजवादी समाज की स्थापना. इस विषय पर उनके तर्क कोई नहीं काट पाता था. इतिहास, राजनीति और मार्क्सवादी विचारधारा की पुस्तकों व पत्रपत्रिकाओं का अध्ययन उसका हर रोज का काम था. 1966 में वह डिप्लोमा इंजिनियर छात्र संघ के वे अध्यक्ष चुने गए थे. तब उन्होंने एक राज्यस्तरीय छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था. तब उनके द्वारा उठाई गयी दस प्रमुख मांगों में से सरकार को सात मांगों को मानने पर मजबूर होना पड़ा था.

पश्चिम बंगाल में 1967 में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई थी. वहां तब संशोधनवादी वामपंथियों की मिलीजुली सरकार बनी थी. उसी साल शुरु हुआ था वहां पर नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह. इसी की तर्ज पर आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिला में भी आंदोलन शुरु हो गया था. साथी रमेश इस आंदोलन में कूद पड़े थे. उन्होंने डिप्लोमा इंजिनियरिंग पास कर लिया था. उस समय डिप्लोमा करने वालों को बड़ी आसानी से सरकारी नौकरी मिलती थी. लेकिन उन्होंने देश की सेवा के लिये इस के मोह को छोड़ कर, सशस्त्र क्रांति एकमात्र रास्ता की विचारधारा को आत्मसात किया. उसने उस समय कई महत्वपुर्ण लेखों का अनुवाद किया. उस समय एक नारा बहुत प्रचलित था -ये आजादी झूठी है - वह हमेशा दोहराते थे.

साथी रमेश के विचार...

"तेलंगाना आंदेलन को हराया नहीं जा सकता. भारत के समाजवादी राष्ट्र बन सकता है. चीन कम्युनिस्ट आंदोलन की सफल कहानी, हरेक कम्युनिस्ट पार्टी के लिये अनुकरणिय है. नक्सलबाड़ी लाईन पर जो सशस्त्र संग्राम शुरु हुआ है, इस पर आगे बढ़ते हुए ही भारतीय क्रांति सफल होगी." एक छोटे इलाके में शुरु हुए संघर्ष से कैसे पूरे देश में क्रांति आ सकती है? प्रश्न का जवाब देते हुए उसने कहा था "जरूर आ सकती है. इसमें संदेह की कोई गुंजाईश

( www.revolutionarydemocracy.com पर पोस्ट लेख का हिंदी अनुवाद)

...विशेष लेख...

# भारतीय क्रांति के सबक और चुनौतियां

गणपति

महासचिव भाकपा (माओवादी)

हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने पार्टी की दसवीं बरसगांठ के मौके पर दिये अपने संदेश में पीछले 10 सालों मूल्यांकन किया है . जिसमें हमारे द्वारा प्राप्त उपलब्धियों व विस्तार को दर्शाया गया है. उसमें हमारी कमजोरियों व खामियों सहित वस्तुगत परिस्थिती में अनुकूल व प्रतिकुल पहलूओं पर भी ध्यान दिलाया गया है .यह लेख पूरी पार्टी के सामने रखे गए सीसी संदेश के कुछ मुद्दों का विस्तार है .जो केंद्रीत है कुछ महत्वपुर्ण सबकों व चुनौतियों पर जिसको हमें हराना है .

हमारी पार्टी नवजनवादी क्रांति को संपन्न करने के लिये शासक वर्गों के खिलाफ दीर्घकालीन जनयुद्ध के रास्ते पर पीएलजीए का नेतृत्व कर रही है. यह एक पूर्ण यूद्ध है, यह हर पहलू से - सैद्धांतिक, राजनैतिक, सैनिक, सांस्कृतिक, मानसिक और आर्थिक रूप दीर्घकालिक है. यह भारतीय राजसत्ता को ध्वस्त करके, नयी राजसत्ता निर्माण करेगा, जैसे अभी वर्तमान में क्रांतिकारी जनताना सरकार है. यह अभी छोटी सी ताकत है, इसे बड़े व शक्तिशाली दुश्मन को हराना है. इसलिये इसके सामने युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है. क्रांतिकारी युद्ध का हर तरीके से दमन करने के लिये शासक वर्गों द्वारा प्रतिक्रांतिकारी युद्ध चलाया जा रहा है. इसका मकसद हमारा पूरी तरह से सफाया करना है. यह हमारी पार्टी की सामान्य समझदारी है और हम व्यवहार में प्रतिक्रांति को हरा कर उपलब्धी हासिल कर सकते हैं. लेकिन अभी तक हमारे द्वारा जो प्रयाप्त समय व ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया. दुश्मन ने अपनी प्रतिक्रांतिकारी युद्ध रणनीति व कार्यनीति (लो इनटेनसिटी कन्फलिट एलआईसी) को, विश्वव्यापी अनुभव से विकसित कर लिया. इसलिये हमारे सिद्धांत के अनुसार, हमारे व्यापक दृष्टिकोण के चलते हमारे अपने अनुभव को रोक नहीं पाया. हमने बाद में दुश्मन की

---

नहीं है. वह हमेशा कहा करते थे कि क्रांति हमेशा कम लोगों से ही शुरू होती है. कुछ लोग अपने प्राणों का बलिदान देकर क्रांति की नींव डालते हैं. जैसे घर के निर्माण से पहले नींव डाली जाती है. और नींव हमेशा माटी के नीचे दब जाती है. वह बहार दिवारों की तरह नहीं दिखती. उसी प्रकार हम हैं भारतीय साम्यवादी समाज की नींव. हमें कोई याद रखे या न रखे लेकिन हमारे प्राणों की नींव पर ही खड़ी होगी साम्यवादी समाज की विशाल इमारत. हजार-हजार शहीदों के त्याग व बलिदान पर देश के करोड़ों-करोड़ गरीबों, कंगालों व गुलामों के जीवन की मुक्ती होगी. तब बनेगा सोने का भारत."

इस सपने को पूरा करने के लिये उसने परिवार से मिली अपने हिस्से की संपत्ति को बेच कर पूरा पैसा पार्टी को सौंप दिया था.वे आगे बढ़ रहे भूमिगत आंदोलन में शामिल हो गए. वे गांव-गांव में संगठन निर्माण के कामों में जुट गए. पार्टी के निर्देश पर वे किसान क्रांति के एक निडर सैनिक के रुप में अपने आप को बदल लिये. उस समय आंदोलन का निर्मूलन करने के लिये संगठन के नेताओं, कार्यकर्ताओं के झूठे एनकाउंटर, पकड़ कर गोली मारना शासक बलों के सशस्त्र बलों ने शुरू कर दिया था. उसी समय झूठे एनकाउंटर करने के इरादे से साथी रमेश सहित अन्य पांच लोगों को पकड़ लिया गया था. उस समय कामरेड रमेश ने कहा था "तमाम कानूनों का उल्लंघन करके तुम हमें मार रहे हो. तुम लोग हमारे दुश्मन नहीं हो. हम भी तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं. एक शोषणमुक्त समाज बनाने के लिये हम लड़ रहे हैं. शोषक वर्गों को खत्म करना हमारा लक्ष्य है. पुलिस का कर्तव्य है देश व देशवासियों की सुरक्षा करना. तुम शोषक वर्गों के लिये हमारे जैसे देश प्रेमियों को मार रहे हो यह घोर अन्याय है. किसी न किसी दिन तुम लोग यह आत्मसात जरूर करोगे कि हमारा आंदोलन देश की मुक्ति के लिये है. तुम लोग भी हमारे संगठन में शामिल होगे. यही इतिहास है. इंकलाब जिंदाबाद.....इंकलाब जिंदाबाद.... "

एक उत्साहित जीवन का अंत हुआ. बहुत कम ही लोग रमेश साहू के बारे में जानते हैं. उसके कहे अनुसार वे हैं आगामी साम्यवादी समाज की नींव. यह त्याग व बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. आज हजार-हजार संख्या में युवक-युवती, किसान, भूमिहीन, आदिवासी, मजदूर इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं. रक्त से रंजित लाल झंडे को उठाये आम जनता आगे बढ़ रही है.

कामरेड रमेश के आधुरे सपनों को पूरा करने के लिये, उसके बनाये त्याग व बलिदान के पथ पर आज देश की युवा शक्ति आगे बढ़ेगी. इसी कामना के साथ जनसंग्राम.

एलआईसी नीति के खिलाफ अपनी नीति बनाई. लेकिन इसमें विलम्ब के चलते, हमारी पूरी पार्टी इसकी तीव्रता की गहरी समझदारी को नहीं पकड़ पाई कि प्रतिक्रांतिकारी युद्ध ठोस रूप से, व्यापक पैमाने पर पुर्ण युद्ध है. इस बाधा के कारण हम दुश्मन द्वारा खड़ी की जा रही चुनौतियों व उसके नये तरिकों का सामना करते हुए, अपेक्षित सफलतायें प्राप्त नहीं कर पाये.

हमारी पार्टी ने बड़ी संख्या में, दुश्मन के हमलों में हमारे कामरेडों को खो दिया. इसमें सीसी से लेकर ग्राम स्तर तक के कामरेड हैं. 2005 मई से अब तक नेतृत्व की भारी क्षति हुई है, एकता कांग्रेस के बाद भी यह जारी रही और 2011 में इस स्थिति ने गंभीर रूप ले लिया. नेतृत्व बड़े स्तर पर खुद की व कतारों की रक्षा करने में फेल हो गया. इससे के चलते नवजनवादी क्रांति के तीन जादूई हथियार - पार्टी, पीएलजीए व संयुक्त मोर्चा भी कमजोर हुआ है. यह एक बहुत गंभीर विफलता है.

क्रांति में बलिदान अनिवार्य है. कभी भी क्रांति की अंतिम जीत दुश्मन की शक्ति को ध्वस्त करते हुए खुद की शक्ति को विकसित करते हुए हो सकती है. यही सूत्र दीर्घकालीक जनयुद्ध पर लागू होता है. जब जनता हथियार उठाती है, विद्रोह कर दुश्मन का सफाया करती है, वे क्रुरत्म प्रतिहमला करेंगे. वे क्रांति का खात्मा करने के लिये अत्यंत खूंखार व क्रूर हमले करेंगे. नेतृत्व को हथियारबंद क्रांति की विजय के लिये, प्रतिक्रांति को हराते हुए, अंततः उसे पूरी तरह साफ कर देने के लिये त्यार रहना चाहिए. युद्ध में पार्टी को दुश्मन के हमलों से, वामपंथी, दक्षिणपंथी रुझानों से बचाते हुए विजय की ओर ले जाने में जीत के लिये निर्णायक पहलू है. यह नेतृत्व की जिम्मेदारी है. हम दुश्मन को टुकड़ों-टुकड़ों में खत्म करते हुए, कदम दर कदम अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए दीर्घकालिन लोकयुद्ध को हमलों से बचा पायेंगे.

नक्सलबाड़ी दौर में पिछेहट (setback) होने का सबसे महत्वपुर्ण कारण था, केंद्रीय नेतृत्व सहित आत्मगत ताकतों की भारी क्षति. यही कारण एपी व तेलंगाना के आंदोलन पर भी लागू होता है. पेरु की क्रांति पूरे केंद्रीय नेतृत्व के गिरफ्तार होने से सेटबैक का सामना कर रही है. यह कड़ुवा अनुभव हमें शिक्षा देता है कि नेतृत्व की सुरक्षा का व अत्मगत ताकतों का सरंक्षण कितना महत्वपुर्ण है. यह एक सैद्धांतिक व राजनीतिक मुद्दा है. इसे रणनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए. यह दुश्मन की एलआइसी नीति को समझने से जुड़ा हुआ है. और यह पार्टी, सेना व संयुक्त मोर्चा की ताकत के निर्माण व उसे शक्तिशाली बनाने, जनाधार को विकसित करने से भी जुड़ा हुआ है.

क्रांति में बलिदान अनिवार्य है. कभी भी क्रांति की अंतिम जीत दुश्मन की शक्ति को ध्वस्त करते हुए खुद की शक्ति को विकसित करते हुए हो सकती है. यही सूत्र दीर्घकालीक जनयुद्ध पर लागू होता है. जब जनता हथियार उठाती है, विद्रोह कर दुश्मन का सफाया करती है, वे क्रुरत्म प्रतिहमला करेंगे. वे क्रांति का खात्मा करने के लिये अत्यंत खूंखार व क्रूर हमले करेंगे. नेतृत्व को हथियारबंद क्रांति की विजय के लिये, प्रतिक्रांति को हराते हुए, अंततः उसे पूरी तरह साफ कर देने के लिये त्यार रहना चाहिए. युद्ध में पार्टी को दुश्मन के हमलों से, वामपंथी, दक्षिणपंथी रुझानों से बचाते हुए विजय की ओर ले जाने में जीत के लिये निर्णायक पहलू है. यह नेतृत्व की जिम्मेदारी है.

इस मुद्दे पर हमारी पार्टी की सामान्य समझदारी ये है कि हमारा नुक्सान उदारतावाद व व्यवहार में ठोस कमियों के कारण हुआ है. पीछले एक दशक के अनुभव से निचोड़ निकलता है. वस्तुगत परिस्थितियां क्रांति के बेहद अनुकूल हैं, फिर भी, इन अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग क्रांति की विजय के लिये करना है तो योजनाबद्ध ढंग से, लगातार संघर्ष में आत्मगत ताकतों का सरंक्षण करना व विकसित करना बेहद जरुरी है. वर्तमान में, जब दुश्मन का हमला बेहद गंभीर है, जब उसकी निगरानी व इनफिल्टरेशन (टोही) तरिके बहुत ही उन्नत हैं, आधुनिक तकनिक से लैस है, हमारे लिये जरुरी हो जाता है कि हम हमारी क्षमताओं को उन्नत करें और गुप्त ढांचे के लिये कार्यनीति सूत्रबद्ध करें और गुप्त तरिकों से हमारी आत्मगत ताकतों का सरंक्षण करें. हमें इन कार्यनीतियों को बहुत दृढ़तापूर्वक लागू करना होगा. इसे ही लागू करते हुए हम कदम व कदम विकसित हो सकेंगे.

हमें हमारे अनुभवों को दिमाक में रखना चाहिए, महान मार्क्सवादी शिक्षकों की शिक्षाओं व अनुभवों को जो बहुत देशों के क्रांतिकारी इतिहास से निकले हैं, उन शिक्षाओं से मार्गदर्शन करना चाहिए, हमारी पार्टी को शक्तिशाली संगठन के रूप में विकसित करते हुए दीर्घकालीक लोकयुद्ध के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए. जनयुद्ध व जनाधार के बीच रिश्ता विकसित करते हुए उस पर उचित पकड़ कायम करनी चाहिए. न केवल वहां जहां आरपीसीस हैं बल्कि अन्य ग्रामीण इलाकों में भी किसानों व खेत मजदूरों को कृषि क्रांति में व्यापक रूप से गोलबंद करना चाहिए और गुरिल्ला युद्ध को आगे की और विकसित करना चाहिए.

इसके साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में विकसित हो रहे नये मध्यम वर्ग को, अन्य उत्पीड़ित तबकों को क्रांतिकारी आंदोलन

> हमें ग्रामीण इलाके के शहरी केंद्रों के सामाजिक मुद्दों पर पकड़ कायम करते हुए, अलग-अलग वर्गों की एकता का निर्माण करते हुए नये तरीकों के साथ जन गोलबंदी पर जोर देना चाहिए.

से जोड़ने में खामियों के चलते गुरल्लि युद्ध के विकसित होने में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. पीछले 10 सालों में आंदोलन शहरी व मैदानी इलाकों में कमजोर हो गया है. इसके साथ-साथ हम गुरिल्ला जोनों के आसपास गैर किसानी व्यापक जनता को उल्लेखनीय स्तर पर गोलबंद नहीं कर पाये. यह दोनों कमजोरियां हमारे केंद्रीय कार्यभार को पूरा करने में बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाली हैं. लेकिन हमें देश के कई हिस्सों में व्यापक जनता को गोलबंद करने का अनुभव भी प्राप्त हुआ है जैसे - नंदीग्राम, लालगढ़, नरायणपटना आंदोलन, पृथक तेलांगाना आंदोलन व अन्य विस्थापन विरोधी आंदोलन. ये हमारे लिये नये अनुभव हैं, जिनसे हमें ध्यान देते हुए सीखना है.

हमें ग्रामीण इलाके के शहरी केंद्रों के सामाजिक मुद्दों पर पकड़ कायम करते हुए, अलग-अलग वर्गों की एकता का निर्माण करते हुए नये तरीकों के साथ जन गोलबंदी पर जोर देना चाहिए. यह सच्चाई है कि 'भारतीय क्रांति की रणनीति-कार्यनीति' दस्तावेज में अन्य-अन्य मैदानी इलाकों में क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करने के लिये व्यापक कार्यनीतिक मार्गदर्शक नियम दिये गए हैं. उनको दिमाक में रखते हुए हमें देश में आ रहे बदलावों पर भी ध्यान देना है. शहरी कामकाज से संबंधित योजना-दस्तावेज (policy document) भी हमारे पास है. लेकिन उसकी परिक्षा तभी अच्छे से हो सकेगी कि हम उसे कैसे व कितनी गहराई से उसकी रणनीतिक महत्ता को समझ कर दोनों एरियाओं में लागू करते हुए कठिन कार्य को संपन्न करेंगे. इसके संबंध में खामियों व विफलताओं के कारण हम काफी आत्मगत ताकतों का नुक्सान झेल चुके हैं, यहां दुश्मन के लिये हमारा दमन करना बहुत आसान होता है. इस तरह की खामियों का महत्वपुर्ण कारण दृढ़ता के साथ सामाजिक जांचपड़ताल व अध्ययन न कर पाना है. मैदानी व शहरी इलाकों में ज्यादातर जनता साम्राज्यवाद, सामंतवाद व दलाल नौकरशाह पूंजीपति के शोषण से पीड़ित है. बहुत सारे आंदोलन मैदानी व शहरी इलाकों में उठ रहे हैं. दोनों ही इलाकों में वैश्विक आर्थिक संकट जनता को कुचल रहा है. जनता सैंकड़ों मुश्बितें उठा रही है. उसके पास क्रांति के बिना कोई विकल्प नहीं है. और हमारे जनयुद्ध का इन इलाकों की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा है.

इन इलाकों की वस्तुगत परिस्थिती क्रांति के बहुत अनुकूल हैं. यहां जनता के विभिन्न तबकों व वर्गों की मांगो पर परिस्थितियों के अनुकूल ठोस व सृजनात्मक रूप से पहुंच बनाने की जरूरत है. पहले से ही इन इलाकों में काम करने का हमारा दशकों का अनुभव है. और पीछले एक दशक की नयी परिस्थितियों में काम करने का अनुभव भी हमें प्राप्त है, जो आगे हमारी मदद करेगा. हमे अब सृजनात्मक कार्य, योजनबद्ध ढंग से करना है. दुश्मन की बदली कार्यनीति व परिस्थितियों के अनुरूप नये तरीके लागू करने हैं. इसके साथ-साथ हमें दीर्घकालीन जनयुद्ध के तहत व्यापक इलाके में गुरिल्ला युद्ध का निर्माण करना होगा. जब दुश्मन गंभीर हमले करते हुए हमें जनता से अलग-थलग कर खत्म करने के लिये आगे आ रहा है तब हमें यह कार्यनीति लागू करते हुए हमारी ताकतों का संरक्षण करना होगा.

हम दुश्मन को ध्वस्त करते हुए ही अपनी अच्छे से आत्मरक्षा कर सकते हैं. फिर भी हमारी ताकतों की आत्मरक्षा व संरक्षण की जरुरी पद्धति अपनाते हुए हमें अपने दीर्घकालीन युद्ध के राजनीतिक, सांगठनिक, सैनिक कार्यभार पूरे करने हैं व जनाधार को बढ़ाना है. दुश्मन की नीति है हमें जनता से अलग-थलग करके खत्म करना. हमारी नीति होनी चाहिए गहराई से जनता में जाना, उनके साथ गहराई से जुड़ जाना व दुश्मन को ध्वस्त कर देना. वर्तमान वस्तुगत परिस्थितियां हमें ये सब करने के अच्छे मौके दे रही हैं. हमें इसका इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक रूप से किसानों व अन्य तबकों की उत्पीड़ित जनता को कई राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आदि मुद्दों पर लामबंद करना चाहिए. इन संघर्षों से जो सक्रीय तत्व आगे आग आएंगे हमें उन्हें सुदृढ करते हुए उनकी राजनैतिक, सैद्धांतिक चेनता को बढ़ाना चाहिए. इस प्रकार हम जरूर हमारे जनाधार व आत्मगत ताकतों को बढ़ा पाएंगे. हमें जरूर राजनैतिक रूप से दुश्मन के अंतरविरोधों का इस्तेमाल करने की पहलकदमी मुख्य दुश्मन को अलग-थलग करने के लिये लेनी चाहिए ओर उसे अंत में उसे खत्म कर देना चाहिए.

कई इलाकों की परिस्थिती के मुताबिक, सरकार जनता से हमें अलग-थलग कर खत्म करने के लिये विकास का भ्रम फैला रही है. हमें दुश्मन की एलआईसी को पराजित करने के लिये, हमारे द्वारा पहले से बनाई गयी नीति व खुद के अनुभवों के आधार पर कार्यनीति कार्यक्रम त्यार करने चाहिए. इसके साथ-साथ पार्टी, पीएलजीए व जन संगठनों को दुश्मन द्वारा जारी निर्दीय मानसिक हमलों को हरा देना चाहिए. हमें व्यापक रूप से मालेमा, व नवजनवादी क्रांति की राजनीति को जनता में प्रचारित करते हुए आंदोलन को सफल करना चाहिए. हमें अपनी तमाम कमियों को हराने के लिये प्रयाप्त रूप से सैद्धांतिक, राजनैतिक अध्ययन, सामाजिक विश्लेषण, अनुभावों का संश्लेषण करते हुए

व गैर सर्वहारा वर्ग रुझानों को दूर करना चाहिए.

लौह अनुशासन, जनवादी केंद्रीयता लागू करने में, गुप्त ढांचे व गुप्त कार्यपद्धति में और नेतृत्व की कार्यपद्धति व शैली में खामियां पार्टी के अंदर विचारों की एकता व कार्रवाई को ध्वस्त कर रही है. उपरी नेतृत्व सहित हमारी आत्मगत ताकतों के भाग जाने में यह एक कारण है..... हमारी पार्टी सैद्धांतिक, राजनीतिक, सैनिक लाईन सही है. यही दीर्घकालीन जनयुद्ध की अंतिम विजय में निर्णायक तत्व है. फिर भी हमारे व्यवहार की गलतियों व कमियों के कारण हमारी मंजिल तक पहुंचने में तात्कालिक रूप से विफलता व कठिनाई सामने आयी है. हमें हमारी राजनैतिक व सैनिक लाईन को मजबूती के साथ पकड़े रहना है. मालेमा की रोशनी में हमारी राजनैतिक, सांगठनिक व सैनिक कामकाज को ठीक करना है. हम फिर विजय पथ पर आगे बढ़ सकते हैं.

हमारी पार्टी ने 1970 को दौरान भी इसी तरह देशव्यापी सेटबैक का दौर झेला है, फिर से कदम व कदम आंदोलन को विकसित किया है. उस समय हम भारतीय क्रांति के दृश्यपटल से ओझल हो गए थे और फिर मजबूती से उभर कर सामने आए. कई देशों की सफल क्रांतियों का ऐसा ही अनुभव है. वे हार कर सही रवैया अपनाईं. वर्तमान परिस्थितियों में हमारी पार्टी का कुंजीभूत कार्य है कि जिन कठिन परिस्थितियों व कमजोरियों का हम सामना कर रहे हैं उनसे निकलने के लिये पार्टी को उस योग्य बनाना, उस रास्ते की तरफ मोड़ना और आंदोलन को आगे बढ़ाना. इसके लिये हमें हमारे पुराने अनुभवों से सबक लेने चाहिए. और हर स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए.

हर स्तर पर हमारे कामरेडों को अपने अनुभवों पर चर्चा करनी चाहिए, अपनी गलतियों मानना चाहिए. उनको सुधारने के लिये कदम उठाने चाहिए. हमें महान मार्क्सवादी शिक्षकों की शिक्षाओं का अध्ययन करना चाहिए. अगर हम केवल सफलताओं को ही देखते रहेंगे, विफलताओं व कठिन परिस्थिती को अनदेखा करते रहेंगे तो अवश्य ही हम पिछली गलतियों को नहीं सुधार पायेंगे व निराशावाद का शिकार हो जायेंगे..... एक और अन्य महत्वपूर्ण काम है पार्टी निर्माण में गुणवत्ता को बढ़ाना. जब नये लोगों को पार्टी सदस्यता दी जाती है, जब उनको पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में विकसित किया जाता है, जब उनको पदोन्नति दी जाती है हमें गुणवत्ता को महत्व देना चाहिए.

अगर हम केवल सफलताओं को ही देखते रहेंगे, विफलताओं व कठिन परिस्थिती को अनदेखा करते रहेंगे तो अवश्य ही हम पिछली गलतियों को नहीं सुधार पायेंगे व निराशावाद का शिकार हो जायेंगे..... एक और अन्य महत्वपूर्ण काम है पार्टी निर्माण में गुणवत्ता को बढ़ाना. जब नये लोगों को पार्टी सदस्यता दी जाती है, जब उनको पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में विकसित किया जाता है, जब उनको पदोन्नति दी जाती है हमें गुणवत्ता को महत्व देना चाहिए.

हमे जनसंगठनों व पीएलजीए में से सक्रिय सदस्यों को पार्टी सदस्यता देनी चाहिए. उनको पार्टी संविधान के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. पार्टी के अंदर नई भर्तीयों से न केवल हमारा विस्तार होता है. ब्लकि युवा खून व नया अनुभव भी साथ में आता है. पार्टी की गुणवत्ता का सुधार करने के लिये मालेमा अध्ययन व प्रशिक्षण को एक अभियान के तौर पर चलाना चाहिए. हमें चाहिए कि हम ठोस परिस्थितियों का अध्ययन करें, उन पर चर्चा करें और उन के अनुरूप सृजनात्मक रूप से हमारी राजनीति व सिद्धांतों को लागू करें. पार्टी निर्माण के सारे प्रयास बोल्शेविकीकरण अभियान से जोड़े जाने चाहिए.

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें सैद्धांतिक, राजनैतिक स्तर उंचा उठाना चाहिए. और पार्टी की सांगठनिक एकता को बढ़ाना चाहिए. इससे व्यापक जनाधार को बढ़ाने की योग्यता, पीएलजीए को दक्षता के साथ नेतृत्व करने की क्षमाता बढ़ाते हुए जनयुद्ध को आगे बढ़ाना चाहिए. वर्तमान अनुकूल परिस्थितियों में आंदोलन को विकसित करने के लिये जरुरी है प्रयाप्त आत्मगत शक्तियां. यहां तक कि जब हमारी ताकतें कमजोर हैं, अगर हम दृढ़ता के साथ सही राजनैतिक व सांगठनिक प्रयास करें, तो अनुकूल वस्तुगत परिस्थितियां हमें अच्छे तरीके से अपनी आत्मगत ताकतों को बढ़ाने का मौका दे रही हैं.

हमारा पूराना अनुभव यही साबित करता है. अगर हम इसे ध्यान में न रखते हुए अदिभौतिकवादी (metaphysical) दृष्टिकोण से सोचेंगे तो निष्क्रिय हो जायेंगे, यह सोचना की हमारी आत्मगत ताकत कमजोर है, तो हम कभी भी इन कठिन परिस्थितियों को तोड़ नहीं पायेंगे. दीर्घकालीन जनयुद्ध का रास्ता हमें सीखाता है कि कैसे एक कमजोर ताकत शक्तिशाली ताकत में बदल जाती है, कि कैसे एक कमजोर आंदोलन शक्तिशाली आंदोलन में विकसित हो जाता है. रुसी क्रांति सफल होने से पहले, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन पर संशोधनवादियों का नियंत्रण था और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक जैसे सच्चे क्रांतिकारी अल्पमत में थे. अक्तुबर क्रांति ने दूसरे इंटरनेशनल के संशोधनवाद को चकनाचुर कर दिया और इसके बाद दुनिया के स्तर पर बड़ी संख्या में क्रांतिकारी व कम्युनिस्ट पार्टियों का उदय हुआ. और जब ख्रुश्चेवी संशोधनवाद

जब आंदोलन कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, पार्टी के अंदर वामपंथी व दक्षिणपंथी अवसरवादी रुझान पार्टी में आने की संभावना ज्यादा रहती है. अगर ऐसे समय में हम सतर्क नहीं रहते और इसके खिलाफ संघर्ष नहीं करते उस समय हम ज्यादा नुक्सान उठायेंगे. अगर हम क्रांतिकारी ताकतों का अंकलन बढ़ा-चढ़ा कर करते हैं. और दुश्मन को छोटा करके देखते हैं. तब हमारी पार्टी वामपंथी गलती से ज्यादा नुक्सान झेल सकती है. और अगर हम दुश्मन की ताकतों का ज्यादा आंकलन करते हैं. हमारी ताकत को कम आंकते हैं. तब फिर पार्टी दक्षिणपंथी गलती से नुक्सान झेल सकती है. आज के दौर में यह मुख्य खतरा है. हमें पार्टी के अंदर वाम व दक्षिण दोनों तरह के रुझानों के खिलाफ सही पार्टी पद्धति के साथ आंतरिक संघर्ष चलाना चाहिए. फिर भी हमें हर मतभेद को बुनियादी और पूरी लाईन के खिलाफ के रूप में नहीं देखना चाहिए न ही अंतहिन बहसों में पड़ना चाहिए. किसी भी विषय को स्पष्ट रूप से संबंधित कमेटी में सही तरीके से हमारे संविधान के अनुसार चर्चा करनी चाहिए. पार्टी के अंदर भिन्न विचारों भिन्न दृष्टिकोण को उठाने का यही सही तरीका है.

के खिलाफ माओ के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ने संघर्ष छेड़ा तब सीपीसी के साथ कुछ ही पार्टियां खड़ी हुई थीं.

लेकिन महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति फिर से नयी पार्टियों व क्रांतियों की शक्तिशाली लहर लेकर आयी. हमारा क्रांतिकारी आंदोलन व फिलिपिन्स का दीर्घकालीन जनयुद्ध उसी लहर का हिस्सा है. फिर एक बार, जब संशोधनवादी देंग के नेतृत्व में चीन की सत्ता पर कब्जा किया, उसके खिलाफ कुछ ही पार्टियां खड़ी हुई थीं. लेकिन संघर्ष ने फिर पेरु व नेपाली क्रांति को जन्म दिया. हालांकि वे भी नव संशोधनवाद के कारण सेटबैक का शिकार हुई. लेकिन सबक अभी बचा है. क्रांति के निर्माण में पूरी शक्ति के साथ अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग करते हुए साम्राज्यवाद व उसके प्रतिक्रियावादी हथियार संशोधनवाद को हराना पड़ेगा.

मालेमा पर दृढ़ता के साथ खड़े रहते हुए, सर्वहारा के सिद्धांत से और क्रांतिकारी पथ पर डटे रहकर चुनौतियों का सामना करते हुए विजय प्राप्त की जा सकती है. 2008 से साम्राज्यवादी व्यवस्था का विश्वव्यापी संकट जारी है. यह उत्पीड़ित देशों व साम्राज्यवाद दोनों के लिये संदेश है कि एक बार फिर संघर्षों का समय आ रहा है. दीर्घकालिन लोकयुद्ध जारी है. हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध को पूरी दुनिया में व्यापक समर्थन मिल रहा है. प्रचंड-भट्टाराई गुट के विश्वासघात व अवकाइनिज्म के (liquidation-ism) परिसमापनवाद से लड़ते हुए माओवादी ताकतों की एकता बढ़ रही है. दुनिया की वस्तुगत परिस्थितियां क्रांतिकारी लहर के लिये शक्तिशाली व बहुत प्रबल दिखाई दे रही हैं. लेकिन यह भी दिख रहा है कि हमारी आत्मगत ताकतें गंभीर रूप से वस्तुगत परिस्थितियों से पीछे हैं. लेकिन यहां एक अंतरविरोध दिखता है कि वस्तुगत परिस्थितियों की प्रबलता व माओवादी ताकतों की आत्मगत क्षमता में बड़ा अंतर है.

दुनिया की क्रांतियों का इतिहास हमें सीखाता है कि विजय की और बढ़ने का एक ही रास्ता है हिलाकर रख देने वाली (waging) क्रांति. इस के लिये हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है. पार्टी के अंदर कई तरह के विचारों का संघर्ष, समाज में जारी वर्ग संघर्ष का प्रतिबिम्ब है. हमेशा और खासकर तब हमें दिमाक में रखना चाहिए, जब आंदोलन कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, पार्टी के अंदर वामपंथी व दक्षिणपंथी अवसरवादी रुझान पार्टी में आने की संभावना ज्यादा रहती है. अगर ऐसे समय में हम सतर्क नहीं रहते और इसके खिलाफ संघर्ष नहीं करते उस समय हम ज्यादा नुक्सान उठायेंगे. अगर हम क्रांतिकारी ताकतों का अंकलन बढ़ा-चढ़ा कर करते हैं. और दुश्मन को छोटा करके देखते हैं. तब हमारी पार्टी वामपंथी गलती से ज्यादा नुक्सान झेल सकती है. और अगर हम दुश्मन की ताकतों का ज्यादा आंकलन करते हैं. हमारी ताकत को कम आंकते हैं. तब फिर पार्टी दक्षिणपंथी गलती से नुक्सान झेल सकती है. आज के दौर में यह मुख्य खतरा है. हमें पार्टी के अंदर वाम व दक्षिण दोनों तरह के रुझानों के खिलाफ सही पार्टी पद्धति के साथ आंतरिक संघर्ष चलाना चाहिए. फिर भी हमें हर मतभेद को बुनियादी और पूरी लाईन के खिलाफ के रूप में नहीं देखना चाहिए न ही अंतहिन बहसों में पड़ना चाहिए. किसी भी विषय को स्पष्ट रूप से संबंधित कमेटी में सही तरीके से हमारे संविधान के अनुसार चर्चा करनी चाहिए. पार्टी के अंदर भिन्न विचारों भिन्न दृष्टिकोण को उठाने का यही सही तरीका है. कुछ लोग दीर्घकालीन लोकयुद्ध के श्रमसाध्य पथ पर चलने को तैयार नहीं है और आत्मबलिदान की भावना भी खो चुके हैं. वे सोचते हैं हमेशा दुश्मन की ताकत ज्यादा रहेगी और जनता की ताकत कम रहेगी.

वे दुश्मन के साथ हाथ मिलाने के लिये दिवालिये तर्क पेश कर रहे हैं. हमें ऐसे विश्वासघातियों के खिलाफ शक्तिशाली तरीके से लड़ना चाहिए. हाल ही में, हमारे देश में फिर एक बार कुछ व्यक्ति दृष्टिकोण

लाये हैं कि भारत के अर्धसामंति संबंध पूंजीवादी संबंधों में बदल गए हैं और भारत के समाज में दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाईन हमारे देश में फिट नहीं बैठती. कुछ लोग इनमें से अस्पष्ट रूप से बगावत की लाईन पर तर्क करते हैं. भारत की कम्युनिस्ट लीग (सीएलआई) 30 साल पूरानी समझदारी से अपनी लाईन पर जमी हुई है. वह अच्छी तरह से जानती है कि उसके सालों के व्यवहार में उसे छोटी सी सफलता भी नहीं मिली है. हमे सिरे से इस रुझान को खारिज कर देना चाहिए. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद उत्पीड़ित देशों अमेरिकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व उसके व उसके नौकरों के अंदर नव-उपनिवेश किस्म के बहुत सारे बदलाव दिखते हैं.

इसके बावजूद, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या वाले देश में मुक्ति संघर्ष व नयी जनवादी क्रांतियां दीर्घपथ व दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन अपना रहे हैं. कुछ देशों में दीर्घकालिक लोकयुद्ध के रास्ते पर क्रांतियां जारी हैं. यह इसलिये संभव हुआ क्योंकि वहां बुनियादी रूप से समाज का अर्ध सामंति व अर्ध औपनिवेशिक स्वभाव और बुनियादी अंतरविरोध मौजूद हैं. इसी कारण से दशकों से हमारे देश में भी नवजनवादी क्रांति जारी है. इन्हीं सामाजिक संबंधों से जनता जुड़ रही है और क्रांति का निर्माण कर रही है. 1947 के बाद हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य पहलूओं में उल्लेखनिय बदलाव भी आये हैं.

फिर भी उनसे समाज के स्वभाव में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया है. इस ऐतिहासिक सच्चाई को हमारे देश की नवजनवादी क्रांति का इतिहास बखूबी साबित करता है. इसलिये उनके गलत दृष्टिकोण का अस्विकार कर देना चाहिए. और उनके द्वारा लाये जा रहे तर्कों का पर्दाफाश करना चाहिए. सभी देशों व समाजों में जहां वर्ग अंतरविरोध व वर्ग संघर्ष लगातार तीखा है वहां लगातार बदलाव भी नजर आते हैं. हमारे देश में भी, न केवल आर्थिक,राजनीतिक, व सांस्कृतिक पहलू ब्लकि परिवहन, संचार, मिडिया, तकनिक, युद्ध कला, धरातल (topography), शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या अनुपात, प्रशासन व न्यायिक व्यवस्था आदि में काफी बदलाव आये हैं जिनका जनयुद्ध पर काफी प्रभाव पड़ता है. एलपीजी के समय में, भी हमारे देश में असामान विकास हुआ है. और तो और पहले भी ऐसा था. हमें अपनी राजनीतिक व सैनिक लाईन पर मजबूती से डटे रहना चाहिए. और गहराई से बदलाओं का अध्ययन करना चाहिए. उनको हमारी रणनीति और कार्यनीति के बीच द्वंद्वात्मक संबंधों के नजरिए से देखना चाहिए.

ये बदलाव हमारी रणनीति के कुछ पहलूओं पर प्रभाव डालते हैं. वह ये कि हमें हमारी रणनीति को सृजनात्मक रूप से लागू करते हुए हमारी कार्यनीति का विकास करना चाहिए. हमें चाहिए कि हम उन नारों, संघर्षों व सांगठनिक तरीकों में जरुरी बदलाव लायें जो व्यापक जनता को जनयुद्ध में नहीं जोड़ पा रहे हैं.

यह पहले भी जरुरी था. और आज तो और भी जरूरी है जब बदलाव बहुत जल्दी-जल्दी आ रहे हैं. जब वर्ग संघर्ष लगातार प्रचंड रूप से जारी हो, परिस्थितियों का अध्ययन व जांचपड़ताल करके उनके अनुरूप कार्यनीति बनाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. इसलिये हमारे देश में हमें इस संबंध में आ रहे बदलावों का एक अलग नजरिए से भी अध्ययन करना चाहिए. हमारे देश के कई पहलूओं में अभूतपूर्व रूप से नव उपनिवेशवादी शोषण-उत्पीड़न व साम्राज्यवादी नियंत्रण में आये कई बदलाओं को समझने के लिये यह अनिवार्य हो जाता है.

यह हमारी कार्यनीति को तय करने के नजरिए से बेहद जरूरी है. हमारे दस्तावेज - भारतीय क्रांति की रणनीति और कार्यनीति में हमारे देश व दुनिया की परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से अध्ययन किया गया है. मालेमा की रोशनी में जांचपड़ताल व विश्लेषण किया गया है. पार्टी को इसके आधार पर शिक्षित करना चाहिए. सक्रीय व व्यापक रूप से जनता को गोलबंद करते हुए संघर्ष, संघर्ष के रुपों व संगठन के रुपों का विकास करना अत्यंत जरूरी है. अगर लागू की जा रही कोई कार्यनीति लंबे समय तक परिस्थितियों के अनुरूप फिट न बैठती हो तो जरूर आंदोलन नष्ट हो जाता है.

जब बदलाव बहुत जल्दी-जल्दी आ रहे हैं. जब वर्ग संघर्ष लगातार प्रचंड रूप से जारी हो, परिस्थितियों का अध्ययन व जांचपड़ताल करके उनके अनुरूप कार्यनीति बनाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. इसलिये हमारे देश में हमें इस संबंध में आ रहे बदलावों का एक अलग नजरिए से भी अध्ययन करना चाहिए. हमारे देश के कई पहलूओं में अभूतपूर्व रूप से नव उपनिवेशवादी शोषण-उत्पीड़न व साम्राज्यवादी नियंत्रण में आये कई बदलाओं को समझने के लिये यह अनिवार्य हो जाता है. यह हमारी कार्यनीति को तय करने के नजरिए से बेहद जरूरी है. हमारे दस्तावेज - भारतीय क्रांति की रणनीति और कार्यनीति में हमारे देश व दुनिया की परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से अध्ययन किया गया है. मालेमा की रोशनी में जांचपड़ताल व विश्लेषण किया गया है. पार्टी को इसके आधार पर शिक्षित करना चाहिए. सक्रीय व व्यापक रूप से जनता को गोलबंद करते हुए संघर्ष, संघर्ष के रुपों व संगठन के रुपों का विकास करना अत्यंत जरूरी है. अगर लागू की जा रही कोई कार्यनीति लंबे समय तक परिस्थितियों के अनुरूप फिट न बैठती हो तो जरूर आंदोलन नष्ट हो जाता है.

हम पहले से ही आंध्रा के आंदोलन की ऐसी समीक्षा एक गलती के रूप में कर

हमें ध्यान देकर ऐसे मुद्दों में हस्तक्षेप करते हुए जनता को संघर्षों में गोलबंद करना चाहिए. इससे हम मौजूद परिस्थितियों से बहार आ पागयेंगे, हमें हमारी आत्मगत ताकतों को बचाना चाहिए, उनको सुदृढ़ करना चाहिए, जन आधार को मजबूत करते हुए दीर्घकालीन जनयुद्ध को तेज करते हुए शक्तिशाली बनाना चाहिए. मोदी सरकार के बाद आयी परिस्थितियों को उपयोग करते हुए इस दिशा में जाना है. इस में कोई संदेह नहीं है कि हमारे सामने चुनौतियां गंभीर हैं लेकिन सच यह भी है कि अवसर भी ज्यादा पैदा हुए हैं. हमें चाहिए कि हम सहास के साथ गहराई व व्यापकता के साथ विभिन्न वर्गों व तबकों की जनता में जायें, राजनीतिक रूप से उनको संघर्षों में गोलबंद करें. हमें चाहिए कि हम मोदी सरकार की हर जनविरोधी, देश विरोधी नीतियों व कदमों पर प्रतिक्रिया दें, उसका तुरंत पर्दाफाश करें, उसके खिलाफ जनता को संघर्षों में लामबंद करें, और उनको दीर्घकालीन जनयुद्ध के साथ जोड़ दें. हम सब को बहार निकल कर इन मौकों को पकड़ लेना चाहिए.

चुके हैं. हम ऐसी कुछ गलतियों को पीछले दशक में भी समझ चुके हैं. जहां पार्टी मजबूत है वहां पहल अपने हाथ में रखनी चाहिए, जहां कमजोर है वहां पुनः ताकत प्राप्त करनी चाहिए. और गलतियों को सुधारते हुए आंदोलन का विकास करना चाहिए. मालेमा के सैद्धांतिक हथियार को मजबूती के साथ पकड़े हुए, सृजनात्मक रूप से राजनीतिक, सैनिक लाईन को लागू कर विकसित करते हुए, राजनीतिक, सांगठनिक और सैनिक संघर्ष में प्रयास करते हुए अपनी कमजोरियों पर पार पा सकते हैं. ऐसे ही हम सही व्यवहार से एक बार फिर हमारे कारे कार्य क्षेत्र में अनुकूल वस्तुगत परिस्थितियों को पुनः प्राप्त कर, सामना कर रही परिस्थितियों से निकल कर नवजनवादी क्रांति में विजय हासिल कर सकते हैं.

हमने चुनाव बाद की परिस्थिति का अकलन करने हुए, सीसी ने चिन्हित किया है कि आरएसएस प्रभाव वाली एनडीए सरकार के आने के बाद ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवाद का खतरा बढ़ गया है. इसके खिलाफ सभी क्रांतिकारी, जनवादी संगठनों, ताकतों, व व्यक्तियों सहित तमाम जनता को एकजूट कर, व्यापक आधार पर शक्तिशाली आंदोलन खड़ा करना अति आवश्यक और महत्वपुर्ण कार्यभार है. धार्मिक अल्पसंख्यकों व दलितों पर हमले व उत्पीड़न बढ़ेगा. इनके निशाने पर प्रगतिशील बुद्धीजीवि और आंदोलन भी आएंगे. जैसे जैसे हिंदू फासीवाद बढ़ेगा व सत्ता मोदी के हाथों में सिमटती रहेगी तब शासक वर्गों के बीच के अंतरविरोध भी तीखे होते जायेंगे.

हिंदी, हिंदू, हिंदूस्तान का छुपा हुआ एजेंडा जैसे-जैसे लागू होगा वैसे वैसे राष्ट्रवादियों की तरफ से विरोध सामने आयेगा. ये सब परिस्थितियां व्यापक ताकतों को संघर्ष में लाने के लिये हमें नये व विभिन्न प्रकार के मौके मुहैया करवाएंगी. मोदी सरकार एलपीजी एजेंडे को आक्रामक रूप से लागू करेगी, जिस से हमारे देश पर नव उपनिवेशवादी शिकंजा कस जाएगा. राष्ट्रवाद के झूठे जूमलों से इसे ढका जाएगा. संघ परिवार राष्ट्रवाद का दिखावा कर रहा है. जबकि तथ्य यह है कि मोदी देश को थोक के भाव में बेच रहा है. मोदी के सच्चे साम्राज्यवाद व सामंतवाद परस्त स्वभाव के खिलाफ व्यापक व ठोस प्रचार चलाकर उसे नंगा कर देना चाहिए.

आपरेशन ग्रीनहंट का नया चरण शुरु हो चुका है. मोदी सरकार राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों व जन आंदोलन के खिलाफ भी कदम उठाना शुरु कर दी है. जनता पर यह हमला काले कानूनों के साथ, साधारण कानूनों तक का उल्लंघन करके, राजनीतिक कैदियों को उत्पीड़ित करके और किसी भी मुद्दे के उठाने वाले कार्यकर्ताओं पर भी किया जा रहा है. हमें ऐसे मुद्दों में उत्साह के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए. यह सब व्यापक व शक्तिशाली मानव व नागरिक अधिकार आंदोलन खड़ा करने के लिये अवसर प्रदान करता है. हमें इसे राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिये और आपरेशन ग्रीनहंट के खिलाफ गतिविधियां से जोड़ना चाहिए.

मोदी सरकार का आक्रमक विकास का एजेंडा अभूतपूर्व रूप से विस्थापन लेकर आयेगा. बड़े पैमाने पर आदिवासी जनता इससे गंभीर रूप से प्रभावित होगी. हमें इसमें सक्रीय व प्रत्यक्ष रूप से सही व पद्धति के साथ उनके बीच जाना चाहिए या समर्थक की भूमिका निभानी चाहिए. हमे यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे हम बड़े जन आंदोनल खड़ा कर सकते हैं. मोदी सरकार की अक्रमाक नव उदारवादी नीतियां किसानों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों सहित महिला, छात्र-नौजवान आदि तबकों को बुरी तरह से प्रभावित करेंगी.

हमें ध्यान देकर ऐसे मुद्दों में हस्तक्षेप करते हुए जनता को संघर्षों में गोलबंद करना चाहिए. इससे हम मौजूद परिस्थितियों से बहार आ पागयेंगे, हमें हमारी आत्मगत ताकतों को बचाना चाहिए, उनको सुदृढ़ करना चाहिए, जन आधार को मजबूत करते हुए दीर्घकालीन जनयुद्ध को तेज करते हुए शक्तिशाली बनाना चाहिए. मोदी सरकार के बाद आयी परिस्थितियों को उपयोग करते हुए इस दिशा में जाना है. इस में कोई संदेह नहीं है कि हमारे सामने चुनौतियां गंभीर हैं लेकिन सच यह भी है कि अवसर भी ज्यादा पैदा हुए हैं. हमें चाहिए कि हम सहास के साथ गहराई व व्यापकता के साथ विभिन्न वर्गों व तबकों की जनता में जायें, राजनीतिक रूप से उनको संघर्षों में गोलबंद करें. हमें चाहिए कि हम मोदी सरकार की हर जनविरोधी, देश विरोधी नीतियों व कदमों पर प्रतिक्रिया दें, उसका तुरंत पर्दाफाश करें, उसके खिलाफ जनता को संघर्षों में लामबंद करें, और उनको दीर्घकालीन जनयुद्ध के साथ जोड़ दें. हम सब को बहार निकल कर इन मौकों को पकड़ लेना चाहिए.

*समाप्त*

# सिध्दांत

**संक्षप्ति नोट्स**

**- स्तालिन**

कामरेड स्तालीन ने अपनी पुस्तक में सिध्दांत के विषय पर तीन प्रश्नों के रुप में चर्चा की है -

१. सर्वहारा आंदोलन के लिए सिध्दांत का महत्व क्या है ?

२. स्वत:स्फूर्तता के 'सिध्दांत' की आलोचना,

३. सर्वहारा क्रांति का सिध्दांत क्या है ?

## *सर्वहारा आंदोलन के लिए सिध्दांत का महत्व*

सभी देशों के मजदूर आंदोलनों का अनुभव ही सामान्य रुप से सिध्दांत कहलाता है. अगर क्रांतिकारी व्यवहार को सिध्दांत की रोशनी न मिले तो वह अंधेरे में भटकता फिरेगा. अगर सिध्दांत का निर्माण क्रांतिकारी आंदोलन के अनुभव से हुआ हो तो वह मजदूर आंदोलन के लिए एक प्रचंड शक्ति बन सकता है. केवल सिध्दांत और एकमात्र सिध्दांत ही वह चीज है जो आंदोलन की क्षमता के संबंध में हमारे अंदर विश्वास भर सकता है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल नीति अपनाने और चारों ओर की घटनाओं के आपसी संबंधों को समझने की शक्ति दे सकता है. सिध्दांत हमें बताता है कि कौन सा वर्ग आज किस तरह और किस तरफ आगे बढ़ रहा है और भविष्य में किस मार्ग पर उसका विकास होगा. लेनिन के शब्दों में ''**क्रांतिकारी सिध्दांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन असंभव है.**'' और ''हिरावल की भूमिका वही पार्टी पूरी कर सकती है जिसके मार्गदर्शन के लिए अत्यंत उन्नत सिध्दांत हों.'' यह लेनिन ने उस समय कहा था तब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थति जटील थी और बोल्शेविक पार्टी पर अतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के आंदोलन का नेतृत्व करने का भार आ पड़ा था.

## *स्वत:स्फूर्तता के 'सिध्दांत' की आलोचना या आंदोलन में अगवा दस्ते की भूमिका*

रुस में और दूसरे इंटरनेशनल में भी कई पार्टियां थीं जिनका मानना था कि आराम से बैठे रहो, जब 'परिस्थतियां' आएंगी अपने आप यानि स्वत:स्फूर्त ही सब ठीक हो जायेगा. अपने आप पार्टी की, आंदोलन की ताकत बढ़ जायेगी. यह सिध्दांत स्वत:स्फूर्तता की पूजा करने का सिध्दांत है. जो अवसरवाद के सिवाए कुछ नहीं है. यह सिध्दांत मजदूर वर्ग की पार्टी द्वारा आंदोलन का नेतृत्व करने की जरुरत को नकारता है.

स्वत:स्फूर्तता का सिध्दांत मजदूर आंदोलन के क्रांतिकारी स्वरुप का विरोधी है, यह मजदूर आंदोलन द्वारा पूंजीवाद के प्रधान स्तंभों पर प्रहार करने की नीति का विरोधी है. यह सिध्दांत इस बात को भी नकारता है कि स्वत:स्फूर्त उठे आंदोलनों को राजनीतिक रुप से संगठित करना चाहिए. और मजदूर वर्ग की पार्टी को उन आंदोलनों का नेतृत्व करना चाहिए. यह सिध्दांत चाहता है कि स्वत:स्फूर्त उठे आंदोलनों में पार्टी दखल न दे बल्कि उन आंदोलनों की पिछलग्गू बन जाये. पिछलग्गूपन ही अवसरवाद का आधार होता है.

मार्क्स ने कहा था - भौतिकवादी सिध्दांत को केवल संसार की व्याख्या करने तक सिमित नहीं करना चाहिए, उसे संसार को बदलने का काम हाथ में लेना चाहिए. लेकिन स्वत:स्फूर्तता के पुजारी या अवसरवादी लोग केवल परिस्थतियों का ही इंतजार करते रहते हैं.

इस 'सिध्दांत' का विरोध किये बिना कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती.

## *सर्वहारा क्रांति का सिध्दांत*

सर्वहारा क्रांति का लेनिनवादी सिध्दांत तीन मौलिक सिध्दांतों के आधार पर स्थापित किया गया. इसमें कामरेड स्तालिन ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि यानि सर्वहारा क्रांति कैसे सफल हो सकती है और क्यों सफल हो सकती है.

**पहला सिध्दांत -** उन्नत पूंजीवादी देशों में बैंकिंग पूंजी (वित्तीय पूंजी) का राज होता है. यह कारोबार मुख्य रुप से

शेयरों व बांडस की खरीद-बिक्री के जरिये चलता है. जहां कच्चा माल मिलता है वहां पर पूंजी का निर्यात किया जाता है और पूंजी का यह निर्यात साम्राज्यवाद का एक आधार-स्तंभ बन जाता है. (जैसे भारत के शेयर बाजार में अमेरिकी साम्राज्यवाद व अन्य साम्राज्यवादी देश पूंजी लगाते हैं, विदेशी कंपनियां आकर भारत में पूंजी लगाकर कारखाने लगाती हैं. आदि पूंजी का निर्यात कहलाता है, सं.) बैंकिंग या कहें वित्तीय पूंजी के प्रभुत्व के कारण उस पूंजी के थोड़े से मालिकों की शक्ति सर्वव्यापी (वैश्वीक) बन जाती है. इन सभी लक्षणों के कारण एकाधिकार पूंजीवाद का भयंकर शोषक रुप प्रकट होता है. ... पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ मजदूर वर्ग का विद्रोह तेज हो उठता है. अन्य जनता भी सर्वहारा क्रांति को ही अपनी मुक्ति का एकमात्र मार्ग समझ कर उस क्रांति में शामिल हो जाती है.

**पहला निष्कर्ष - पूंजीवादी देशों के अंदर क्रांतिकारी संकट गहरा हो जाता है. जिससे 'मेट्रोपोलिज' (साम्राज्यवादी देशों) के अंदर सर्वहारा क्रांति के रुप में विस्फोट के तत्व मौजूद होते हैं.**

**दूसरा सिध्दांत -** उपनिवेशों यानि गुलाम देशों में पूंजी का निर्यात बढ़ जाता है. पूरी दुनिया में उपनिवेशों का विस्तार हो जाता है. (साम्राज्यवाद सभी देशों को गुलाम बना लेते हैं. स. ) ...उन्नत देश संसार की अधिकांश जनता को आर्थिक गुलामी और औपनिवेशिक शोषण की बेड़ियों में जकड़ देते हैं. इसके कारण अलग-अलग देशों की अर्थनीतियां और भूमि विश्वव्यापी अर्थनीति का हिस्सा बन जाती है. संसार की जनता दो शिविरों में बंट जाती है. एक तरफ मुट्ठीभर साम्राज्यवादी देश होते हैं. जो गुलाम देशों, उपनिवेशों का शोषण करते हैं. दूसरी तरफ अधिकांश औपनिवेशिक और गुलाम देश होते हैं जो साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाने और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ने पर मजबूर हो जाते हैं.

**दूसरा निष्कर्ष - औपनिवेशिक देशों में क्रांतिकारी संकट बहुत गहरा जाता है और साम्राज्यवाद के बाहरी मतलब औपनिवेशिक मोर्च पर उसके खिलाफ विद्रोह के तत्व मौजूद होते हैं.**

**तीसरा सिध्दांत -** साम्राज्यवादी देश अलग-अलग देशों को उपनिवेश या गुलाम बना लेते हैं. कुछ पहले साम्राज्यवादी देश बनते हैं, कुछ बाद में बनते हैं. जो बाद में बनते हैं वह अपना प्रभाव और बढ़ाना चाहते हैं जबकि पहले वाले साम्राज्यवादी देश अपना प्रभाव कम करना नहीं चाहते. यानि दुनिया को लूटने के लिए बांटने के लिए पूंजीवादी देशों में आपसी टकराव होता है. दूसरे देशों पर कब्जा जमाये बैठे पूंजीवादी देशों और 'अपना हिस्सा' मांगने वाले नए पूंजीवादी देशों के बीच युध्द होते हैं. इससे साम्राज्यवादी देश कमजोर हो जाते हैं. इस से क्रांति अनुकूल स्थिति बनती है - खुद साम्राज्यवादी देशों के अंदर चलने वाले क्रांतिकारी आंदोलन व साम्राज्यवाद के उपनिवेश-गुलाम देश में चलने वाले क्रांतिकारी आंदोलन एक ही संयुक्त मोर्चे में आ जाते हैं.

**तीसरा निष्कर्ष - साम्राज्यवादी व्यवस्था में युध्दों को नहीं रोका जा सकता. साम्राज्यवाद का मतलब ही होता है युध्द. यह युध्द साम्राज्यवादी देशों व उपनिवेशिक देशों के क्रांतिकारी आंदोलनों के बीच संयुक्त मोर्चे के लिए अवसर प्रदान करता है.**

इन तीनो का निष्कर्ष लेनिन के शब्दों में - ''साम्राज्यवाद सामाजवादी क्रांति का आरंभ काल है.''

## *इस विश्लेषण के बाद क्या फर्क आया?*

लेनिन द्वारा साम्राज्यवाद के इस महत्वपूर्ण विश्लेषण के बाद सर्वहारा क्रांति, उसके स्वरुप, उसके लिए अवसर, उसकी गहराई और योजना आदि के संबंध में हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है - कैसे ?

मजदूर क्रांति की अवस्थाओं का विश्लेषण अब केवल अपने ही देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर नहीं किया जा सकता. क्योंकि अब सभी अर्थव्यवस्थाएं साम्राज्यवादी विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का ही अंग है. मुट्ठीभर साम्राज्यवादी देश ज्यादातर जनता को आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ देते हैं, उनका शोषण करते हैं.

पहले किसी देश में सर्वहारा क्रांति की सफलता के लिए दूसरे देश की मदद (बाहरी परिस्थितियों) जरुरी समझी जाती थी. लेकिन अब यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है. अब हमें साम्राज्यवाद को एक विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था मानकर उसके अंदर ही बाहरी परिस्थितियों के अनुकूल होने न होने की बात करनी चाहिए. इस व्यवस्था में कुछ ऐसे देश भी हो सकते हैं जहां औद्योगिक विकास पूरा न हुआ हो लेकिन क्रांति के लिए परिस्थितियां तैयार हो गयी हों. अब देशों का पिछड़ा या कम विकसित होना क्रांति में कोई बाधा नहीं है, जैसे पहले समझा जाता था.

पहले तो यह भी समझा जाता था कि अपने-अपने देश की क्रांतियां अलग-अलग हैं. अब हमें **विश्वव्यापी सर्वहारा क्रांति** की बातें करनी चाहिएं. सभी देशों की क्रांतियां विश्व सर्वहारा क्रांति का ही अंग हैं. क्योंकि सभी देशों के शासक वर्ग साम्राज्यवाद के निचे एकजुट हो गए हैं. एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनके खिलाफ प्रतिरोध भी क्रांतिकारी आंदोलनों के एक संयुक्त मोर्चे के जरिये ही किया जाना चाहिए.

पहले यह भी समझा जाता था कि क्रांति की शुरुआत वहां होगी जहां पर औद्योगिक धंधे, कारखाने आदि ज्यादा हैं, जहां मजदूर वर्ग बहुमत में होगा. जहां की संस्कृति विकसित होगी और जहां पर ज्यादा जनवाद होगा. लेकिन लेनिन ने कहा कि यह जरुरी नहीं है. पूंजी का मोर्चा वहां टूटेगा (क्रांति की शुरुआत) जहां साम्राज्यवाद की जंजीर सबसे ज्यादा कमाजोर होगा. हो सकता है पीछड़े देश में क्रांति सफल हो जाये और विकसित देश पूंजीवाद की चौखट में कैद रह जाये.

१९१७ में रुस से ज्यादा विकसित देश बहुत थे, लेकिन रुस में ही क्राांति इस लिए सफल हुई क्योंकि साम्राज्यवाद की जंजीर वहीं सबसे ज्यादा कमजोर थीं.

इसलिए सर्वहारा क्रांति की रणनीति-कार्यनीति बनाते वक्त देश की जनसंख्या में मजदूर कितने हैं, किसान कितने हैं आदि आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं होते. जरुरी नहीं है कि मजदूर बहुमत में होंगे वहीं क्रांति सफल होगी.

## *क्या पूंजीवादी जनवादी क्रांति और सर्वहारा क्रांति के बीच लंबा समय लगेगा.*

दूसरे इंटरनेशनल के नेता और रुस में मेन्शेविक[२] यह प्रचार करते थे कि पूंजीवादी जनवादी क्रांति के बाद सर्वहारा क्रांति होने में कई दशक लग जायेंगे. लेकिन यह सिध्दांत गलत है. हम यह नहीं मान सकते. क्योंकि आज साम्राज्यवाद दुनिया के सभी प्रतिक्रियावादियों के साथ गठबंधन कायम कर रहा है. चाहे वह जारशाही[३] हो या सामंतवादी. इसलिए किसी भी देश में पूंजीवादी जनवादी क्रांति अब सर्वहारा क्रांति का हिस्सा होगी. आगे जाके पूंजीवादी जनवादी क्रांति अवश्य ही समाजवादी क्रांति में बदल जायेगी.

लेनिन ने लिखा है -

''किसान जनसमूह का सहयोग प्राप्त करके सर्वहारा वर्ग को जनवादी क्रांति को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए. (इस से प्रतिक्रांतिकारी ताकतों का दमन करना होता है. सं.) जनता में से अर्ध्दसर्वहारा स्तर के लोगों का सहयोग प्राप्त करके सर्वहारा वर्ग को समाजवादी क्रांति को पूरा करना चाहिए.

कितना समय लगेगा लेनिन ने स्पष्ट किया है एक जगह - ''घटनाओं ने वही रुप धारण किया है जो हमने कहा था. क्रांति की गति ने हमारे तर्कों की सच्चाई को प्रमाणित कर दिया है. पहले तो, राजतंत्र के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, मध्यकालीन शासन व्यवस्था के खिलाफ 'सारा' किसान वर्ग उठ खड़ा हुआ. इस प्रकार क्रांति का स्वरुप भी पूंजीवादी, बुर्जुआ-जनवादी ही रहा. दूसरा, पूंजीवाद के खिलाफ देहाती धनिकों, धनी किसानों और मुनाफाखोरों के भी खिलाफ गरीब किसान, अर्ध सर्वहारा और सभी तरह के शोषित लोग उठ खड़े हुए और इस प्रकार क्रांति का स्वरुप समाजवादी हो गया. क्रांति की इन दो अवस्थाओं के बीच किसी तरह की बनावटी दीवार खड़ी करना बिल्कुल गलत है. **मजदूर वर्ग क्रांति के लिए किस हद तक तैयार है और गरीब किसानों के साथ उसकी एकता कहां तक बढ़ी हुई है, इन्हीं दो बातों पर क्रांति की इन दो अवस्थाओं का अंतर निर्भर करता है.** इस अंतर को जो आदमी इससे बड़ा करके दिखलाता है, वह मार्क्सवाद को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है. ..... वह मार्क्सवाद के स्थान पर उदारवादी पूंजीवाद की स्थापना करने की कोशिश करता है.'' लेनिन

लेनिन का विचार था कि किसान वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता का 'पूरी तरह' उपयोग करके जारशाही का समूल नाश कर दिया जाये और पूंजीवादी क्रांति को सर्वहारा क्रांति में बदल दिया जाये. मेन्शेविक रुसी क्रांति में किसान वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं समझ पाये थे. वे किसान समूह की क्रांतिकारी शक्ति और क्षमता को कम करके आंकते थे.

## *क्या एक देश में क्रांति सफल हो सकती है?*

पहले ये मानकर चलते थे कि क्रांति पूरी दुनिया में एक साथ ही सफल होगी, एक देश में सफल नहीं होगी. लेकिन अब यह सिध्दांत सही नहीं रहा है. साम्राज्यवाद की अवस्था में पूंजीवादी देशों का विकास असमान है. उनके बीच इतने भयंकर अंतरविरोध पैदा हो गए हैं जिसका नतीजा युध्द ही होता है. संसार के सभी देशों में क्रांतिकारी आंदोलन भी विकसित हो चुके हैं. इन कारणों से अलग-अलग देशों में भी क्रांति सफल होने की परिस्थितियां तैयार हो गयी हैं.

एक देश में क्रांति तो सफल हो सकती है. लेकिन उसे समाजवाद की अंतिम विजय या पूरी विजय नहीं माना जा सकता. क्योंकि दूसरे पूंजीवादी देशों द्वारा उसके ऊपर हमला करने, पूंजीवाद को दोबारा स्थापित करने का खतरा मंडराता रहता है. इसलिए इस खतरे को दूर करने के लिए कई देशों में क्रांति सफल होने से उसको मदद मिलती है. इस प्रकार तुरंत ऐसे देश को जिसमें क्रांति सफल हो जाये दूसरे देशों के क्रांतिकारी आंदोलनों की मदद करनी चाहिए. विश्व सर्वहारा क्रांति की सफलता के लिए एक साधन के तौर पर किसी भी देश की क्रांति को समझना चाहिए.

समाप्त

# साम्प्रदायिक दंगे और उनका इलाज

**भगत सिंह (1928)**

**1919 के जालियँवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटश सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों का खूब प्रचार शुरु किया। इसके असर से 1924 में कोहाट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना में सामप्रदियक दंगों पर लंबी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की जरूरत तो सबने महसूस की, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू-मुस्लमान नेताओं में सुलहनामा लिखाकर दंगों को रोकने के यतन किए।**

**इस समस्या के निश्चित हल के लिए क्रांतिकारी आंदोलन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। यह लेख जून, 1928 के 'किरती' में छपा। यह लेख इस समस्या पर शहीद भगतसिंह और उनके साथियों के विचारों का सार है।**

भारत की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायी के जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का शत्रू होना है। यदि इस बात का अभी यकिन न हो तो लाहौर के ताजा दंगे ही देख लो। किस प्रकार मुसलमानों ने निर्दोष सिखों, हिंदुओं को मारा है और किस प्रकार सिखों ने भी वश चलते कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह मार-काट इसलिए नहीं का गयी कि फलाँ आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फलाँ आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफी था और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसका जान लेने के लिए प्रयाप्त तर्क था। जब स्थिती ऐसी हो तो हिंदूस्तान का ईश्वर ही मालिक है।

ऐसी स्थिती में हिंदूस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन 'धर्मो' ने हिंदूस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अभी पता नहीं कि यह धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नजर में भारत को बदनाम कर दिया है। और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते है। कोई विरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है, जो अपना दिमाग ठंडा रखता है, बाकि सब के सब धर्म के यह नामलेवा अपने नामलेवा धर्म के रौब को कायम रखने के लिए डंडे लाठियाँ, तलवारें-छुरें

हाथ में पकड़ लेते है और आपस में सर-फोड़-फोड़कर मर जाते है। बाकि कुछ तो फाँसी चढ़ जाते है और कुछ जेलों में फैंक दिये जाते है। इतना रक्तपात होने पर इन 'धर्मजनों' पर अंग्रेजी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग का कीड़ा ठिकाने आ जाता है।

यहाँ तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांम्प्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदूस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भले । वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतन्त्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था और जो 'समान राष्ट्रीयता और 'स्वराज्य-स्वराज्य' के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छिपाये चुपचाप बैठे है या इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले है। सिर छिपाकर बैठने वालों का संख्या भी क्या कम है? लेकिन ऐसे नेता जो सांम्प्रदायिक आंदोलन में जा मिले है, जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आते है। जो नेता दिल से सबका भला चाहते है, ऐसे बहुत ही कम है। और सांम्प्रदायिकता का ऐसी प्रबल बाढ़ आयी हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि भारत में नेतृत्व का दिवाला पिट गया है।

दूसरे सज्जन जो सांम्प्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे है, अखबार वाले है। पत्रकारिता का व्यवसाय, किसी समय बहुत ऊँचा समझा जाता था। आज बहुत ही गन्दा हो गया है। यह लोग एक-दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे-मोटे शीषर्क देकर लोगों की भावनाएँ भड़काते है और परस्पर सिर फुटौ-वल करवाते है। एक-दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए है कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे है। ऐसे लेखक बहुत कम है जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शान्त रहा हो।

अखबारों का असली कर्त्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांम्प्रदायिक भावनाएँ हटाना, परस्पर मेल-मिलाप बढ़ाना और भारत का साझी राष्ट्रीयता बनाना था. लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्त्तव्य अज्ञन फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांम्प्रदायिक बनाना, लड़ाई-झगड़े करवाना और भारत का साझी

राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से आँसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या.?'

जो लोग असहयोग के दिनों के जोश व उभार को जानते है, उन्हें यह स्थिति देख रोना आता है। कहाँ थे वे दिन कि स्वतंत्रता कि झलक सामने दिखाई देती थी और कहाँ आज यह दिन कि स्वराज्य एक सपना मात्र बन गया है। बस यही तीसरा लाभ है, जो इन दंगों से अत्याचारियों को मिला है। जिसके अस्तिव को खतरा पैदा हो गया था, कि आज गयी, कल गयी वही नौकरशाही आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है।

यदि इन सामप्रदायिक दंगों की जड़ खोजी तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। असहयोग के दिनों में नेताओं व पत्रकारों ने ढेरों कुरबानियाँ दी. उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गयी थी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास-सा हो गया जिससे आजकल के बहुत से सामप्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गए। वास्तव में जो भी काम होता है, उसकी तह में पेट का सवाल जरूर होता है। कार्ल मार्कस के तीन बड़े सिद्धांतों में से यह एक मुख्य सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के कारण ही तबलिग तनकीम, शुद्धि आदि संगठन शुरु हुए और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा हुई, जो अवर्णनीय है।

बस, सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है दरअसल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चव्वनी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है।

भूख और दुख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या न करता। लेकिन वर्तमान स्थिती में आर्थिक सुधार होना अत्यन्त कठिन है

क्योंकि सरकार विदेशी है और लोगों की स्थिती को सुधरने नहीं देती। इसीलिए लोगों को हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाना चाहिए और जब तक सरकार बदल न जाए, चैन की सांस न लेना चाहिए। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग-चेतना की जरूरत है। गरीब, मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूँजीपति है। इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हो, अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का प्रयत्न करो। इन यत्नों से तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा, इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी।

जो लोग रुस का इतिहास जानते है, उन्हें मालूम है कि जार के समय वहाँ भी ऐसी ही स्थितीयाँ थीं वहाँ भी कितने ही समुदाय थे जो परस्पर जूत-पतांग करते रहते थे।

लेकिन जिस दिन से वहाँ श्रमिक-शासन हुआ है, वहाँ नक्शा ही बदल गया है। अब वहाँ कभी दंगे नहीं हुए। अब वहाँ सभी को 'इन्सान' समझा जाता है, 'धर्मजन' नहीं। जार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी। इसलिए सब दंगे-फसाद होते थे। लेकिन अब रुसियों की आर्थिक दशा सुधर गयी है और उनमें वर्ग-चेतना आ गयी है. इसलिए अब वहाँ से कभी किसी दंगे की खबर नहीं आयी।

इन दंगों में वैसे तो बड़े निराशाजनक समाचार सुनने में आते है, लेकिन कलकत्ते के दंगों में एक बात बहुत खुशी की सुनने में आयी। वह यह कि वहाँ दंगों में ट्रेड यूनियन के मजदूरों ने हिस्सा नहीं लिया और न ही वे परस्पर गुत्थमगुत्था ही हुए, वरन् सभी हिंदू-मुसलमान बड़े प्रेम से कारखानों आदि में उठते-बैठते और दंगे रोकने के भी यत्न करते रहे। यह इसलिए कि उनमें वर्ग-चेतना थी और वे अपने वर्गहित को अच्छी तरह पहचानते थे। वर्गचेतना का यही सुन्दर रास्ता है, जो सांम्प्रदायिक दंगे रोक सकता है।

यह खुशी का समाचार हमारे कानों को मिला है कि भारत के नवयुवक अब वैसे धर्म से जो परस्पर लड़ाना व घृणा करना सिखाते है, तंग आकर हाथ धो रहे है। उनमें इतना खुलापन आ गया है कि वे भारत के लोगों को धर्म की नजर से-हिंदू, मुसलमान या सिख रूप में नहीं, वरन् सभी को पहले इन्सान समझते है, फिर भारतवासी। भारत के युवकों में इन विचारों के पैदा होने से पता चलता है कि भारत का भविष्य सुनहला है।

भारतवासियों को इन दंगों आदि को देखकर घबराना नहीं चाहिए। उन्हें यत्न करना चाहिए कि ऐसा वातावरण ही न बने, और दंगे हों ही नहीं।

1914-15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है इसमें दूसरे का कोई दखल नहीं। न ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए क्योंकि यह सरबत को मिलकर एक जगह काम नहीं करने देता। इसलिए गदर पार्टी जैसे आंदोलन एकजुट व एकजान रहे, जिसमें सिख बढ़- चढ़कर फाँसियों पर चढ़े और हिंदू मुसलमान भी पीछे नहीं रहे।

इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे है जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते है। झगड़ा मिटाने का यह भी एक सुन्दर इलाज है और हम इसका समर्थन करते है।

यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इक्टठे हो सकते है। धर्म में हम चाहे अलग-अलग ही रहे।

हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताये इलाज पर जरूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है, उससे हमे बचा लोगे।

**ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवाद के खिलाफ एकजुट हो संग्रर्ष तेज करो.**

# आम बजट 2015-16 - पूंजीपतियों के हित में जनविरोधी बजट

सब के साथ सबका विकास और अच्छे दिन आने वाले हैं करके आम जनता को भरोसा दिलाकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा (एनडीए) सरकार 2015-2016 का बजट फरवरी अखिर में संसद में पेश की है. इस में किए आवंटनों से पता चलता है कि सत्ता में आते ही रेल भाड़ा बढ़ाने से लेकर भू अधिग्रहण 2013 कानून में बदलाव तक का जो कानून बनाया, अध्यादेश लाया है वह तो साफ तोर पर सब का विकास नहीं देश विदेशी पूंजीपतियों का विकास और अच्छे दिन आम जनता के नहीं अमेरीकी साम्राज्यवाद और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आये हैं. उसी को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है आम बजट. आइये देखें इन दलाल शासकों ने आम जनता को किस तरह लूटकर देश की आमदनी को साम्राज्यवादियों के हवाले कर दिया है, किस तरह आम जनता का जाप करते हुए साम्राज्यवादियों को पोषा है.

सत्ता में आने के बाद भी कई नारे दिये जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, कौशल विकास, इसके अलावा कई जन कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की गयी है. आम जनता हो या उदारवादी बुद्धिजिवी सोचते हैं. कि इन के लिये बजट में शायद कुछ प्रावधान होंगे, मगर सभी लोगों की आशाओं व आकंक्षाओं पर पानी फेरते हुए, जनता को धत्ता दिखाकर हुए उल्टा टैक्स बढ़ाया और पहले से ही अमल में रही कुछ योजनाओं को आवंटन भारी में कटौती किए है. इस से नरेंद्र मोदी ने साफ दर्शाया है कि हम दलाल शासक वर्ग एक ही होते हैं चाहे व बिजेपी हो या कांग्रेस या कोई और पार्टी.

आइये सरकार ने संसद में पेश किए आंकड़ों से ही समझेंगे कि यह बजट किस तरह साम्राज्यवाद अनुकूल और जनविरोधी है. बजट को हम समझना है कि सरकार को अलग-अलग टेक्सों से जमा होने वाली रकम और उसे किस के लिये कितना खर्च करने की योजना को बोलते हैं. यहां दिखाया जैसा ही खर्च करने का कोई सख्त प्रावधान नहीं है. कटौती की पहली मार जन कल्याणकारी योजनाओं और कृषि क्षेत्र पर ही पड़ती है.

2015-16 आमदनी और खर्च

| पैसा आया | पैसा जाएगा |
|---|---|
| उधार 24पैसा | उधारी पर ब्याज 20 पैसा |
| इन्कमटैक्स 14पैसा | केंद्रीय योजाना 20 पैसा |
| कार्पोरेट टैक्स 20 पैसा | राज्यों को 23पैसा |
| इनडैरेक्ट टैक्स 18 पैसा | सब्सिडी 10 पैसा |
| अन्य 24 पैसा | अन्य 27 पैसा |

2015-16 आर्थिक साल के लिये कुल बजट 17,77,447 (सतरह लाख सत्तातर हजार चार सौ सेंतालिस करोड़) (पीछले साल से 96 हजार 216 करोड़ अधिक है.) इस में सिर्फ 4 लाख 65 हजार करोड़ रूपये योजनाबद्ध खर्च है. यह राशि पिछले साल से 1657 करोड़ रूपये कम है. देश का विकास योजनाबद्ध खर्च से ही होता है. बाकि खर्च देशी-विदेशी ऋणों पर ब्याज और कर्मचारियों का वेतन जैसे कामों के लिये खर्च होता है. अब जो बताया जा रहा है वह केवल 30 प्रतिशत भी नहीं है. कम से कम उतना भी खर्च नहीं करते जब दलाली पूंजीपतियों बड़े-बड़े सामंतियों से टैक्स वसूल नहीं होता तो उतना योजना खर्च में कटौती की जाती है. इसी लिये कई कृषि व सिंचाई योजनाएं दस-बीस साल पीछे रह गयी वहीं खर्च की रकम कई गुना बढ़ गई है.

## कृषि क्षेत्र की अनदेखी

आज देश में किसानों की हालात बद से बदत्तर बनती जा रही है. सव्वा सौ करोड़ जनता का पेट भरने वाला खुद आधा पेट भूखे सोने पर मजबूर है. सकल विकास राशि में कृषि क्षेत्र को 2013-14 में 9.5 प्रतिशत दिया गया तो 15-16 में आते ही केवल 2.7 प्रतिशत कर दी गयी है. कर्जों में डूबकर आत्महत्या करने पर मजबूर है.

कृषि उत्पादन में लागत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. उसकी तुलना में उत्पादन कम होता जा रहा है. प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलकर अगर फसल उगया तो न्यूनत्म दाम को तय करने में सरकार मनमानी तरीका तो दूसरी तरफ मार्किट का उचित व्यवस्था नहीं करना, कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सीडि साल दर साल कम करते जा रहे हैं. उस न देने के बराबर लाया जा रहा है. कृषि उत्पादन में लगने वाली बिजली, डिजल, खाद पर पीछले तीन सालों में ही 4 प्रतिशत से अब 1.5 प्रतिशत कर दिये हैं. वहीं साम्राज्यवादी देशों की सररकारें किसानों को 35 प्रतिशत सब्सिडी देती हैं. देश के विकास में कृषि क्षेत्र बहुत अहम भूमिका निभाता है. कृषि विकास दर 4 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है. मगर आवंटन का समय आते ही खाली झोला दिखाया है. सरकार द्वारा पेश किए आंकड़े ही बताते हैं कि सरकार किसानों को अपनी हालात पर छोड़ कर उनकी रीढ़ को तोड़ना चाहती है. सकल घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत का बीड़ उठा रही है. कृषि क्षेत्र उस पर आधार साढे 14 करोड़ किसानों को पिछले साल से 14 प्रतिशत बजट कम किया है. सरकार द्वारा नियुक्त कमेटियों ने ही माना कि सरकारी ऋण 25 प्रतिशत किसानों को मिलता है. तो बाकि 75 प्रतिशत किसान साहूकारों व महाजनों के जाल में फंस रहे हैं.

## पूंजीपति मालामाल वेतनभोगियों का हाल-बेहाल

नरेंद्र मोदी राजनीतिक और आर्थिक विषयों में अपनी सूजबूझ के बल

पर प्रधानमंत्री नहीं बना, उनकी तानाशाही का इस्तेमाल करने के लिये दलाल पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों ने मिलकर भाजापा को अधिकृत रूप से ही 363 करोड़ रूपये चुनावी खर्च दिये हैं. अनधिकृत आंकड़े तो 7000 के ऊपर ही हैं. और कार्पोरेट घरानों के ही हाथों की कठपुतली बनी प्रिंट व इल्क्ट्रोनिक मिडिया गुजरात तक ही सीमित रहे मोदी को रातों रात देश के भावी प्रधानमंत्री व सूझबूझ वाले राजनेता के रूप में पेश की है. इस परिपेक्ष में सत्ता में आये नरेंद्र मोदी और भाजपा देशी विदेशी कार्पोरेट घरानों का कर्ज चुकाने का बीड़ उठा कर अपना फ़र्ज मान कर आक्रामक तरीके से पिछले सरकार से भी ज्यादा पूंजीपतियों को उनके अपेक्षा से ज्यादा वरदान दिया है. इसी लिये देशी विदेशी पूंजीपतियों ने खुस जताया इतना ही नहीं भारत के नंबर वन पूंजीपति रिलायंस बंधुओं की मां कोकिलाबेन ने कहा कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बना है. (मोदी खुद को चायवाला बताता है तो पूंजीपतियों ने अपना बेटा इसका मतलब है कि जन्में किसी के घर में काम करे पूंजीपतियों का.)

देश में बड़े कार्पोरेट घरानों में से 23 प्रतिशत लोग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. इन लोगों से सख्ती से वसूलने की बजय खुद सरकार ने ही ज्यादा होने का कुतर्क सामने लाकर 30 से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी है. इस 5 प्रतिशत कम करने से ही सरकार को 25 हजार करोड़ रूपये का नुक्सान हुआ है. पूंजीपतियों और सामंतियों से वसूलने वाले संपत्ति कर पूरी तरह रद्द किए हैं. इन दोनों प्रावधानों से ही लगभग 49 हजार करोड़ रूपये का रजस्व कम होगा. इस के अलावा पूंजीपतियों से वसूलने वाला उत्पादन (प्रत्यक्ष) कर 8 हजार करोड़ रद्द करके उनका जगह पर अप्रत्यक्ष कर से 233 हजार करोड़ वसूलने का प्रावधान किया गया है. परोक्ष कर सीधा जनता से ही वसूला जाता है. जैसे सेवा शुल्क, 2 प्रतिशत बढ़ा दिया है. इस से 41 हजार 600 करोड़ रूपये नौकरनी करने वाले मध्यम वर्ग और गरीब जनता से वसूला जाएगा. विदेशी पूंजीपतियों पर कुछ अंकुश लगाने के लिये त्यार किए –गार- नामक योजना को दो साल तक रोके रखने की घोषणा से विदेशी पूंजीपतियों ने भी अपनी खुशी जाहिर की है. 2010 से हर साल पांच लाख करोड़ की छूट जारी है. मैं जनता का प्रधान सेवक हूं कह करके छाती फूलाने वाला मोदी का यह असली (सेवा) लूट है.

वेतन भोगियों दो लाख से अधिक आय के मध्यमवर्ग और कर्मचारियों से आयकर वसूली किया जाता है. पूंजीपतियों को 5 प्रतिशत कर छूट और संपत्ति कर को पूरा ही हटा देने वाली सररकार कर्मचारियों को एक कौड़ी के भी राहत का कदम नहीं उठाई. ऊपर से सेव कर में बढ़ोतरी कर और अप्रत्यक्ष कर से खानपान की चिजों से लेकर सभी महंगा हो गया है. और होटल में चाय से लेकर सिनेमा तक को भी ज्यादा गिनती करनी पड़ती है.

आज हमारे देश में कर प्रणाली उल्टा दिशा में चल रही है. क्योंकि साधारण तौर पर पूंजीपतियों, धनवानों पर कर लगाकर कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडियों या मध्यमवर्ग और गरीब जनता को राहत पहुंचते हैं. लेकिन देश में आम जनता पर करों का बोझ लादकर थोपते पूंजीपतियों को खुली छूट देते जा रहे हैं. क्यों 23 प्रतिशत पूंजीपति कर चोरी कर रहे हैं. क्या धंधा नुक्सान में चल रहा है. सरकारी आंकड़े से ही देश में 38 लोगों की संपत्ती डेढ़ गुणा बढ़ी है. इसका मतलब देश में कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ती जमा हो रही है. दूसरी तरफ आम जनता गरीब बनती जा रही है. कई पूंजीवादी देशों की सरकारें 30 प्रतिशत से भी ज्यादा कर लगा रही हैं. कर ज्यादा नहीं है. शासकों का इमानदारी की कमी है.

रक्षा के नाम परपिछले साल 2,22,370 करोड़ रूपये खर्च किए गए थे. इस साल सभी क्षेत्रों और कल्याणकारी योजाओं का अवंटन पर बिना संकोच कैंची चलाकार सुरक्षा के नाम पर 11 प्रतिशत बढ़ोतरी कर इस आर्थिक साल के लिये 2,46,727 (दो लाख 46 हजार 727) करोड़ रूपये आवंटन किया गया है. यह सुरक्षा के लिये खर्च नहीं किया जाता है. यह मोटी रकम साम्राज्यवादी हथियार उत्पादकों और व्यापारियों के खजाने में जाएगी. अमेरीका, फ्रांस और इज्राइल देशों की कंपनियां फायदा उठाने पर अतुर हैं. इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय को पीछले साल 56 हाजार 372 करोड़ किया तो इस साल 62 हजार 124 रोड़ रूपया आवंटन कि है. इसमें से 580 करोड़ रूपये से कश्मिर में जनता में दरार पैदा करने की साजिश से पंडितों को अलग से कालोनियां बनाने के लिये आवंटित किया बाकि 61,544 करोड़ नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल सीआरपीएफ को 14 हजार 89 करोड़, बीएसएफ को 12 हजार 517 करोड़, सीआईएसएफ को 5 हजार 196 करोड़ आवंटन किया गया है. हमें इतिहास दर्शाता है. कि अन्य योजनाओं में कटोती कर इस में ज्यादा खर्च किया जाता है.

## जनकल्याणकारी योजनाओं के आवंटनों में कटोती

केंद्र सराकर वसूलने वाले टेक्सों से राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत बढ़ाने का बहाना बता कर लगभग 40 कल्याणकारी योजनाओं को आवंटन में भारी कमी की गयी. 8 प्रधान योजनाओं पर राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय हिस्से को पूरी तरह रद्द कर 24 योजनाओं को किए जाने वाले आवंटन में भी कटोती की गयी है.

इस से पहला से ही वित्तीय संकट में फसे राज्य सरकारे इन योजनाओं को चलाना संदेह ही नहीं बंद ही होगा. एक्का दुक्का योजना आधा अधउरा चलेका क्योंकि पूरी तरह बंद करने का साहस नहीं करते क्योंकि यह सरकरें ही इन योजनाओं पर टिकी हैं.

देश में घट रहे लिंग अनुपात पर गहरी चिंता जताते हुए, घड़ियाली आंसू बहाते मोदी नें भाववेश से भाषण देकर देश का भविष्य के लिये बेटी बचाओ-बेटी

पढ़ाओ करके नारे दिया सभी ने सोचा कि काश सरकार इसके लिये बजट में कुछ प्रावधान करेगी मगर भाषण बाबा रूप में बजट से साफ हुआ है. इतना ही नहीं माता ओर शिशू सरंक्षण को भगवान के भरोसा छोड़ दिया.

देश में पांच साल से कम उमर के बच्चों में 50 प्रतिशत कुपोशण की चपेट में हैं. इसको दूर करने के लिये बनाई गयी. समग्र शिशू विकास योजना को इस बरस 50 प्रतिशत घटा कर 16 हजार करोड़ से 8 हजार करोड रूपये ही आवंटित किए गए हैं. इसका मतलब बाल मृत्यु खासकर बच्चियों का दर को न्योता देना ही है. भ्रुण हत्या करने वालों को साधारण दस साल की कडी सजा वाला कानून बनाने वाला मोदी को लाखों बच्चों को मृत्यु के मुंह में धकेल देने वाले प्रधानमंत्री मोदी को जनता क्या सजा देना है?

इसी तरह दलित और आदिवासियों को दी जाने वाली बजट में भी 50 प्रतिशत की भारी कटोती करके दलितों को 30 हजार 851 करोड आदिवासियों को 19 हजार 980 करोड़ आवंटन किए हैं. इसी तरह बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले गरीब लड़कों को स्कूल से जोड़ने के लिये मध्यह्न भोजन योजना करके पुंगी बजाने वाली केंद्र सरकार बजट में बढोतरी करने की जगा 13 हजार करोड़ के बजाय केवल 9 हजार करोड़ दिया है. क्या मार्केट में रासन दरों में कमी आई है. क्या नहीं तो शायद सरकार के नजर में बच्चे स्कूल में खाया भोजन से मोटापेका शिकार हो रहे हैं होगा. इस से गरीब बच्चों की पढ़ाई के प्रति सरकार की मनंशा साफ झलकती है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को पीछले साल दिये 35 हजार 163 करोड़ रूपये को काट कर अब 29 हजार 653 करोड़ कर देते है. गृह निर्माण और शहरी गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम को 6 हजार 8 करोड़ की बजाए 5 हजार 634 करोड़ का आवंटन किया गया है. इसका मतलब शहरों में गरीबी में कमी होना नहीं है. उन लोगों को बेसहारा छोड़ देना है. इस बजट में महिला विकास और साधिकार के लिये किए आवंट में 20 हजार करोड़ कम किए गए हैं. सरकार की नजर में अब देश की महिला विकसित हो ना नहीं हैं. महिला सधिकार से सरकार पल्ला काट लेना है. इसी तरह महिलाओं का सुरक्षा के लिये निर्भया फंड का नाम से जो एक हजार करोड़ पिछले साल आवंटन किए थे. उस में से एक रूपया भी खर्च नहीं किए. देश भर में आये दिन महिलाओं पर हो रहे निर्भया कांड का रिपोर्टों को सरकार सुनने और देखाई नहीं देता. नहीं तो क्यों एक रूपया भी खर्च नहीं किए. लातों की भूत को बातों से नहीं मनते जैसे ही भूख बदरी सरकारक को तोड़फोड़ और आगजनी से ही समझ में आती है.

## शिक्षा

दुनिया में हर देश शिक्षा और स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता के तौर पर मानता है. भारत देश आजाद 70 साल होने जा रहे हैं. मगर देश का औसतन शिक्षा 70 प्रतिशत के पार नहीं कर पाई. लज्जा जनक इस विषय से ध्यान हटाने के लिये कई योजनाएं केंद्र राज्य सरकारें बनाये हैं. और 14 साल के हर बच्चों को उचित शिक्षा का गारंटी कानून केंद्र सरकार ने बनाई है. इस का अमल के लिये हर पांच किलोमीटर दायरे में एक उच्च माध्यमिक शाला और हर 10 किलोमीटर की दूरी में कालेज का प्रबंध का दावा करने वाली सरकार जब बजट आवंटन का समय आते ही सभी वायदे, योजनाओं को भूल कर आवंटन में कटौती का कैंची आसानी से चलाई है.तभी तो हर साल दर साल हर गल्ली मोहल्ला से लेकर छोटा मोटा शहर तक प्रायवेट (निजी) शिक्षा दुकानें कुकरमुत्ते जैसे उभर दिन दुगना रात चौगुना फल फुल रहे हैं. पिछले साल के 82 हजार करोड़ को काट कर 69 हजार आवंटन कर दिये हैं. इस में भी पाठशाला शिक्षा को 10 प्रतिशत कम करके उच्च शिक्षा को 13.5 बढ़ोतरी किए यानी गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों को प्राइवेट शिक्षा खरीदने को मजबूर कर इस लिये ही कम बजट आवंटन की और शिक्षकों की नियुक्ती से लेकर उनके वेतन तक की अनदेखी करना और तो और बच्चों को स्कूलों में परोसने वाली मध्यहन भोजन में भी कटोती कर दी है.

अंततहः अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिये कार्पोरेट घरानों की मदद से सत्ता में आया यह सरकार है. कार्पोरेट घरानों और पूंजी के प्रति श्रधा और भक्ति भाव प्रकट करने में न हिचकिचाने वाली यह सरकार है. जनविरोधी योजनाओं और मजदूरों के खिलाफ श्रम कानूनों को बदल कर अमल करके, देशी, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संतुष्ट करने वाली यह सरकार है. जनता का मनोभावनाओं की उपेक्षा करते हुए उनके हितों के लिये काम न करते हुए जनता का हकों को रोंदने वाली यह सरकार है. कार्पोरेट घरानों का मुनाफा के लिये श्रम कानूनों और भू अधिग्रहण कानूनों को बदलाव किए यह सरकार है. रेलवे, बीमा, बैंक, रक्षा क्षत्रों में विदेशी पूंजी निवेश को निमंत्रण देने वाली यह सरकार है. कार्पोरेट घरानों के मुताबिक कानून व योजनाएं बनाते हुए कार्पोरेट क्षेत्र की पिट्ठू जैसे बने है. यह सरकार है.

यह बजट अमीर और गरीब के बीच के खाई बढ़ाने वाला है. विकास, नौकरियों में बढ़ोतरी, जनता का जीवन स्तर सुधारने वाला बजट जनता पर खासकर गरीब और पीछड़े वर्गों पर और अधिक बोझ लादने वाली है. कुल मिलाकर यह बजट किसानों, मजदूरों, छात्रों, गरीब, मध्यमवर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दलित और आदिवासी जनता की आकांक्षाओं पर पानी फेरने वालाहै गरीब और पिछड़े वर्गों की कल्याणकारी, कृषि, ग्रामीण विकास, बेरोजगार युवाओं को अन्यायकारी है. यह बजट कारपोरेट घरानों के दिशा निर्देशों में, कार्पोरेट घरानों के लिये बनाया गया है. इसके खिलाफ बुद्धिजिवियों और सभी तबकों की जनता को एक होकर संगर्ष तेज कर नवजनवादी क्रांति की राह में आगे बढ़ाना है.

समाप्त

# "सबके साथ - सब का विकास" के नाम पर जनता का विनाश और पूंजीपतियों का विकास

*"पहाट" भाकपा (माओवादी) महाराष्ट्र राज्य कमेटी के मुखपत्र दिसंबर 2014 में छपे मराठी लेख का स्वतंत्र अनुवाद*

लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के वैश्विक आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं. पूरे मिडिया जगत में एक ही चर्चा हो रही है कि मोदी ने राजनीति को पलट दिया है. चाय व पान की दुकानों पर इसी चर्चा की रंगत दिख रही है. मोदी द्वारा पेश की जा रही मुफ्त की चाय की घूंट से दिमाक में ये लंपट उतेजनायें फूट रही हैं. जिस की खावे बोकली उसके गावे गीत (जिसका खाये, उस के गुण गाये) की भारतीय मानसिकता (भारतीय दलालों की सं.) को अंग्रेजों से लेकर अमेरिकी साम्राज्यवाद तक सब अच्छे से जानते हैं. उन्हें पता है कि अगर उनक पेट गले तक भर दिया जाए तो वह गदद हो जायेंगे. फिर उनसे जो चाहे करवा लो. इस प्रकार वे जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के पेट को भर दिया जाए तो वह देश तक को बेचने के लिये तैयार हो जाएगा. इसी सूत्र के आधार पर साम्राज्यवादियों ने भारत में 'मेक इन प्राइममनिस्टर' मिशन को सफल किया है. ताकि वह लूट के सारे दरवाजे खोल सके.

राजनीति और अर्थनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. राजनीति अर्थव्यवस्था की सेवा करती है. तो अर्थव्यवस्था के आधार पर ही राजनीति का निर्माण होता है. साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी को अपने आर्थिक संकट में ज्यादा से ज्यादा लूट व शोषण करने के लिये ऐसी राजनैतिक परिस्थितियों व स्थिरता की जरूरत होती जो इस लूट को कायम रख से और इस कारण फूटने वाले जनाक्रोश को भी दबाने में प्रभावी भूमिका निभा सके. इसलिये इस साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी ने दक्षिणपंथी सरकारों को लाने की शुरूआत की है. भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाने की योजना पर पीछले दो सालों से खुद अमेरीका अपने दलालों के माध्यम से काम कर रहा था. उसकी कारपोरेट लाबी ने मिडीया के जरिए कृत्रिम लहर का निर्माण किया. अकेले मोदी ब्रांड के प्रचार के लिये ही 7000 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च किए गए ताकि उनके मनमाफिक सरकार बन सके. पूंजीवादी लोकतंत्र के उत्सव में जनता को केवल गिनी-पिग की तरह इस्तेमाल किया गया. बटन दबाने में पांच सेकेंड भी नहीं लगते, लेकिन पांच साल के लिये गुलाम बन जाते हैं.

## ब्राह्मणवादी, करोड़पतियों व अपराधियों का संसद में जमघट:

संसद में आजतक जिस प्रकार पूर्व में राजा-महाराजा, नवाब, जमींदार व पूंजीपति रहते थे. उसी प्रकार इस संसद में भी यही सब हैं. पूराने शोषकों के वारिस आज भी सत्ता में कायम हैं. हां कुछ नये गब्बर सिंग भी आ गए हैं. पूंजीपतियों ने भी उन नये गब्बरों के साथ जोड़ी बन ली है. संसद में चुने गए सांसदों में भी भ्रष्ट व नामी-गिरामी लुटेरे हैं. 34 प्रतिशत सांसदों पर खून, बल्तकार और अपहरण जैसे गंभीर मुक्दमें दर्ज हैं. मोदी सरकार के मंत्रीमंडल में 99 प्रतिशत मंत्री करोड़पति हैं. तब ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार किसी है. किस वर्ग की है. और किसके लिये है.

नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद सबके साथ सबका विकास लोकलुभावना नारा दिया और कई योजाओं की घोषणा किया है. ढोलनगाड़ों की थाप पर की जा रही इन घोषणाओं की सच्चाई सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है. कम से कम शासन और ज्यादा से ज्यादा प्रशासन, काले धन की वापसि, गंगा शुद्धिकरण, न्यायधिश नियुक्ति आयोग, योजाना आयोग को रद्द कर नीति आयोग का गठन, ई-गवर्नेश, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट सिटी, श्रमे मेव ज्यते, व मन की बात आदि की घोषणा की जा रही है. तो दूसरी तरफ हिंदू फासीवादियों का तेजी से प्रसार-प्रचार जारी है. उसका प्रचार करने के लिये सरकारी तंत्र (स्वायत संस्थानों) का दुरूपयोग किया जा रहा है. आरएसएस के दशहरा उत्सव (विजय दशमी) में सर संघचालक मोहन भागवत के भाषण को सरकारी टेलीविजन चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया. आरएसएस के मुखपत्र पाञ्चजन्य को भाजपा शासित प्रदेशों की ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ-साथ मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिन के अंदर ही देशभर में 600 सांप्रदायिक दंगे हुए.

जंबो मंत्री मंडल बनाने के बाद उनकी कम से कम शासन ज्यादा से ज्यादा प्रशासन नारे का गुबारा तो फूट गया है. इसी प्रकार गंगा शुद्धि करण के नाम पर केवल प्रचार व पूजा-पाठ किया जा रहा है. गंगा को प्रदुषित करने वाले किसी भी कारखाने पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. यह गंगा शुद्धि करण की बजाय जनता के साथ शुद्ध धोखेबाजी है.

## सड़े हुए दिमाक में स्वच्छ भारत का नारा:

स्वच्छ भारत यह जनता को भ्रम में रखने का ढकोसला मात्र है. स्वच्छता का संबंध सार्वजनिक स्वच्छता से होता है. सरकार अपना कचरा साफ करवाने के लिए जनता पर बोझ डाल रही है. जबकि स्वच्छता पर सरकार का खर्च बहुत कम कर रही है. स्वच्छता का भार अपने कंधो

पर ढोने वाले दलित आज अमानवीय जिंदगी जीने पर मजबूर हैं. गंदे नाले में दबकर हर साल कितने ही दलित सफाई कर्मचारी मौत के मुंह में समा जाते हैं. सिर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी कई शहरों में जारी है. मोदी मंगल पर तो यान भेज रह है. पर जमीन की सच्चाई उसे क्यों दिखाई नहीं देती. जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालने वाले इन कामगारों को सब से कम वेतन दिया जा रहा है. स्वच्छता का संबंध गरीबी व आर्थिक असमानता से है. यहां मुकेश अंबानी के एक परिवार को रहने के लिये 36 मंजिल की एंटेलिया इमारत है. तो दूसरी तरफ उसी शहर मुंबई की 65 प्रतिशत आबादी के लिये गटरगंगा की धारवी झौपड़पट्टी है. गांव की 80 प्रतिशत जनता के लिये ये अब तक शौचलय की व्यवस्था नहीं कर पाया है. पीने का पानी नहीं दे रहे, उनके लिये कोई ठोस योजना नहीं बना रहे. क्या केवल प्रचार से स्वच्छ भारत बन जाएगा. यह केवल कोरा प्रचार है. और कुछ भी नहीं. पश्चिम देशों की जनता स्वच्छ हैं. क्योंकि वहां की जनता किचड़ नहीं फैंकती. यह भारत की जनता पर गंदा रहने का सरासर आरोप है. अपने आप को जनता का सेवक कहने वाला मोदी जनता को गंदगी के लिये धमका रहा है. गंगा शुद्धि करन के नाम पर हिंदूओं के अस्तित्व के नाम पर स्वच्छ भारत जैसे नारे उच्छाल कर जनता का ध्यान मुलभूत समस्याओं से भटका रहा है. जबकि साधारण गंदगी के अलावा इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों की डंपिंग, कारखानों का जहरिला कचरा, मोटर-गाड़ियों का धुल-धुआं, खदानों आदि से हो रहे नदीनालों पर उसने चुप्पी साध रखी है. ब्रह्माणवादी हिंदू फासीवादी मानसिकता के कचरे से भरा मोदी का दिमाक स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर अत्यंत गंदगी फैला रहा है.

## काला धन – सफेदपोश नेताओं के घोटाले:

काले धन का तिलस्म खोल दिया गया है. यह खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा दिख रहा है. विदेशों में कुल कितना काला धन जमा है, सरकार को अभी तक नहीं पता है. जिन लोगों के सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नाम दिये हैं. वे सब उन देशों की सरकारों को टैक्स देते हैं जिन देशों में उन्होंने पैसे जमा करवाये हैं. अगर वह टैक्स देते हैं तो उसे काला धन नहीं माना जा सकता. यह अपनी बेईमानी को छुपाने के लिये पहले कांग्रेस ने ड्रामा किया तो अब भाजपा भी वही नाटक कर रही है. जानकारों का कहना है कि भ्रष्टाचार से जमा किया गया पैसा देश में भी बहुत ज्यादा है. यह काला पैसा देश में गुप्त रूप से सामानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है. इसमें भाजपा, कांग्रेस व देश के बड़े दलाल पूंजीपति और उनके तमाम चम्मचे शामिल हैं. इसलिये सरकार उन पर हाथ नहीं डाल रही है.

## कम, मेक इन इंडिया

इसी प्रकार यह भी कुछ और नहीं बल्कि विदेशी पूंजपतियों के लिये भारत को लूटने के सभी दरवाजे खुला छोड़ने का कार्यक्रम है. दुनिया के तमाम साम्राज्यवादी देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. इस संकट से निकलने के लिये इन पूंजीवादी व्यवस्थाओं को सस्ता कच्चा माल व सस्ता श्रम चाहिए. मोदी यह सब इस योजना के जरिए उनको मुहैया करवायेगा. भारत में आकर जब विदेशी कंपनिया चिजों का निर्माण करेंगी तो भारत को उन से कोई फायदा नहीं होने वाला है. क्योंकि उनकी बिक्री पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं होगा. दशकों से इस लंपट विदेशी पूंजी से अभी तक तो कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ है. यह पूंजी केवल हमारे देश की जमीन, नदी-नालों, जंगल पहाड़ों का दोहन कर उन्हें प्रदुषित करेगी. जमीन को बंजर बना कर छोड़ दिया जाएगा. विदेशी पूंजिपतियों पर भरोसा कर आर्थिक विकास का गुबारा फुलाया जा रहा है. यह पहले अन्य एशियाई देशों में भी हो चुका है. जैसे ताईवान, सिंगपुर, इंडोनेशिया आदि में. वहां पर यह झूठे विकास का गुबारा कब का फूट चुका है. ऐसा ही भारत में भी होगा. क्योंकि यह विदेशी पूंजी किसी एक देश में स्थिर नहीं रहती. यह वहीं भागती है जहां उसे कुछ फायदा दिखता है. आज यहां है तो कल कहीं दूसरे देश में. इस योजना से भारत में केवल दलालों की ही कमाई होगी, बाकि जनता का शोषण पहले से और अधिक बढ़ जाएगा. देश में भारी संख्या में बेरोजगारी पैदा होगी जो भयांकर रूप धारण करेगी. देश में तिव्र आर्थिक संकट व आराजकता फैल जाएगी. मोदी की यह योजना भारत को पूर्ण रूप से साम्राज्यवादियों की आर्थिक गुलाम बना देगी.

## स्किल इंडिया

यह कार्यक्रम भी एक ढकोसला के अलावा कुछ नहीं है. खुशहाल भारत का निर्माण इस कच्छुए की चाल से संभव नहीं है. इस स्किल डेवलपमेंट से केवल 30 लाख लोगों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी जबकि देश में अभी 50 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाने की जरूरत है. इस कौशल विकास ट्रेनिंग को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन एजेंसी के जरिए दिया जाएगा. इसका समन्यव करने के लिये योजना आयोग के उध्यक्ष की अध्यक्षता में नेशनल स्किल डेवल्पमेंट कोर्डिनेशन बोर्ड बनाया गया है. लेकिन इस योजना के जरिए पीछले साढ़े तीन सालों में केवल 1.35 लाख युवाओं का ही कौशल विकास किया गया है. (यह योजना मनमोहन सरकार ने शुरु की थी - सं.) राज्यों व केंद्र की सरकार ने मिलकर केवल 8.7 लाख युवाओं को ही ट्रेनिंग दी है. इस कच्छुए की चाल से यह काम जारी है. हर साल 1.3 करोड़ नयी वर्क फोर्स की जरूरत पड़ती है. लेकिन सरकार केवल 3.1 लाख लोगों को तैयार कर पाती है. यानी जरूरत का केवल 2 प्रतिशत. यानी तमाम युवाओं में से 3 होशियार युवाओं को कोई कौशल विकास की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी. कितनी भी योजना बनाने के बावजूद आने वाले 10 सालों में तमाम युवाओं को वह कौशल विकास की ट्रेनिंग नहीं दे पायेगी. यह केवल प्रचार से मीठे सपने दिखाने वाली बात मोदी सरकार कर रही है.

## सांसद या सरपंच

आदर्श ग्राम योजना कांग्रेस के निर्मल ग्राम योजना, मुलायम सिंग की लोहिया ग्राम योजना व मायवती की अंबेडकर ग्राम योजना की नकल के अलावा कुछ नहीं है. मोदी नयी बोतल में पुरानी शराब परोस रहा है. करोड़ों रूपायों पर कुंडली मारे बैठे सांसदों को केवल एक गांव के विकास की जिम्मेदारी देने का मतलब है - ऊंट के मुंह में जीरा. सांसदों को चुना जाता है देश के विकास को देखने के लिये, लेकिन उनको केवल एक गांव देकर देश की समस्याओं से ध्यान भटकाना इस योजना की साजिश है.

एक बात यह भी समझो, अगर इमानदारी से भी देश की राज्यसभा व लोकसभा के कुल 795 सदस्य अपने कार्यकाल में तीन गांव को आदर्श गांव बना भी देते हैं तो भी 2024 तक (मोदी के दस साल के टार्गेट के अनुसार) मात्र 6360 गांव ही विकसित हो पायेंगे. जबकि देश में 7 लाख गांव हैं. अगर इसी गति से गांव का विकास करना है तो आखरी गांव का नंबर कितने दशकों बाद आयेगा. यह मोदी के देवता भी नहीं बता पायेंगे. यह सरकार की कार्यक्षमता नहीं बल्कि नालायकी है. यह चालबाजी गांव की जमीनों पर कब्जा करने के लिये की जा रही है. इस योजना के लागू होते ही बड़े-बड़े बिल्डरों ने गांव में मार्च करनी शुरू कर दी है. वे भारी मात्रा में गांव की जमीनें खरीद रहे हैं. किसानों के समाने जमीन बेचने की बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है. सांसद हर गांव में घरों का निर्माण कर उन्हें बेचने की योजना बना रहे हैं. बड़े-बड़े बिल्डर यह बनायेंगे. इस से शहरों के अमीर गांव की जमीनों को हड़प लेंगे.

## स्मार्ट सिटी बनाने की झूठ

इसी प्रकार मोदी ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा भी जोर-शोर के साथ की है. इससे पहले महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना की सरकार आयी थी. तब भी उन्होंने मुंबई को सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी. वह आ कर चली गयी. बाद में कांग्रेस का विलासराव मुख्यमंत्री बना. उसने मुंबई को शंघाई बनाने की घोषणा की थी. बाल ठाकरे व विलासराव दोनों ही दुनिया छोड़ चुके हैं. लेकिन मुंबई का कचरा वैसा का वैसा ही है. छोटे उद्योगों, फेरीवालों, झोपड़पट्टी वालों को उजाड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं. अभी फिर शंघाई-मुंबई सिस्टर सिटी नाम से समझौता हुआ है. पहले से मौजूद शहरों की खराब हालात को तो सरकार सुधार नहीं सकी, और बात करती है नये स्मार्ट सिटियों की. आज विश्व के सबसे ज्यादा प्रदुषित शहर कहीं हैं तो वह है भारत. मुंबई से लेकर गड़चिरोली तक झोपड़पट्टी व खुले बहने वाले गंदे नाले भारत के शहरों की पहचान बन चुके हैं. महिलाओं तक के लिये शौचालय नहीं हैं. मलेरिया. डेंगू, चिकनपाक्स, आदि सरकार के लिये जनसंख्या नियंत्रण के औजार बन गए हैं. ऐसी स्थितियों में मोदी द्वारा स्मार्ट सिटी बनाने की योजना विदेशी पूंजी द्वारा बनाये जाने वाले चारागाह हैं. इससे मोदी के स्थानीय बड़े व्यापारी व बिल्डर भी चरेंगे.

## जनता की जेब खाली करने वाली जनधन योजना

प्रधानमंत्री जन-धन योजना संकट में फस चुकी बैंकिग व्यवस्था को बचाने का हथकंडा है. जनता की जेब में जमा थोड़ा-बहुत पैसा भी बैंकों में खींच कर पूंजीपतियों को बाजार में खोलने के लिये पूंजी मुहैया करवाने की साजिश है. इससे जनता की फायदे की बजाए नुक्सान ही होगा. संकटग्रस्त बैंकिंग व्यवस्था किसी भी तरह फायदा नहीं पहुंचा सकती. यह जनता की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाली योजना है. (अभी तक इस योजना के कारण गरीबों की जेब से 15800 करोड़ रुपये सरकार के पास चले गये हैं. सं.)

## श्रमेव ज्यते, पूंजीपतियों की.....

यह योजना मजदूरों को उनके हकों से वंचित करने वाली योजना है. मोदी सरकार ने संसद के पहले ही सत्र में मजदूर विरोधी बिल पास कर दिया है. यह मजदूरों को रुलाने वाला समय है. कानूनों के होते हुए भी आज मजदूर अपनी यूनियन नहीं बना सकता. मोदी ने किसी यूनियन बनने के लिये फैक्ट्री के कुल मजदूरों के 30 प्रतिशत मजदूरों की मंजूरी को अनिवार्य बना दिया है. इससे यूनियन बनाना मुश्किल हो गया है... कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है. कानून बनाकर मालिकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. इन कानूनों के जरिए नये व अप्रेंटिश मजदूरों को बड़ी संख्या में रख कर उनका ज्यादा शोषण किया जाएगा. मजदूरों के जमा 6 लाख करोड़ रूपयों के प्राईवेट फंड को शेयर मार्किट में लगाकर मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. यह सब श्रमेव ज्यते सुंदर नाम पर किया जा रहा है. किसी मजदूर संगठन को मंजूरी नहीं देती. यह खुलमखुला श्रम कानूनों को उलंघन है.

## मोदी पुराण और आधुनिक विज्ञान

ई-गवर्नेश, डिजीटल इंडिया की घोषणा करने वाले मोदी की विचारधारा कितनी अवैज्ञानिक, पुरातनपंथी, घोर विकास विरोधी है इस का अंदाजा मुंबई में अंबानी के हस्पताल के उद्घाटन पर दिये गए उनके भाषण से लगाया जा सकता है. मोदी ने कहा – भगवान गणेश को लगाया गया हाथी का सूंड और व महाभारत में सूतपुत्र के रूप में प्रसिद्ध करण यह साबित करते हैं कि तब ट्रांसप्लांट व जेनेटिक तकनिक भारत में मौजूद थी. यह सुन कर पूरी दुनिया भारत पर हंसी होगी. जैसा संघ परिवार ने सिखाया वैसा ही मोदी ने सीखा है. मोदी ब्राह्मणवादी जमीन पर कचरे के खाद से उगी हुई साम्राज्यवादी गाजर जैसे दिखते हैं. पिछले छह महिनों में जनता को

प्रचार के लालिपाप के अलाव कुछ भी वास्तविक रूप में नहीं दिया है. इसके विपरीत पहले से अधिक जनता पर शोषण व दमन बढ़ाने वाले निर्णय लिये गए हैं. इन फैसलों ने साम्राज्यवादी और देश के दलाल पूंजिपतियों के लिये लूटने के रास्ते और ज्यादा खोल दिये हैं.

## मोदी - मेकिंग प्राइम मिनिस्टर

मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का ठेका एवको नामक अमेरिकी कंपनी को दिया गया था. 7000 करोड़ से ज्यादा पैसा केवल उसके प्रचार पर खर्च किया गया है. जिन पूंजीपतियों ने मेक इन प्राइम मिनिस्टर नामक परियोजना में पूंजीनिवेश किया उनको इतना मुनाफा हुआ है कि वे दोनों हाथों से इसे नहीं संभाल सकते, उन्हें जेसीबी मशीन का सहारा लेना होगा. मोदी के प्रचार मैनेजमेंट व आर्थिक बजट को संभालने वाले दलाल पूंजीपति गौतम अडानी की संपत्ति इस समय अचानक 152 प्रतिशत बढ़ गयी है. उसकी शेयर पूंजी 44000 करोड़ रूपये हो गयी. वह अब भारत के प्रथम दस अरबपतियों की लिस्ट में सूमार हो गए हैं. मुकेश अंबानी के बाद व दूसरे नंबर पर आये सन फार्मा के दिलीप सिंघवी की संपत्ति 43 प्रतिशत बढ़ गयी है. इसी का नतिजा है कि देश में अचानक अरबपतियों की संख्या 59 से बढ़कर 109 हो गयी है. यह मोदी के असली विकास को दर्शाती है. अमेरिका के दलाल इन अरबपतियों में पहले दस नंबरों में आने वाले अंबानी, दिलीप संघवी, लक्ष्मी मित्तल, अजिम प्रेमजी, शिव नादर, एसपी हिंदूजा, पल्लोजी मिश्र, कुमार मंगलम, सुनिल मित्तल, व गौतम आडानी ने मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया है. मोदी ने विकास के मिठे सपने दिखाकर जनता को फसाया है. इस प्रकार मोदी सरकार इस देश को आर्थिक रूप से रसोताल में ले जा रही है. इससे भटकाने के लिये देश में सामाजिक द्वेष फैलाया जा रहा है. जनता पर ब्राह्मणवादी हिंदू फासिवादियों के हमले बढ़ गए हैं. पिछले छह महिनों में अगर सही अर्थों में देखा जाए तो सबके साथ सब का विकास का नारा जनता का विनाश- पूंजीपतियों का विकास के रूप में बदल गया है. ...

## मोदी पुराण = ब्राह्मणवाद+साम्राज्यवाद

मोदी की ये सारी योजनायें बासी खिचड़ी है. मोदी देश की जनता की जेब से पैसे निकाल कर, देश की साधन-संपत्ति को कम भाव में बेच कर, पूंजीपतियों के 'अच्छे दिन' लाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है. इंसान को इंसान न समझने वाली अमानवीय जातिव्यवस्था ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रधान सेवक बने मोदी जनता के लिये अच्छे दिन सपने में भी नहीं देखता. विदेशी पूंजी के भरोसा, जनता व देश को और ज्यादा संकट में ले जाएगा. दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह बीमार हो चुकी है. इसका एक ही इलाज है वह है समाजवादी व्यवस्था की स्थापना. सत्ताधारी वर्ग बंदूक के दम पर जनता को नियंत्रित कर रहा है. विदेशी कंपनियों से समझौते कर इस व्यवस्था को टिकाये रखने की कोशिश कर रहा है. लेकिन इस से विदेशों पर भारत की निर्भरता पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी और भारत अपनी संप्रभुता गवा कर गुलाम बन जाएगा.

नौजवानों की भूख मोदी के भाषणों से नहीं मिट सकती. मजदूर विरोधी फैसले लेने से मजदूरों में आक्रोश और ज्यादा तेज होगा. किसानों की जमीन पर मोदी के कारण संकट मंडरा रहा है. इन छह महीनों में जनता का भ्रम टूटना शुरू हो गया है. मोदी मिडिया के जरिए बड़े-बड़े भाषण देकर इस भ्रम को बनाये रखने की नाकाम कोशिश कर रहा है. उसे पता है यह आक्रोश नहीं संभल सकता, इसलिये इस जनाक्रोश को भटकाने के लिये धार्मिक दंगों को हथियार की तरह प्रयोग करना शुरु कर दिया है. माओवादी आंदोलन पर लादे गए युद्ध को और तेज करने के लिये आईएएस अधिकारियों के ट्रेनिंग सलेबस में नक्सलवाद विषय भी शामिल कर दिया गया है. और 2 लाख अर्धसैनिक बलों को माओवादी आंदोलन पर हमला करने के लिये तैनात करने की योजना बनाई जा चुकी है. इस प्रकार सत्ता के सर्वशक्तिशाली हथियार सेना को भी इस्तेमाल करने की निर्णय कर लिया गया है. मानसिक युद्ध को तेज करते हुए सरकार रेडियो व दुरदर्शन के माध्यम से माओवाद विरोधी दुष्प्रचार तेज कर दिया गया है. माओवादी नेतृत्व को खत्म करने के लिये बड़े-बड़े इनाम घोषित किए गए हैं. इसलिये युद्ध की तिव्रता और बढ़ जाएगी.

मोदी के सत्ता में आते ही हिंदू अहंकार देशभर में बढ़ गया है. इस से ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवाद सत्ता की झलक साफ दिखाई देनी लगी है. शैक्षणिक क्षेत्र में भी अध्यात्मवादी, अवैज्ञानिक सलेबस लागू करने के प्रयास तेज हो गए हैं. खुद मोदी ने गणेश व करण के नाम को विज्ञान से जोड़ कर, अपने अवैज्ञानिक मोदी पुराण की शुरूआत कर दी है. इस प्रकार मोदी की नीति देश को आर्थिक व सामाजिक रूप से पीछे ले जाने की है. इन नीतियों के मजदूरों व किसानों पर तेज गति से विपरीत प्रभाव पड़ना शुरु हो गया है. आदिवासी, दलित, महिला व अल्पसंख्यकों पर दंगे बढ़ गए हैं. और यह तेज भी होंगे. इस प्रकार इस फासीवादी सत्ता के खिलाफ सभी लोकतांत्रिक व धर्मनिर्पेक्ष ताकतों का एकजुट होकर संघर्ष करना अनिवार्य बनता जा रहा है. देश की प्रभुसत्ता, सार्वभौमिकता को बचाये रखने के लिये, देश को उंगलियों पर गिने जा सकने वाले हाथों से मुक्त करवाने के लिये, देश में सही अर्थों में जनता के राज की स्थापना के लिये, समाजवादी भारत का निर्माण करना होगा. इसके लिये क्रांति के अलावा कोई दूसरा आसान रास्ता नहीं है. इसलिये सचेत होकर देश में माओवादियों के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर या फिर ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवाद के विरोध में न्यायपूर्ण जनसंघर्षों में शामिल होकर सभी को अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है.

समाप्त

# भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक का विरोध करो

देश में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी की हिन्दुत्व फासीवादी भाजपा सरकार ने भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश को दो दिनों की चर्चा के बाद लोकसभा में 10 मार्च को पारित कराया है। हालांकि राज्य सभा में अभी चर्चा बाकी है। संसद में पूर्ण बहुमत के बावजूद संसद के भीतर और बाहर जबर्दस्त विरोध की आशंका के मद्धेनजर 31 दिसंबर, 2014 को इसे लागु किया गया था जिसके तुरंत बाद से देश भर में इस अध्यादेश के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज हो रहा है। यह अध्यादेश देश विरोधी एवं जन विरोधी खासकर आदिवासी व किसान विरोधी है। मोदी के 'मेक इन इंडिया' नारे के अनुरूप ही देशी कारपोरेट घरानों व विदेशी पूंजीपतियों को देश के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को कौड़ियों के भाव सौंपने के लिए ही उक्त अध्यादेश को लाया गया था। 'मेक इन इंडिया' दरअसल 'लूटो इंडिया' आह्वान के सिवाय और कुछ नहीं है। हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी देश की जनता खासकर किसानों व आदिवासियों का आह्वान करती है कि वे भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में धरना, जुलूस, पिकेटिंग, घेराव, चक्काजाम आदि जुझारु संघर्ष रूपों के जरिए व्यापक व संगठित जन आन्दोलन करें। प्रगतिशील, जनवादी बुद्धिजीवियों व मानवाधिकार संगठनों, मजदूरों से अपील करती है कि वे उक्त देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ आवाज बुलंद करें और देश की संपदाओं को हड़पने के देशी दलाल पूंजीपतियों व साम्राज्यवादियों की साजिशों को नाकाम करने आगे आवें।

हमारे देश की प्राकृतिक संपदाओं को लूटने के लिए सन् 1894 में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के द्वारा बनाया गया भूमि अधिग्रहण कानून ही तथाकथित आजादी के बाद से लेकर 2013 तक के 66 साल देश में लागू रहा और प्राकृतिक संपदाओं व संसाधनों की देशी, विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा बेरोकटोक लूट जारी रही। इस दौरान करीबन दस करोड़ लोग जिनमें आदिवासी सबसे ज्यादा हैं, विस्थापित हो गये। बिना मुआवजे, कम मुआवजे, बिना सही पुनर्वास, बिना पारदर्शिता एवं बिना सहमति के ही इन तमाम लोगों को विस्थापित किया गया था। खासकर 5 वीं अनुसूची के द्वारा प्रदत्त ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी जनता को बड़े पैमाने पर उनकी जल–जंगल–जमीन से बेदखल किया गया था। जनता के जल–जंगल–जमीन को हड़पकर देशी, विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने की उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण की साम्राज्यवादी परस्त, जन विरोधी नीतियों पर तेजी से अमल करने की कोशिश के तहत ही यूपीए–2 की सरकार ने दिसंबर, 2013 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में सही मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार कानून–2013 बनाया। विकास के नाम पर दरअसल भूमि अधिर्गहण को आसान बनाने के लिए ही यह कानून लाया गया था। 'जन हित' की परिभाषा के दायरे को विस्तार देते हुए भूमि अधिग्रहण को देशी, विदेशी पूंजीपतियों के हित में और उनके ज्यादा अनुकूल बनाया गया था। हालांकि देश भर में जारी विस्थापन विरोधी आन्दोलनों, किसान व आदिवासी आन्दोलनों एवं हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध के चलते इस कानून में कुछेक ऐसे प्रावधानों को जोड़ दिया गया था जो जनानुकूल नजर आते हैं। हालांकि इन प्रावधानों का पालन कहीं भी ठीक ढ़ंग से नहीं हुआ था। निजी कंपनियों के द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 80 फीसदी, सार्वजनिक व निजी भागीदारी–पीपीपी वाली परियोजनाओं के लिए 70 फीसदी मालिकों की सहमति को आवश्यक बनाया गया था। आदिवासियों के जमीन अधिग्रहण के पहले ग्राम सभाओं से परामर्श के पेसा कानून के प्रावधान को दरकिनार करके 80 व 70 फीसदी की बात कही गयी है। ग्राम सभाओं के आयोजन से लेकर मुआवजे तक हर मामले में पुलिस की लाठी, गोली, दबाव, धौंस झेलने किसान विशेशकर आदिवासी मजबूर हैं। अभी यह कानून साल भर भी अमल में नहीं था कि जनानुकूल दिखने वाले इन प्रावधानों को भी देश के विकास में बाधक बताते हुए मोदी की हिन्दुत्व फासीवादी सरकार ने इनमें देशी, विदेशी कारपोरेट घरानों को संसाधनों की सस्ती लूट की खुली छूट देते हुए पूरी तरह उनके अनुकूल संशोधन करते हुए 2013 के कानून की जगह भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 को दिसंबर, 2014 से लागु कर दिया है। यह अब जगजाहिर हो चुका है कि मोदी के विकास का मतलब है, देशी, विदेशी कारपोरेट घरानों का विकास। मोदी अब मेक इन इंडिया के नारे के अनुरूप कारपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए, पूंजी निवेश के लिए यानी बड़ी खनन परियोजनाओं, बड़े उद्योगों, बड़े बांधों, परमाणु संयंत्रों, हवाई अड्डों, सैनिका अड्डों, विशेष आर्थिक जोनों, स्मार्ट शहर आदि के लिए देश के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों खासकर किसानों व आदिवासियों की जमीन को कौड़ियों के भाव आसानी से व बरोकटोक उपलब्ध कराने की साजिश के तहत ही इस जन विरोधी अध्यादेश को कानूनी अमली जामा पहनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों, गांव में बुनियादी ढ़ांचे का विकास, सस्ते मकान, औद्योगिक कॉरिडोर और पीपीपी प्रोजेक्ट के

लिए मालिकों की सहमति के प्र. ावधान को अब पूरी तरह हटा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण से होने वाले सामाजिक प्रभाव के आंकलन से भी छूट दी गयी। इससे साफ जाहिर है कि अब किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं रहा। उसकी जमीन के अधिग्रहण के संबंध में फैसला पूरी तरह सरकार लेगी। अधिग्रहित भूमि का पांच साल के भीतर इस्तेमाल करने की समय सीमा को खत्म करके कंपनी को ही भूमि इस्तेमाल की समय सीमा तय करने की छूट दी गयी। इससे कारपोरेट कंपनियों को यह मनमानी करने की खुली आजादी मिलती है कि वे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि व समयावधि को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत कर सके। यहां यह उल्लेख करना लाजिमी होगा कि मोदी के खासम खास अदानी ने पूर्व में ही, इस तरह की छूट के बिना ही गुजरात में परियोजना के लिए प्राप्त जमीन को बेचकर 45 हजार करोड़ का जनधन हड़प लिया था। अब इस छूट के बाद क्या होगा, इसका अंदाजा लग. ाना कठिन नहीं है। पुराने कानून में सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह कानून के लागू होने के दो साल तक उसे लागू कराने कोई भी कदम उठा सकती है। नए कानून में इस समयावधि को पांच साल तक बढ़ाकर पूंजीपतियों को मनमाने छूट दी गयी है। इस तरह के किसान विरोधी एवं दलाल पूंजीपति परस्त संशोधनों के साथ संसद में इसे पारित कराने मोदी सरकार आमादा है।

देश भर में इस संशोधन विधेयक के खिलाफ तीव्र आक्रोश फुट पड़ा। जनता को दिग्भ्रमित करने नये अध्यादेश में 9 छोटे–माटे संशोधनों के साथ उसे लोकसभा में पारित किया गया है। यहां यह गौर करने वाली बात है कि संशोधन विधेयक में किसानों व आदिवासियों के हितों के विपरीत के प्रावधान यथावत हैं। जन. विरोधी भाजपा सरकार इसे 21 वीं सदी के विकास की जरूरतों को पूरा करने वाले अध्यादेश के रूप में प्रचारित कर रही है। 22 मार्च को अपने 'मन की बात' कार्यकम में न केवल देश के किसानों बल्कि समूचे देश को ही गुमराह करने की नाकाम कोशिश की। किसानों की ज्वलंत मुद्दों को छुआ तक नहीं। भूमि अधिग्रहण विधेयक के बारे में सफेद झूठ बोला। जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। यह इस बात से भी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन के अनुषांगिक संगठनों को भी इस अध्यादेश का विरोध करने व उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करने मजबूर होना पड़ा। यह अध्यादेश देश के किसानों व आदिवासियों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जल–जंगल–जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने की साजिश है। अपने ही संविधान के द्वारा आदिवासियों को प्रदत्त पांचवीं अनुसूची, पेसा व ग्राम सभाओं के अधिकारों का खुला उल्लंघन का सबसे बड़ा मिसाल है। साम्राज्यवादी वित्तीय व आर्थिक संकट के बोझ को हमारे देश की जनता खासकर किसानों व आदिवासियों के कंधों पर लादने की कोशिश का हिस्सा है।

संशोधन विधेयक के विरोधी आन्दोलनों में किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों सहित विपक्षी दल भी शामिल हैं। राजनीतिक दलों का हो हल्ला दरअसल जनता के बीच अपनी गिरती साख को बचाने की नाकाम कोशिश का हिस्सा है। विपक्षी संसदीय दलों का विरोध बेम. ानी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक ये दल भू अधिग्रहण के खिलाफ कभी नहीं रहे। अब भी ये विधेयक के खिलाफ कतई नहीं हैं। यहां यह गौर करने वाली बात है कि यह संशोधन विधेयक अधिकतर संसदीय राजनीतिक दलों के समर्थन व राज्य सरकारों से सलाह–मशविरे के बाद ही लाया गया है। अध्यादेश के खिलाफ व्याप्त जन आक्रोश को देखते हुए ये जनपक्षधरता का दिखावा करने के तहत ही अध्यादेश में कुछ छोटे–मोटे संशोधनों की बात कर रहे हैं। विधेयक विरोधी आन्दा. ेलन में शामिल गैर सरकारी संगठन भी विधेयक में कुछेक जनानुकूल संशोधनों की ही मांग कर रहे हैं या 2013 के कानून को यथावत जारी रखने की मांग कर रहे हैं। ये जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाते हैं। उस दिशा में जनता को जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। समाज में आमूलचूल परिवर्तन के लिए जारी हथियारबंद संघर्षों की राह से लोगों को भटकाने के अपने मूल मकसद के अनुरूप ही ये संगठन काम कर रहे हैं। जबकि जबरिया अधिग्रहण से प्रभावित जनता जी जान से लड़ रही है। विस्थापन के विरोध में, जल–जंगल–जमीन पर अपने अधिकार, अपने अस्तित्व व अस्मिता के लिए संघर्ष कर रही है। एक तरफ संसद में इस अध्यादेश पर बहस जारी है तो दूसरी तरफ नेशनल हाइवे प्राजेक्टों, बड़ी खनन परियोजनाओं, बड़े कारखानों, बड़े बांधों के खिलाफ यानी केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा दलाल पूंजीपतियों, बहु राष्ट्रीय कंपनियों के साथ किये गये तमाम एमओयु को रद्ध करने की मांग को लेकर देश भर में आन्दोलन उग्र हो रहे हैं। हमारी पार्टी इन तमाम आन्दोलनों का तहेदिल से समर्थन करती है और यह आह्वान करती है कि जोतने वाले को जमीन के नारे पर आधारित होकर क्रांतिकारी भूमि सुधारों के लिए हथियारबंद लड़ाई के रास्ते में आगे बढ़े। इस देश में नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध में शामिल होवें। हमारे देश के किसानों, मजदूरों, आदिवासियों सहित तमाम पीड़ित जनता की मुक्ति का सही व एकमात्र रास्ता यही है।

**....जान देंगे लेकिन जल-जंगल-जमीन नहीं देंगे....**

# भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

## केंद्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

08/12/2014

# बीजेपी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार द्वारा अपनाई जा रही ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवादी नीतियों का नतीजा है कासलपाड़ा एंबुश

## पीएलजीए के वीर योद्धाओं, कमांडरों को क्रांतिकारी अभिवादन

2 दिसंबर जनमुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) का स्थापना दिन है। समुचे देश भर के माओवादी क्रांतिकारी इलाकों में पीएलजीए अपना 14 वां स्थापना दिन जनता के साथ मनाने की तैयारी चल रही थी। तो दुसरी तरफ माओवादी संघर्ष इलाकों में लाखों की तादात में तैनात किए गए पुलिस कमाण्डों एवं अर्धासैनिक बल पीएलजीए सप्ताह में बाधा डालने के लिए अपने ''घेराव करो और खोजों'' अभियान को चला रहे थे। जिसके तहत गावों पर हमले करना, जनता को गिरफ्तार करना, क्रूर यातनाएं देना, महिलाओं पर अत्याचार करना तथा सड़क एवं रास्तों पर तलाशी अभियान जारी थे। ऐसी परिस्थिति में दण्डकराण्य के दक्षिण बस्तर डिविजन के (सुकमा जिला) चिंतागुफा एरिया के कासलपाडा में हमारे बहादूर पीएलजीए गुरिल्लाओं ने 1 दिसंबर को किए साहसिक-कार्यनीतिक प्रतिहमले में 223 बटलियन के जव. ानों को धूल चटाया जिसमें 14 जव. ान मारे गये और 15 जवान घायल हुए। साथ ही कोब्रा जवान दुम दबाकर भाग निकले। हमलें में मारे गये CRPF के जवानों के हथियारों को हमारे पीएलजीए ने जप्त कीए है। उसका विवरण इस प्रकार है - AK47-7, UBGL-3, INSAS (LMG)-3, SLR-1 और कुछ सैनिकी सामग्री गुरिल्ला अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। समुचे क्रांतिकारी आंदोलन को नेस्तानाबुद करने के मकसद से ही पिछले 5 सालों से चल रहे ऑपरेशन ग्रीन हंट के हमलों को तेज करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के पृष्ठभूमी में कासलपाडा एम्बुश को सफल किए पीएलजीए के गुरिल्लाओं एवं कमाण्डरों को हमारी केन्द्रीय कमेटी क्रांतिकारी अभिवादन पेश कर रही है। लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर BJP के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सत्ता की बागडोर संभालने के बाद हमारे पीएलजीए द्वारा किए एम्बुश को ऐतिहासिक महत्व है। मारे गये जवानों के लाशों के साथ हमारे पीएलजीए सैनिकों द्वारा किए गए तथाकथित बदसलूकी भरे व्यवहार को मिडिया द्वारा किए जा रहे प्रचार को हमारी पार्टी तीव्र भर्त्सना करती है। दरअसल, उक्त हीन संस्कृती फासिवादी शासकों द्वारा अपने बलों में किस प्रकार भरी जा रही है, यह तो गडचिरोलि के मेडरी, दोबूर जैसी कई घटनाओं को लेकर बनाए गए चित्रफित (विडियो) देखने से उनकी अस. लियत जनता समझ जाएगी।

केंन्द्र में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA की सत्ता आने के तुरंत बाद ही गृहमंत्री बने राजनाथ सिंग ने छत्तीसगड के बस्तर संभाग के लिए 10 अतिरिक्त बटालियन को भेजे। इनमें से अधिक बटालियनों को सुकमा, दंतेवाडा, बीजापूर आदी जिलों में ही तैनात किए है। नरेंद्र मोदी सरकार खुले तौर पर अपना रही देशद्रोही नीतियों के तहत बस्तर पहुंचे सभी बल यहां के खदान क्षेत्रों में ही अपना डेरा जमाए है। रावघाट रेल लाईन का निर्माण समेत कई क्षेत्रों में मौजूद खदानों की खुदाई का काम शुरू करने के लिए जोरों से प्रयास जारी है। बस्तर संभाग के दंतेवाडा, सुकमा, बीजापूर, नारायणपुर, बस्तर, कोण्डागांव और कांकेर जिले एंव राजनांदगांव, दुर्ग जिलों के साथ महाराष्ट्र के गडचिरो. लि व गोंदिया जिलों में तमाम पु. लिस एवं अर्धासैनिक बलों द्वारा चलाये जा रहे फासिवादी ऑपरेशन

ग्रीन हंट के बर्बर दमन नीतियों से समुचा दण्डकारण्य उबल रहा है। सुकमा, दंतेवाडा एवं बीजापूर जिलों के ग्रामीण इलाके में छत्तीसगड सहित पडोसी राज्यों के बल बिना किसी रूकावट के लगातार हमले कर है। छत्तीसगड बलों के साथ महाराष्ट्र के सी-60 एवं आंध्रप्रदेश के ग्रे-हाउण्ड्स संयुक्त हमले करते हुए जनता में दहशत फैला रहे है। खदानों की खुदाई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही माओवादी आंदा. लन को नेस्तानाबूद करने सुरक्षा बल तमाम जंगलों की छानबिन कर रहे है। बस्तर संभाग के आय.जी. एस. आर.पी.कल्लूरी के नेतृत्व में चल रहे 'घेराव करो और खोजों' कार्रवाई से स्त्री-पुरूष सहित बच्चों व बुढ़ों में भी भय निर्माण कर रहे है। ब्राह्मणी हिदू फासिवादी ताकतों के सत्ता में आने के बाद क्रांतिकारीयों के सिरों पर पहले से घोषित इनामों को कई गुणा और बढ़ाया गया है। क्रांतिकारी ताकतों को लुभाने के लिए नई योजनाओं के साथ कई प्रलोभनों को भी फैला रहे है। क्रांतिकारी इलाकों मे अत्यंत साधारण जनता को गिरफ्तार कर इनामी नक्सली के रूप में पेश किया जा रहा है। माओवादीयों के बड़े पैमाने पर आत्मसर्मपण की झूठी कहानियों का प्रचार करने में बस्तर के आय.जी. कल्लूरी ने गोबेल्स को भी पछाड दिया है। उक्त खोखले एवं मनगढ़ंत आत्मसमर्पण करने की कहानियों को बुद्धिजीवी भी बड़े पैमाने पर पर्दाफाश कर रहे है। तो दूसरी तरफ पुलिसी अत्याचारों के विरोध में हजारों की संख्या में जनता सडकों, पर उतरने के लिए मजबूर हो रही है। अक्तुबर 2014 को भैरमगड एरिया के पोटेगांव के पास 3 मा. हला मड़काम रामबत्ती, जमली व लक्ष्मी की हत्या की और उसी एरिया के नेमेड गांव की सामबत्ती पर पुलिस द्वारा पाशविक अत्याचार कर उसकी हत्या के विरोध में बड़े पैमाने पर जनता एकत्रित होकर विरोध रेली निकाल कर दोषी पु. लिसों को सजा देने की मांग किए है। अपने गांववालों को अवैध रूप से गिरफ्तार कर जेल डालने के विरोध में हजारों आदिवासी स्त्री-पुरूष मार्च-2014 को दंतेवाडा जेल के सामने धरना दे चुके है। जुलाई माह में कोण्टा क्षेत्र के पिढ़मेल गांव के हिडमा, रामुम के निवासी वेटी हडमे की हत्या की गयी थी। अगस्त में जग्गवरम में पोडियम गंगा की हत्या की गयी थी। कोतागुडा के निवासी दोडी भीमा की हत्या की गयी। बीजापुर जिले के डुमरी पालनार ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा किए गए अंधाधूंद गोलीबारी में कारम आयतु की मृत्यु हुई। सितम्बर 30 से अक्तुबर 2 तक बीजापूर, सुकमा, दंतेवाडा जिलों के ग्रामीण इलाकों में पुलिसों ने आतंक मचाया। मुरंगा गांव के कोरसा आयतु को पकड कर मार डाला। इसी बिच गडचिरोलि जिले के विकासपल्ली गांव के युवा किसान बिजू कोला को झुठी मुठभेड में मार डाला। इन सभी निहत्थे आदिवासियों को माओवादी कहकर पुलिस प्रचार कर रही है। दण्डकारण्य की संघर्षशील जनता इन तमाम हत्याओं का तीव्र विरोध करते हुए पुलिस के नृशंसता को प्रकट कर रही है। खदानों की खुदाई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन को लेकर गंभीर समस्याओं का सामना कर रही जनता हजारों की संख्या में 10 अक्तुबर को ''चलो किरंदुला'' रॅली निकाले है। दिन-ब-दिन पुलिस द्वारा बढ़ाते जा रहे तथाकथित आत्मसर्मपण, आतंकी हमले एवं अत्याचारों के विरोध मे हमारे DK-SZC द्वारा 8 नवंबर को 'दण्डकारणय बंद' का आह्वान कर चूंकी है। यह तो सब जानते है कि उस बंद में संघर्षशील जनता लडाकु संकल्प से बड़े पैमाने पर हिस्सा लेकर उसे सफल किये है। पुलिस एवं अर्धासैनिक बलों के हमलों के बिच में जिंदगी एक युद्ध के रूप में तब्दील हो रहे जगह की जनता के लिए विद्रोही जंग छेडना अनिवार्य हो रहा है।

आर.एस.एस. के अधिपत्यवाली NDA का सत्ता के रूप में ब्राह्मणीय हिंदू फासिवादी शक्तियां दिल्ली की गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद से ही छत्तीसगड़ राज्य में हिंदू धर्मोन्मादी ताकतों की गतिविधियों में काफी इजाफा हुआ है। राज्य में पिछले 12 सालों से सत्ता में रह रही भाजपा सरकार खुले तौर पर उनके समर्थन में उतरे है। स्थानीय सांसद दिनेश कश्यप के नेतृत्व में बस्तर में चल रहे ''घर वापसी'' अभियान नामक हमले से जनता काफी परेशान हो रही है। स्कुलों में हिंदू प्रार्थनाएं, अंधधार्मिक शक्तियां खुलेआम पूरे सप्ताह हिंदू देवी-देवताओं की पुजा. पाठ, आदिवासियों के भगवानों का अपमान करना आदी जैसे विषयों के चरम में धर्मपरिर्वन हो रहा है। देशभर में मुस्लिमों पर लगातार हमले बढ़ रहे है, दलितों की हत्याए की जा रही है, मजदूर कानूनों को मालिको के पक्ष में बदल दिया गया है। संसद में और संसद के बाहर भी खुद सरकार ही भारत के संविधान की धज्जीयां उडा रही है।

मोदी सरकार बड़ी आक्रमकता से LPG एजेंडे को आगे बढ़ाने से देश पर नव-उदारवाद की पकड़ और भी मजबूत हो रही है। इसको राष्ट्रवादी मुखौटे के पिछे छुपाने की कोशिशे चल रही है। संघ परिवार के राष्ट्रवादी मुखौटे की आड़ में मोदी सरकार देश को थोक में बेचने की नीतियों को आक्रमक रूप से लागू कर रही है। मोदी छाप-विकास एजेंडा को लागू होने से बड़े पैमाने पर विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो रही है; जिससे आदिवसियों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को दृढता से सामना कर रही जनता पर भारत के फासिवादी शासक वर्ग द्वारा चलाये जा रहे ग्रीन हंट ऑपरेशन के नए चरण की शुरूवात की गई है। (कासलपाडा हमले के तुरंत बाद केंन्द्रीय गृहमंत्री फैसला कर 11,000 अतिरिक्त बल बस्तर के जंगलो में तैनात करने के लिए भेज रहे है। पहले से हजारों की संख्या में मौजूद बल के साथ और अतिरिक्त बलों के शामिल होने से आदिवासी जनता के रोजमर्रा की जिंदगी में और भी तकलीफे बढ़ेंगी)

जनता के पक्ष में खड़ी पीएलजीए बड़े हौसलों और साहस के साथ ऑपरेशन ग्रीन हंट के विरोध में लड़ रही है; और उसी के तहत तोंगपाले, मुरमुरियां और ताजा कासलपाडा उसी की एक और कड़ी है। ब्राह्मणीय हिंदू फासिवाद खतरे के विरोध में हमारी पार्टी के नेतृत्व में दृढ़ता से लड़ रही क्रांतिकारी जनता एवं उनकी सेना पीएलजीए के समथ. 'न में छात्र, बुद्धिजीवी, शिक्षक, कर्मचारी, जनवादी प्रमीयों, पत्रकार एवं मिडिया कर्मी, लेखक, कलाकार, पर्यावरणविद तथा आदिवासियों के हितैषीयों से खड़ा रहने की हम अपील कर रहे है। तथा, देश में अपनी न्यायपुर्ण समस्याओं पर संघर्ष कर रही कई सामाजिक तबकों की जनता को आतंकवादी घोषित कर, दबाने की बात कर रहे फासिवादी ताकतों को लडाकु जनसंघर्ष एवं जनयुद्ध को तेज करके सबक सिखाने की अपील करते है। ब्राह्मणीय हिंदू फासिवादी ताकतों को आज हम एक होकर मुकाबला नहीं करने से हम हमारे प्यारे भारत देश को नहीं बचा पायेंगे।

(अभय)

प्रवक्ता, केंद्रीय कमेटी

**भाकपा (माओवादी)**

## ओड़िशा राज्य कमेटी

### 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को काले दिवस के रूप में मनाओ.
### दुनिया का नंबर-1 आतंकवादी ओबामा वापिस जाओ.
### झूठे गणतंत्र दिवस समारोह के अध्यक्ष बनने आ रहे ओबामा का विरोध करो.
### देश को दोनों हाथों से बेचने के लिये मोदी का ओबामा को निमंत्रण.

जब नरेंद्र मोदी जी-20 देशों की मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा से मिला तो ओबामा ने मोदी को 'मेन ऑफ दा एक्शन' कहा था. यह उसी देश के राष्ट्रपति के शब्द हैं जिसने दस साल तक मोदी को गुजरात दंगों का दोषी मानकर विजा तक नहीं दिया था. लेकिन पिछले 8 महिनों में ऐसा क्या हो गया कि मोदी अमेरिका की आंखों का तारा बन गया? क्यों पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के 'गणतंत्र दिवस' पर अध्यक्ष बनने के लिये तैयार हो गया? इसका एक ही जवाब है- भारत का विशाल बाजार, जल-जंगल-जमीन व उस में दबी पड़ी अकूत खनिज संपदायें. अमेरिका को लाचार बनाता उसका अर्थिक संकट! नरेंद्र मोदी ने आते ही बेहद चतुरता व शब्दों की जादूगरी के साथ साम्राज्यवाद व बड़े दलाल पूंजीपतियों के लिये योजनाओं की शुरूआत कर दी. उसने युवकों को नौकरियों का लालच देकर मेक इन इंडिया की घोषणा की, लेकिन इसका मतलब है - कि आओ अमेरिका, युरोप, जापान, चीन के पूंजीपतियो हमारे देश से सस्ता कच्चा माल, सस्ता श्रम लूटो, और अपने-अपने आर्थिक संकट दूर करो. दुनिया के विकसित माने जाने वाले 34 देशों में 45 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जो साम्राज्यवादी अपने देश के युवा को नौकरी नहीं दे पा रहे वो भारत के 50 करोड़ युवाओं को क्या नौकरी देंगे? मोदी ने विदेशी कंपनियों व बड़े दलाल पूंजीपतियों के लिये "मन की बात की है" कि - मैं कानून बनाने में नहीं तोड़ने में विश्वास रखता हूं. इसका मतलब है श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन आधिकार कानून आदि जो थोड़े बहुत मजदूर,

किसान, आदिवासियों के हित में दिखते थे. उनको भी पूरी तरह से खत्म कर देना,

यही देख कर मोदी के आका ओबामा ने फरमाया कि मोदी मेन ऑफ द एक्शन हैं. वह लगातार 9 महीनों से साम्राज्यवाद के लिए व अडानी, अंबानी, वेदांता, टाटा, बिरला आदि के हित में एक्शन पर एक्शन कर रहा है.

साम्राज्यवाद व खासतोर पर अमेरिका की दलाली करने में नरेंद्र मोदी ने मनमोहनसिंग कई कोस पिछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत ओड़िशा के नवीन पटनायक व छत्तीसगढ़ के रमन सिंग भी मोदी के सुर में सुर मिलाकर राज्य के खनिज भंडारों को अमेरिकी व अन्य विदेशी कंपनियों को सौंपने के लिये जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं. वे डॉलरों में दलाली खाने के लिये लालायित बठे हुए हैं. इसलिये नवीन पटनायक ने ओड़िशा में 100 से ज्यादा कंपनियों से एमओयू किए हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पूरे बस्तर को बेचने की ठानी हुई है. बस्तर, रावघाट, चारगांव का लोहा, नियमगिरी, कोरापुट, रायगड़, गंदमर्दान का बाक्साइट स्थानीय आदिवासियों के लिये जी का जंजाल बनता जा रहा है.

ओबमा अमेरिका में जारी आर्थिक संकट को दूर करने के लिये यहां के खनिज संसाधनों के सस्ते में ठेके लेने के लिये गणतंत्र दिवस पर अध्यक्ष बनने के लिये तैयार हुआ है. ओबामा अकेला नहीं उसके साथ पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों के सीईओ की बारात भी आयेगी.

जो देश खुद दर्जनों देशों की जनता द्वारा चुनी गयी सरकारों का तख्ता उलट चुका है, जो फिलिपिंस की क्रांतिकारी जनता के जनयुद्ध पर दमन चलाने के लिये फिलिपिंस की फासीवादी सरकार को पूरी मदद दे रहा है. जो फिलिस्तीन के बच्चों पर बमबारी करने के लिये फासीवादी इजरायल सरकार की वकालत करता है. वह किस मुंह से गणतंत्र व जनतंत्र की बात कर सकता है. अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है. भेड़िया भेड़ की खाल में छुपकर अपनी असलियत नहीं छुपा सकता. ओबामा की नाक के नीचे काले अमेरिकियों को सरेआम गौरे पुलिस वाले गोलियों से भून देते हैं, उन पर अमेरिका में मुकद्दमा तक नहीं चलता, हजारों काले अमेरिकी नस्लवाद के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं. लेकिन अमेरिकी गणतंत्र आंख मूंदे चेन की सांस सोता है. ओबामा को क्या नैतिक अधिकार है कि वह गणतंत्र की बात करे.

ओबामा और मोदी के हाथ हजारों निर्दोष जनता के खून से रंगे हैं. फासीवादी संघ परिवार ने जबरन, डर व लालच दिखाकर घर वापसी के नाम पर अल्पसंख्यकों को हिंदू बनाने का अभियान तेज कर दिया है. गणतंत्र दिवस के दिन भारत का संविधान लागू हुआ बताते हैं. लेकिन मोदी व संघ परिवार अपने ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं. वे खुद धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं. मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि देश 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान से चलेगा या फिर आरएसएस के संविधान से चलेगा.

हमारी ओड़िशा राज्य कमेटी भाकपा (माओवादी) 26 जनवरी 2015 को ओबामा के भारत दोरे का विरोध करती है. ओड़िशा की तमाम जनवाद पसंद व प्रगतिशील ताकतों सहित मेहनतकश जनता से अपील करते हैं कि ओबामा के दौरे के विरोध में 26 जनवरी को प्रतिरोध दिवस का पालन करें. मोदी की साम्राज्यवाद व बड़े पूंजीपति परस्त नीतियों के विरोध में गणतंत्र दिवस को काले दिवस के रूप में मनायें. हम ऐलान करते हैं कि भारत का संविधान व गणतंत्र पूंजीपतियों, जमींदारों व साम्राज्यवादियों की लूट को जारी रखने का ही हथकंडा है. यह जनवादी व जनहितकारी संविधान नहीं है. केवल और केवल जनयुद्ध के जरिए ही सच्चे गणतंत्र की स्थापना की जा सकती है.

**प्रवक्ता**

शरतचंद्र माझी

**ओड़िशा राज्य कमेटी**

## दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

### दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा का बहिष्कार करें.

9 मई 2015 को प्रधानमंत्री की छत्तीसगढ़ यात्रा का भाकपा (माओवादी) कड़ा विरोध करती है. हम राज्य के तमाम लोगों, जनवादियों, प्रगतिशील व्यक्तियों, पार्टियों, मजदूरों और किसानों, आदिवासी और गैर आदिवासियों के सामाजिक संगठनों से अपील करते हैं कि इस यात्रा का बहिष्कार करें, जो बड़ी कार्पोरेट कंपनियों को एमओयू कर राज्य की प्राकृतिक संपदा को बेचने के लिये हो रही है. हम अपील करते हैं कि प्रतिरोध के लिये तमाम तरीके जैसे चक्काजाम, रमनसिंग व मोदी का पुतला दहन आदि आपनायें. यह बहिष्कार मेहनतकश जनता के संघर्ष का प्रतिक है, खासकर किसान व आदिवासियों को जो अपनी जिंदगी, पहचान को लिये, अपने जल,जंगल, जमीन की और खनिज भंडारों की रक्षा के लिये लड़ रहे हैं.

जब से मोदी सत्ता में आया है. तब से अभूतपुर्व रूप से आक्रमक तरीके से अपनी ऐसी वित्तीय व औद्योगिक नीतियों को लागू कर रहे है जो सीधा घरेलू व विदेशी कार्पोरेट कंपनियों को लाभ पहुंचाती हैं. देश का विकास करने नौजवानों को नौकरियां देने के लोकलुभाव और एक दम झूठे नारे 'मेक इन इंडिया' के जरिए मोदी ने विदेशी व घरेलू बड़े औद्योगपतियों के लिये सारे दरवाजे खूले कर दिये हैं. देश के जल-जंगल-जमीन और खनिज भंडारों को लूटने की सुविधा प्रदान करने के लिये मोदी भू-अधिग्रहण बिल लेकर आया. यह तथ्य है कि मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं है. वह दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रधान सेवक है जिसने प्राकृतिक संसाधनों को लूटवाने के लिये उनकी सेवा में प्रस्तुत करने मेक इन इंडिया शुरू किया है. और रमन सिंग भी छत्तीसगढ़ को उनकी सेवा में पेश करने के लिये -मेक इन छत्तीसगढ़- लेकर आया है. यह उसके बजट और नई औद्योगिक नीति से साबित हो जाता है. लोह अयस्क और अन्य खनिज संपदा के दोहन के लिये बनाई जा रही दल्ली-रावघाट रेल लाईन के लिये केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गयी है. अभी पूंजापतियों को और अधिक सुविधायें देने के लिये मोदा आ रहा है. रेल लाईन को रावघाट से जगदलपुर तक विस्तार की घोषणा की जाएगी, अल्टारा मेगा स्टील प्लांट के लिये एमओयू किया जाएगा, और नयी राजधानी में पुलिस हैडकवार्टर का उद्घाटन करेगा. यह एक सुवियोजित योजना का हिस्सा है.

बस्तार संभाग और राजनांदगांव में माईनिंग परियोजनाओँ को लागू करने के लिये, रावघाट, चारगांव, आमदायी, कुव्वे, बुधीयारीमाड, पल्लामाड आदि में सरकार अपनी संवेधानिक शक्तियों, पांचवी अनुसूची, पेसा, ग्राम सभा को अधिकारों आदि का बुरे तरीके से उल्लंघन कर रही है. उसने माड़ की एक चौथाई जमीन पर सैनिक प्रशिक्षण स्कूल खोल कर सैना की तेनाती का काम शुरु कर दिया है. इसलिये माड़ समेत सारे संघर्षरत इलाके में कुंबिंग अभियान और गांव पर हमले जारी हैं. खुफिया जानकारियों के जरिए और झूठी मुठभेड़ों के हमले पीएलजीए पर लगातार जारी हैं. हमारी पार्टी तमाम जनता से अपील करती है कि हिंदुत्व फासीवादी बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाकू और संगठित जन आंदोलन खड़ा करें. अपने प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर जल-जंगल-जमीन और खनिज संपदाओं को बजाने के लिये अपनी आदिवासी अस्तित्व की रक्षा के लिये संघर्ष करें. दंडकारण्य क्रांतिकारी जनयुद्ध को हर संभव मदद और समर्थन करें. जनता पर युद्ध आपरेशन ग्रीनहंट का विरोध करें.

**गुड्सा उसेंडी**

## ओड़िशा राज्य कमेटी

# ओड़िशा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को विस्थापित करने का विरोध करो. ग्रीनहंट के तहत शुरु किए जा रहे सलवा जूडुम-2 को मुंहतोड़ जवाब दो.

हमारी ओडीशा राज्य कमेटी प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ यात्रा का कड़ा विरोध करती है. यह यात्रा पूंजिपतियों को देश की खनिज संपदा कौड़ियों के भाव बेचने के लिये है. यह यात्रा साम्राज्यवादी विदेशी कंपनियों के हाथों देश को गरवी रखने के लिये है. डीकेएसजेडसी द्वारा दिये गए 9 मई बंद के आह्वान का हम समर्थन करते हैं ओड़िशा में कालाहंडी, बलंगिर, बरगड़, नवरंगपुर, नुआपाड़ा व छत्तीसगढ़ के महसमुंद, गरीयाबंद, धमतरी जिलों में बंद का आव्हान करते हैं. जनता से अपील है बस्तर आदीवासी जनता को विस्थापन से बचाने के लिये बंद को सफल बनाये. उनका साथ दे.

मेगा स्टील प्लांट से किसी भी आदीवासी को नौकरी नहीं मिलेगी. पहले से मोजूद बैलाडिला खदान में दो प्रतिशत कर्मचारी भी स्थानीय नहीं है तो अब किसको कितनी नौकरी मिलेगी यह समझा जा सकता है. रमन सिहं इस से दस हजार नौकरी मिलेगी कहता है लेकिन बस्तर में तो लाखों लोग बेरोजगार है उनको इस से क्या मिलेगा केवल विस्थापन. दस हजार को नौकरी देकर दस लाख लोगों को उजाड़ना कौनसा विकास है.

सलवा जूडुम पार्ट टू पूरी तरह से मोदी प्रायोजित है. यह किया जा रहा है कार्पोरेट घरानों के हितों के लिये. 2005 जून 5 को सलवा जूडुम शुरु हुआ था, मई 2005 में टाटा ने बस्तर के लोहंडीगुड़ा में 19500 करोड का ग्रीन फिल्ड स्टील प्लांट लगाने की घोषणा की थी. अब मोदी डिलमाली में 24000 करोड के निवेश कर फिर मई 2015 से सलवा जूडुम को शुरु करवा रहा है. जनता ने महेंद्र कर्मा का व सलवा जूडम का क्या हश्र किया इस से वे सबक नहीं ले रहे हैं. सलवा जूडम से बस्तर की जनता पर सरकारी युद्ध और तेज हो जाएगा. मोदी इसके लिये सिधा भारत सेना को उतारने के लिये त्यार हो गया है. हम बुद्धीजिवीयों, मानवअधिकार कार्यकार्ताओं से अपील करते हैं कि बस्तर की जनता को सरकारी फासीवादी हिंस्सा से बचाये. आदीवासियों को आदिवासियों के हाथों खत्म करवा कर, कार्पोरेट घरानों को खनिजों को लूटवाने की नीति का विरोध करे.

प्रवक्ता - शरत चंद्र मांझी

ओड़िशा राज्य कमेटी- भाकपा (माओवादी)

## डिवीजनों से रिपोर्ट....

### डेबरीगढ़ रेंज ऑफिस पर पीएलजीए की कार्रवाई

ओड़िशा राज्य के बरगढ़ जिले में डेबरीगढ़ नाम से एक अभ्यारण्य है. इसमें स्थित गांवों को विस्थापित करने के लिये त्यारियां चल रही हैं. आस-पास के गांव वालों को जंगल में जाने से मना किया जा रहा है. यह अभ्यारण्य महानदी के किनारे है. इसलिये स्थानीय लोगों को नदी से मछलियां पकड़ने से भी रोका जा रहा है. लोग न वनोपज संग्रह कर सकते, न लकड़ी ला सकते और न ही खेतीबाड़ी कर सकते. खेतों से जंगली जानवरों को खदेड़ना भी जुर्म हो गया है. एक तरह से कहें तो पूरे इलाके में जंगल विभाग का आतंक है. जंगल विभाग वाले लोगों को बंदूक दिखा कर डरा रहे हैं. 2012 में इस इलाके में माओवादी पार्टी ने अपना विस्तार किया तो लोगों ने दिल खोल कर पार्टी का स्वागत किया. लोगों की मांग थी कि जंगल विभाग वालों को जन आदालत में लाकर उनके जुल्मों को रोका जाए. इस प्रकार लोगों की आकंक्षाओं के मद्देनजर 30 मार्च 2014 को लखनपुर रेंज ऑफिस पर पीएलजीए ने हमला किया. लेकिन वहां से रेंजर भागने में सफल रहा लेकिन उसके दो रिव्लवार पीएलजीए ने जप्त कर लिये.

रेंज ऑफिस त्यारी के नाम पर थाना कैंप लगाने के लिये एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही थी. हमारे छापामारों ने 7 अप्रैल 2014 को निर्माण कार्य में लगे तीन वहानों को भी आग के हवाले कर दिया. इन कार्रवाईयों से लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली. लोग पुलिस व वन विभाग की लूट के खिलाफ संघर्ष के लिये कमर कस रहे हैं.

### पारसाहीदादर गांव पर पुलिस व वन विभाग के हमले की निंदा करो.

महासमुंद जिला, ग्राम पंचायत तमोरा के गांव परसाहीदादर पर वन विभाग, ततहसिलदार सहित पुलिस के 200 जवानों व वन विभाग के 150 लोगों ने मिलकर गांव पर हमला बोला. वे साथ में चार जेसीबी मशीनें लाये थे. पूरे गांव के 80 के आसपास घरों को गिरा दिया गया है. इसके अलावा घरों से दाल, चावल, गाय, बैल, मुर्गे, बकरियां, बर्तन, कपड़े, नकद 80 हजार रूपयों सहित 5 लाख की संपत्ति को जप्त कर लिया है. लोगों के पास खाने-पीने का सामान नहीं बचा. वन विभाग गांव वालों पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है. इस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय आदिवासी समाज ने महासमुंद में कई दिनों तक धरना दिया. धरने को स्थानीय विधायक विमल चोपड़ा ने भी समर्थन दिया.

बलांगिर-बरगढ़-महासमुंद डिवीजनल कमेटी सचिव कामरेड प्रमोद ने प्रशासन की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए एक प्रैस विज्ञप्ति भी जारी की थी. उन्होंने लोगों से आव्हान किया कि जल-जंगल-जमीन को बचाने के लिये जन आंदोलन तेज करो और आगामी चुनावों का बहिष्कार करो. प्रैस विज्ञप्ति में कहा गया था कि लोगों को विस्थापित करने वाले अधिकारियों को गांव से मार कर भगा दो. जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे नारे पर जनसंघर्ष को आगे बढ़ाओ.

### भूमकाल दिवस मनाया गया

10 फरवरी भूमकाल दिवस को जोरशोर के साथ मनाया गया. इस दिन बस्तर मुक्ति संग्राम के आदिवासी योद्धा शहीद गुंडाधुर को याद करने के साथ-साथ आदिवासी विद्रोही नेता गेंदसिंग, बाबूराव सड़मेक और वीर नारायण सिंग को भी याद किया गया. एक पंचायत के स्कूल में इस का समारोह आयोजित किया गया था. जनता के साथ साथ स्कूली छात्रों ने भी इसमें भाग लिया. पोस्टर भी लगाये गए.

### 26 जनवरी को मनाया काला दिवस

सीतानदी एरिया रिसगांव एल.ओ.एस. इलाके में झूठे गणतंत्र दिवस के दिन काला दिवस मनाया गया. पोस्टरों व पर्चों के साथ प्रचार चलाया गया.

### 23 मार्च को मनाया शहादत दिवस

23 मार्च शहीद भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव के शहादत दिवस को सितानदी इलाके में मनाया गया. शहीदों की याद में पोस्टर व पर्चे जारी किए गए. उनको शिक्षकों व छात्रों में विशेषरूप से वितरित किया गया. इसके अलावा पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के जवानों व निम्न स्तर के अधिकारियों को माओवादी पार्टी द्वारा जारी की गयी अपील को भी इलाके में वितरित कियागया. इसके अलावा एसपीओ पर भी एक पर्चे का वितरण किया गया.

### शहीद सप्ताह मनाया गया.

28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2014 तक इलाके में शहीद सप्ताह का आयोजन किया गया. सितानदी के दो गांव को मिलाकर एक आम सभा का आयोजन किया गया. इसके अलावा पूरे इलाके में बेनर, पोस्टरों व पर्चों के जरिए प्रचार किय गया. इस मीटिंग का आयोजन कामरेड सीमा की अध्यक्षता में हुआ. संगठन कमेटी सदस्या कामरेड सुकराम ने झंडा फहराया. इसके बाद शहीदों को याद करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया और इसके बाद अमर शहीदों की याद में नारे लगए गए. इसके बाद सांस्कृतिक दल ने शहीदों की याद में उनके गीत गाकर श्रद्धांजली अर्पित की. आपरेशन ग्रीनहंट का आव्हान करते हुए कामरेड झांसी ने अपनी बात रखी.

# सितानदी इलाके में जनविरोधी पुलिस मुखबिरों का सफाया

## सालेभाटा का महादेव मंडावी खत्म

ग्राम पंचायत खल्लारी के अंतर्गत आने वाले गांव सालेभाटा के निवासी महादेव मंडावी का पीएलजीए ने 25 मार्च 2015 को सफाया कर दिया. सिहावा थाना के संपर्क में रहकर वह पीछले डेढ़ साल से मुखबिरी का काम कर रहा था. जिस समय हमारी पार्टी इस इलाके में आयी थी तब महादेव पार्टी के संपर्क में आकर कुछ दिन जनसंगठन में काम किया था. बाद में पुलिस ने उसको एरिया कमांडर घोषित कर उस पर इनाम रखा था. धीरे-धीरे वह पार्टी के नाम पर पार्टी विरोधी काम करने लगा. वह दुकानदारों, ठेकेदारों से पार्टी के नाम पर पैसे वसूलने लगा था. बाद में जनता व पार्टी से गद्दारी करते हुए अपने छोटे भाई को एसपीओ के रूप में भर्ती करवाया. पार्टी के पूछे जाने पर उसने अपने भाई का बचावा किया और कहा कि वह फेक्ट्री में काम करता है.

तब हमारे स्थानीय दस्ता ने जन आदालत लगाकर उसके परिवार व महादेव को समझाया था कि वह पार्टी विरोधी, जनविरोधी कामों में भाग न ले. लेकिन न उसका भाई व न महादेव इस बात को माना. आखिर पूरी तरह से पुलिस के साथ मिलकर पार्टी को इलाके से खत्म करने के लिये काम करने लगा. कई बार उसने दस्ता के होने की सूचना पुलिस को दी. इसका एक भाई शंकर एसपीओ है, दूसरे दो भाई गेंदलाल व सहदेव भी पुलिस की मुखबिरी करते हैं. महादेव सीतानदी इलाके के जंगल, नदी-नालों में घुम कर दस्ता का समाचार जुटाता था. और गांव-गांव में लोगों को मुखबिर व युवकों को एसपीओ बनाने का काम भी करता था. पार्टी को खत्म करने के इरादे से काम कर रहे महादेव मंडावी का खात्मा आखिर पीएलजीए के हाथों होकर ही रहा. इसकी मौत की जिम्मेदारी सिहावा पुलिस थाने इंसपैक्टर, नगरी के टीआई व धमतरी के एसपी की है जिन्होंने उसे मुखबिर बना कर बलि का बकरा बनाया.

## हात्मा भालूपानी का पांडुराम नैताम खत्म

ग्राम पंचायत हात्मा भालूपानी के निवासी पुलिस मुखबिर पांडुराम नैताम को पीएलजीए ने 4 अप्रैल 2015 को मौत की सजा दी. पांडुराम 2011 से ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहा था. यह गांव का पटेल था. पार्टी जब गांव में जाती तो वह लोगों पर दबाव डाल कर मीटिंगों में भाग नहीं लेने देता था. इतना ही इसने अपने लड़के को एसपीओ में भी भर्ती करवा दिया था. एक बार वह पीएलजीए के हाथ लग गया था. लेकिन झूठ बोल कर बच निकला था.

पहले इनको जन आदालत लगाकर पार्टी विरोधी कामों से दूर रहने और जनता के साथ मिलजुल कर रहने की समझाईश दी गयी थी. लेकिन पांडूराम ने घमंड में आकर इस बात पर कान नहीं दिये और कोंडागांव पुलिस के साथ मिलकर मुखबिरी करने लगा था. 2011 में उनके गांव में जब दल ने डेरा डाला तो वह भारी संख्या में पुलिस को लेकर आया था. लेकिन तब हमारा दल सुरक्षित रिट्रीट हो गया था. इस तरह की घटनाएं कई बार हुई. लेकिन अंत में उसे पीएलजीए ने मौत के घाट उतारना पड़ा.

# सोनाबेड़ा वन अभ्यरण्य -विकास के नाम पर विनाश का नंगा नाच

नुआपाड़ा और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे वन्यप्राणियों से भरपुर सोनाबेड़ा अभ्यरण्य में बाघ, भालू, हिरण आदि वन्यप्राणियों के साथ-साथ मुख्यत आदिवासी जनजातियां - चौखट भूंजिया, पहारिया, गंडा आदि निवास करती हैं. लेकिन विगत कुछ बरसों से इस इलाके में माओवादियों ने अपनी उपस्थिती दर्ज करवाई है. अभ्यरण्य की सुरक्षा के लिये वन विभाग द्वारा इसे नुआपाड़ा, कोमना, सोनाबेड़ा तीन परिक्षेत्रों में बांटा गया था. सोनाबेड़ा में इसके अधिन 12 फारेस्टर व 35 फारेस्ट गार्ड कार्यरत हैं. फारेस्ट गार्ड----- की हत्या करने के बाद से फारेस्ट कर्मचारियों ने यहां आना बंद कर दिया था. गत बाघ जनगणना कार्यक्रम में भी यहां कामकाज बंद रहा. इसी बीच यह इलाका माओवादियों की अश्रयस्थली बन गया. इस परिस्थिति से निपटने के लिये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश नुआपाड़ा आकर विशेष पैकेज की घोषणा किया था. लोग को सरकार के प्रति आशावादी हुए और खुद के परिवार व इलाके के विकास के सपने देखने लगे. विकास कार्यों के पूर्ण करने के लिये जिला कलेक्टर व आरक्षक अधिक्षक को विशेष जिम्मेदारी प्रदान की गया थी. इसके साथ साथ जिले में हजार हजार कोबरा, सीआरपीएफ, एसओजी, आईआरबी आदि अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया. इनके लिये सोनाबेड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने के लिये लाखों-लाख रूपये भी खर्च किए गए. विकास की जिम्मेदारी एसपी उमाशंकर दास ने अपने हाथों में ली. यहां विकास के नाम पर विनाश का नंगा नाच हुआ. वन विभाग की अनुपस्थिती में बिना अनुमति कार्य किए जा रहे हैं.

कुछ साल पहले सोनाबेड़ा से जामगांव तक ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण करना शुरु किया था. लेकिन उस वन्य प्राणी सुरक्षण कानून व ओड़िशा वन कानून के अंतर्गत कई

आदिवासियों को सजा हुई थी. आज पुलिस की सुरक्षा में हजार-हजार सागवान, साल आदि के पेड़ों को मशीनों से काट कर सड़क का निर्माण किया जा रहा है. वन्य प्राणियों की सुरक्षा को ताक पर रख कर भारी विस्फोटकों से पत्थर तोड़ कर रास्ता बनाया जा रहा है. 25 से 30 फूट चौड़े इस रास्ते से नुआपाड़ा से सोनाबेड़ा की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही कम होगी. इसके अलाव एक मुख्य सड़क आगे है.

माओवादियों का मुकाबला करने के लिये जाने वाले जवान जंगल में आग लगा रहे हैं. यहां पर स्थित जवानों के कैंपों के लिये टनो-टन लकड़ी पेड़ काट कर इस्तेमाल की जा रही है. इसके खिलाफ बुद्धिजिवियों व पर्यावरण प्रेमियों में रोस है. पुलिस व जवानों द्वारा वन कानूनों के खुले उल्लंघन पर साधारण जनता में चर्चा का विषय बने हुए हैं.

## ....पाठकों की राय...

जारी है जनसंग्राम
मानव को मानव जैसा जीने के अधिकार के लिये जनसंग्राम
दुनिया से मानव-मानव के बीच अमानवीय युद्ध को सदा-सदा के लिये मीटाने का जनसंग्राम
गुमनाम असंख्य दमीत प्रतिभाओं को उभारने का जनसंग्राम
आपको हमको हम सबको मार्ग दिखाती जनसंग्राम
संघर्ष के सिलसिला को जारी रखने को जनसंग्राम
वर्ग विहीन मानव सभ्यता को तरासता जनसंग्राम
आओ हम सब मीलकर आगे बढ़ाएं जनसंग्राम
जनसंग्राम, जनसंग्राम, जनसंग्राम
लाल सलाम जन संग्राम.

लाल सलाम.

जनसंग्राम के द्वारा पूरे स्टेट की समसामयिक रिपोर्ट हमारे हाथों तक पहुंचाने के लिये आप सभी कामरेडों को सादार धन्यवाद. आशा करते हैं आगे भी जनसंग्राम का अंक हमे प्राप्त होता रहेगा. वर्तमान सारी प्रतिकुल परिस्थिति के बावजूद जनसंग्राम पत्रिका को जारी रख पाना ही हम सबके लिये एक उपलब्धी है. वैसे तो कहने को हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है. क्योकि हम सभी को पठन-फाठन सामग्री का नितांत अभाव है. आप और हम सब यह समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी में शिक्षकों की बहुत कमी है. साथ ही नेतृत्व कारी कामरेड्स की संख्या में हास हुआ है. काम की अधिकता और हमारी संख्या में कमी के कारण कामरेडों को अनेक काम करना पड़ता है. जिसके कारण एकाग्रता भंग होना स्वाभाविक है. साथ में भाषा की समस्या भी है. हम सभी अलग-अलग क्षेत्रों से आये हैं. एक दूसरे की भाषा में ठीक से पकड़ बनाना बहुत कठिन काम है. यानि बहुत सारे कारणों से पत्रिका में कहीं-कहीं वाक्यों में त्रुटी हुई है. और कहीं-कहीं का के जगह को और को के जगह का आता है. साथ में ही वाक्य में शब्द सेटिंग में त्रुटी भी हो रही है. स्थान के नामों में त्रुटी है. हमारी समस्या पार्टी के साथी समझते हैं. मगर पार्टी से बहार पत्रिका पाठकों को यह समझना कि गड़बड़ क्यों हुई कठिन है. इसलिये वे हमारी त्रुटियों को अलग ढंग से लेंगे. हमारे शैक्षिक स्तर पर प्रश्न करेंगे. इसलिये सभी कामरेड्स से निवेदन है कि धीरे-धीरे त्रुटियों को सुधानरे की कोशिश करें. क्योंकि हमारी पार्टी की प्रतिभा के मान-सम्मान का सवाल है. यहां व्यक्ति नहीं, पार्टी का सवाल है. इसलिये और कड़ी मेहनत की आवश्यकता को समझते हुए आगे बढ़ना है.

- संतोष, बीबीएम डिवीजन

संपादक मंडल जनसंग्राम लाल सलाम

21 सितंबर पर निकाला विशेषांक मिला. पढ़ कर बहुत खुशी हुई. खासकर पार्टी के दस साल पर कामरेड संग्राम का साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा और बहुत सी बहुमूल्य जानकारियां मिलीं.

मुझे जनसंग्राम का तीसरा अंक नहीं मिला है. कृपा पहुंचाने की कोशिश कीजिये. आदिवासी इलाकों में हिंदू धर्म बहुत ही आक्रमाक तरीके से घुसपेठ कर रहा है. यह दलितों पर भी हमले कर रहा है. जनसंग्राम दलित व आदिवासियों की आवाज को उठाती है. इसके लिये धन्यवाद.

आपका एक शुभचिंतक

खोलिभितर एरिया, नुआपाड़ा

## पाठकों से अपील

दो साथियों ने अपनी राय जनसंग्राम पर भेजी है. हम पाठकों की राय का सम्मान करते हैं. और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी कमियों की और ध्यान दिलाया और हमारी प्रशंसा भी की. इसी तरह बाकि पाठकों से भी हम अपील करते हैं कि जनसंग्राम आपकी अपनी पत्रिका है. पत्रिका पढ़ने के बाद आप अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें जरूर भेजिये. इसके अलावा आपके इलाके में पीएलजीए की कार्रवाईयों, संघर्षों, सभा-सम्मेलनों और जनता पर होने वाले दमन की रिपोर्टें भी भेजें.

**संपादक मंडल**

*Jansangram2015@gmail.com*

*पेज आखरि से जारी....*

## घटनाक्रम

8 मार्च 2015 को सुबह 11.30 बजे के करीब यह घटना हुई. हमारे 4 कामरेड्स सुरेश (एरिया डिप्टी कमांडर), रुकमति और फूलबति (जुनागढ़ एरिया कमेटी सदस्य) व एक दल सदस्य सफर कर बुरी तरह से थके हुए थे. पार्टी कमेटी द्वारा सौंपी गयी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये वे कड़ी मेहनत कर दो दिन के सफर को एक दिन में ही पूरा कर दिये थे. तेलनदी को पार कर वे सुबह 5 बजे छूरा पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए थे. उनकी अगली प्लानिंग थी दोपहर 2 बजे तक खाना-पीना खाकर, आराम कर अगले सफर के लिये निकलना.

सुबह आकर वे झिल्लियां बीछा कर सो गए. एक-दो घंटा आराम करने के बाद उन्होंने पानी के पास डेरा डाला. पानी के तीनों तरफ पहाड़ थे. वे बीच में थे. इस जगह को सुरक्षा के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता. उनके रिट्रीट होने के लिये केवल एक ही रास्ता वहां था. वह गड्ढे में थे. आसपास लकड़ काटने की आवाज आ रही थी. एक कामरेड सिविल में होकर वहां तक पेट्रोलिंग करके आया. उसे कोई संदेह नहीं हुआ कि आसपास दुश्मन है. लगभग साढ़े छह बजे एक आदमी आया. उससे दो महिला कामरेडों ने करीब घंटेभर तक बात की तो उसने एक पास के गांव का नाम बता कर अपना परिचय दिया. हमारे कामरेड संतुष्ट हो गए और उससे कुछ सब्जी लाने के लिये कहा. लेकिन वह 11 बजे आया. कुछ बेंगन और टमाटर दे कर चला गया. बस इसके करीब 20 मिनट बाद अंधाधुंध फायरिंग होने लगी. पुलिस वाले पहाड़ पर थे. हमारे साथी नीचे गढ़ा में. एक कामरेड जो सिविल पेट्रोलिंग कर आया था अपनी ड्रैस पहन रहा था. जबकि दो झिलियों पर सोये हुए थे. एक महिला कामरेड नाले में गयी हुई थी. पुलिस ने न तो सरंडर होने का काशन दिया न ही कोई चेतावनी दी. हमारे कामरेडों को प्रतिरोध का कोई मौका नहीं मिला. एक कामरेड घायल हो गया. लेकिन वह वहां से घेरा तोड़ कर बच निकला. दो महिला कामरेड भी नाला से होती हुई बहार निकलने में कामयाब हो गयी. लेकिन कामरेड सूरज वहां से बचने में सफल नहीं रहा. उसके शरीर पर केवल सिर पर एक गोली का निशान है. बाकि शरीर पर गोलियों के निशान नहीं है. इस से साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने कामरेड सूरज की पकड़ कर ठंडे दिमाक से हत्या की है.

जो दो महिला कामरेड बचकर निकली उन्होंने पहाड़ के नीचे गांव बंडारकच्छार में शरण ली. उनके साथ एक बंदूक थी. वे ड्रैस में ही थीं लेकिन उस गांव के एक मुखबिर ने पुलिस को फोन कर उनके यहां होने की सूचाना दी. पुलिस ने तुरंत आकर जिस घर में दो कामरेड थीं उस घर को घेर लिया. उस घर के बुजुर्ग मुखिया की बेसूध पिटाई की. गांव के बुजुर्ग व्यक्ति व रुकमति व फूलवति को भवानीपटना ले जाया गया. गांव वाले को पिटाई कर, धमकी देकर छोड़ दिया गया. लेकिन रुकमति और फूलबति को 8 दिन तक यातएं दी गयीं. उनको अवैध हिरासत में रखा गया. जबकि कानून कहता है कि किसी को भी पुलिस पकड़ने से 24 घंटे के अंदर आदालत में पेश करना अनिवार्य है. अमानवीय यातानएं देकर उनको 16 तारीख को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया. और पत्रकार सम्मेलन बुला कर झूठे ब्यान जारी करवाये. 16 तारिख को उन्होंने इसलिये चुना क्योंकि हमारी डिवीजनल कमेटी ने 16 तारिख इस बर्बर कार्रवाई के खिलाफ बंद का आह्वान दिया था. उस आव्हन में मुख्य मांग यह भी थी कि पुलिस की अवैध हिरासत में मौजूद रुकमति और फूलबति को कोर्ट में पेश किया जाए.

## हमारा आह्वान

कामरेड सूरज उर्फ सूरेश ने पुलिस के सामने घुटने न टेकते हुए वीरगति को प्राप्त किया. उसने जुनागढ़ सहित पूरे देश की जनता की मुक्ति के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया है.

जुनागढ़ एरिया की जनता से हमारी पार्टी आह्वान करती है कि कामरेड सूरज की शहादत का बदला लेने के लिये, अपने जंगल-पहाड़-जमीनों की रक्षा करने के लिये एक जूट होकर माओवादी पार्टी में शामिल हों. विदेशी-बहुराष्ट्रीय कंपनियों, महाजन सूदखोरों, जमींदारों के खिलाफ संघर्ष खड़ा करो.

इस घटना के बाद छूरा पहाड़ की जनता में पुलिस द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है. माओवादियों को मदद देने, खाना-पानी देने के आरोप लगाकर उनको तंग किया जा रहा है. हम पुलिस व अर्ध सैनिक बलों की इस कार्रवाई कड़ी निंदा करते हैं.

ओड़िशा के बुद्धिजिवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि छुरा पहाड़ की बर्बर घटना की स्वतंत्र जांच के लिये आगे आयें. और सूरज की ठंडे दिमाक से की गयी हत्या के, रुकमति और फूलबति पर अवैध हिरासत में यातानायें देने, उनको जबरन सरंडर करवाने वाले पुलिस अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करें.

पीएलजीए बहादुर योद्धाओं से हमारा आह्वान है कि हमारी पार्टी का इतिहास कुर्बानियां देकर आंदोलन को विस्तार करने का इतिहास रहा है. ओड़िशा में विस्तार के समय से अब तक हमारी पार्टी दर्जनों जनता के प्यारे सपूतों की कुर्बानी दी हैं. कुर्बानियों से न डरते हुए, केंद्रिय कमेटी द्वारा दिये गए विस्तार के महत्वपूर्ण कर्तव्य को पूरा करने के लिटे जीजान से काम करें. शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिये उनके दिखाये गए सहास व बहादुरी के रास्ते पर आगे बढ़ें. ☆

**कामरेड सूरज की संक्षिप्त जीवनी**

# कामरेड मिरिया गोटा (जुनागढ़ एरिया कमेटी सदस्य और उप कमांडर) उर्फ सुरेश, सूरज, शिवलाल अमर रहे.

दिनांक 8 मार्च 2015 को कालाहंडी जिला, छुरा पहाड़, गोडलाझरन गांव निकट उड़िशा पुलिस द्वारा की गई एक बर्बर फर्जी मुठभेड़ में हमारी पार्टी की मैनपुर-नुआपाड़ा संयुक्त डिविजन में जुनागढ़ L.O.S डिप्युटी कमाण्डर और एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम कामरेड सूरज (उर्फ मिरया गोटा, शिवलाल उम्र 24 वर्ष) शहीद हुआ है. इसी घटना में पुलिस ने दो महिला माओवादी एसी.एम कामरेड्स फूलबत्ती, रूकमती को पकड़कर 8 दिनों तक यातना देते हुए दबाव डालकर आत्मासमर्पण किया करके मीडिया में दिया गया है। हमारी डिविजनल कमेटी लोगो से आह्वान करती है देश की मुक्ति के लिए, जनता के लिए सेवा व संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलि देने वाले माओवादी सदस्यों पर किए गए इस बर्बर हमले की निंदा करें।

आइये कामरेड सूरज का क्रांतिकारी जीवन पर नजर डालें, इससे प्रेरणा लेकर क्रांति की राह में आगे बढ़ने का संकल्प लें. दण्डकारण्य में माड़ डिविजन (नरायणपुर जिला) कुतुल एरिया कमेटी कुस्तूर मेट्टा गांव के आदिवासी माड़िया समाज, गोटा परिवार में 1990 में दूसरी संतान के रूप में जन्म लिया था कामरेड सूरज। अभूझमाड़ नाम से प्रसिद्ध माड़ पीछड़े आदिवासि जनजाति के रूप में जाना जाता है. वहां 1910 में बस्तर मुक्ती संग्राम यानि महान भूमकाल विद्रोह में यहां माड़ की जनता खासकर गोटा परगाना, नेलनार ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाया थी। ऐसी ऐतिहासिक वीर भूमि में कामरेड सूरज का जन्म हुआ था.

जिस समय दण्डकारण्य में क्रांतिकारी संघर्ष तेजी पकड़ रहा था। उस समय के साथ कामरेड सूरज की उम्र बढ़ती गयी. वह बाल संगठन, जन मिलिशिया में सदस्य रहकर काम किया. माड़िया आदिवासी समाज में पहले से ही मौजूद सामूहिक जीवन पद्धति को आगे बढ़ाया।

माड़ डिविजन के आकाबेड़ा गांव में 2007 में S.T.F के 70 पुलिस वालों ने गांव को घेरा था। उस समय सूरज का L.G.S गांव में था. बिना नुकसान के पुलिस का घेरा तोड़कर बाहर निकल आये थे, शहिद कामरेड जग्गू गोटा एक पुलिस को मारकर एक एक 47 रायफल ले आया था। उस घटना में कामरेड सूरज सदस्य के रूप भाग लिया था। वह उनके गांव में निर्मित क्रांतिकारी जनताना सरकार के मार्ग दर्शन में जनता के साथ सामूहिक उत्पादन बढ़ाने, हर प्रकार जनता को मद्दत करने और सुरक्षा प्रधान करते हुए काम किया। पार्टी दूरा जनसेना के महत्व को बताकर जनमुक्ती छापामार सेना में भर्ती के आह्वान पर 2006 में कामरेड सूरज अपनी 16 साल की उम्र में भर्ती हो गया. तब से 2008 तक करेलघाट लोकल गुरिल्ला दस्ता में सदस्य के रूप में काम किया. यहीं पार्टी सदस्यता ग्रहण किया. पुलिस के नेटर्वक के खिलाफ दृड़ता से लड़े थे। उस क्षेत्र में कई प्रतिरोधी कारवाईयों में शामिल हुआ था। 2008 से 2011 तक राज्य कमेटी सदस्य का गार्ड के रूप में काम किया. 2010 में एक कंपनी के रूप में छत्तीसगढ़-उड़िशा सीमा में विस्तार इलाके में की गई राजनितिक प्रचार में खुलकर भाग लिया। 2010 अक्टुबर 9 को हुई पड़कीपाली (महासमुंद) घटना में एसीएम बन गया. तब से 9 कामरेडों का शहदत बाकी फोर्स तितर-बितर होने पर भी उस नए इलाका में अकेला रहकर भी जनता की मदत से 5 दिन के बाद पार्टी से आ मिला. 2011 से 2014 तक नुआपाड़ा डिविजन में कोलभितर दस्ता में काम किया। 2014 में नये दस्ते जुनागढ़ के डिप्यूटी कमाण्डर का दायित्व लेकर काम कर रहा था।

बचपन से ही क्रांतिकारी माहोल में विकसित हुआ कामरेड सूरज अपनी 9 साल की पूर्णकालिन क्रांतिकारी जीवन में कई घटनाओं में हिम्मत के साथ डटे काम किया। जनमुक्ती छापामार सेना में भर्ती होने के बाद ही राजनितिक के साथ-साथ पढ़ाई भी सीखा और हिन्दी, छत्तीसगढ़, भूंजिया, उड़िया भांषाएं भी सीखा. 5 फीट 4 इंच कद का और सांवला रंग, हंसमुक चेहरा, सीदा-सादा ईमानदार , मेहनती. जनता से कामरेडो से मिलजुलके रहना कामरेड सूरज की पहचान थी. उपरोक्त विषयों से सीख लेकर हम शहिदों का सपना पूरा करने क्रांति की राह में आगे बढ़ेगें। दुशमनों के इस तरह अभियानों हमे कुछ नुकसान होगा. लेकिन इस दीर्घकालिन जनयुध्द में अंतिम विजय पीड़ित जनता के ही होगी यह ऐतिहासिक सच है।

छत्तीसगढ़, उड़िशा सीमा तक सीमत माओवादी जन संघर्ष अब उड़िशा राज्य कमेटी की नेतृत्व में दोनों राज्य में बड़े इलाका में संघर्ष जारी है. इस से दुश्मन घबराकर, इसे रोकने की नापाक कोशिश कर रहे हैं. निश्चित रूप से इसमे दुशमन कामयाब नही होगें। हमारी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) चाहे कितना भी कुरबानिया देना पड़े पिछे नही हटने वाली है. आज शोषक-शासक वर्ग देश पर,जनता पर अर्धसैनिक,सैनिक बलों को भेजकर और साथ में सुधार मोहिम के साथ ग्रीनहंट नाम से युध्द चला रहे हैं. इस बढ़ते क्रूर दमन में भी पार्टी, हमारी जनमुक्ती छापामार सेना आपके साथ ही डटी रहेगी. जनसमस्याओं का हल करने संघर्ष तेज करें। जन प्रतिरोध तेज करके ही अपना हक, अधिकार हासिल कर सकते हैं. इसी तरह शहिदों का सपना पूरा कर सकते हैं। कामरेड सूरज को यही सच्ची श्रध्दांजली होगी.

# गोडलझरन की बर्बर कार्रवाई

# माओवादी आंदोलन के विस्तार को नहीं रोक सकती.

## शहीद मिरिया गोटा उर्फ सूरज, सुरेश, शिवलाल अमर रहे

8 मार्च 2015, को कालाहांडी जिला के क्रूर एसपी ब्रिजेश कुमार राय के नेतृत्व ओड़िशा पुलिस व एसओजी ने मिलकर गोलामुंडा ब्लाक के छुरा पहाड़ पर एक बर्बर घटना को अंजाम दिया. हमारी जुनागढ़ एरिया दस्ते के चार कामरेडों को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की. इस फायरिंग जुनागढ़ एरिया के डिप्यूटी कमांडर कामरेड सूरज को पकड़ कर गोली मार दी गयी. एक कामरेड घायल हुआ और दो महिला कामरेडों को फायरिंग के अगले दिन मुखबिर की सूचना पर बंडारकच्छार गांव से पकड़ लिया. यह कार्रवाई पुलिस मुखबिरों की सूचना पर की गयी. हमारे दस्ते पर किए गए इस क्रूर हमले से ओड़िशा शोसक-शासक वर्गों के नापाक इरादे सफल नहीं हो सकते. इस तरह की घटनाओं से माओवादी आंदोलन का विस्तार नहीं रुक सकता. जनता अपने प्यारे शहीद से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी.

अमर शहीद कामरेड मिरिया गोटा

### इस बर्बर घटना को क्यों अंजाम दिया गया...

कालाहांडी जिला विस्थापन विरोधी संघर्ष के रूप में देश व दुनिया के लिये एक मिशाल बन चुका है. नियमगिरी, काशिपुर की जनता अपने जल-जंगल-जमीन को बचाने के लिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ सफल संघर्ष चला रही है. जिस कारण से वेदांता, हिंडालको जैसी बहुराष्ट्रीय दलाल कंपनियों के बाक्साईट निकालने के इरादे पूरे नहीं हो रहे हैं. जनता को संगठित कर इस संघर्ष को नेतृत्व दे रही है हमारी माओवादी पार्टी. इसलिये साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों व उसके दलाल शासक वर्ग नवीन पटनायक, मोदी जैसों के लिये माओवादी पार्टी एक नंबर दुश्मन बनी हुई है.

गोलामुंडा, जुनागढ़ ब्लाक, कार्लापाट इलाके और खासकर छुरा पहाड़ में भी भारी मात्रा में खनिज संपदाये –सोना, हिरा, बाक्साईट आदि है. कई विदेशी व दलाल देशी कंपनियों की नजर इस इलाके पर लगी हुई है. कार्लापाट विल्डलाईफ सेंचूरी का दर्जा प्राप्त है. लेकिन बाक्साईट निकालने के लिये उसके लिये भी एमओयू हो चुके हैं. छुरापहाड़, कार्लापाट, नियमगिरी, काशिपुर आदि की खनिज संपादओं के दोहन के लिये पीछले साल नवीन पटनायक ने भवानीपटना से लेकर जुनागढ़ रेल लाईन का भी उद्घाटन किया है. इसलिये जुनागढ़, गोलामुंडा, छुरा पहाड़ की जनता पर भी विस्थापन की तलवार लटक रही है. हमारी पार्टी जनता को इस विस्थापन के विरोध में संगठित करने के लिये कुछ समय से प्रयास कर रही है. इसलिये मैनपुर-नुआपाड़ा डिवीजन के अंतर्गत हमारी कमेटी ने जुनागढ़ एरिया कमेटी का गठन किया था.

शोसक-शासक वर्ग इस से घबरा उठे. इस का अंदाजा दिसंबर से मार्च तक के स्थानीय समाचार पत्रों में छपी खबरों से अंदाजा लगाया जा सकता है. लगातार कालाहांडी जिला को माओवादी प्रभावित जिला के तौर पर चिन्हित कर इसके लिये ज्यादा से ज्यादा फोर्स को अवंटन करने के लिए कंपनियां व उनके दलाल मांग कर रहे हैं. पेपरों में लिखा जा रहा है कि- 2013 में माओवादियों ने इस जिले में भारी उपस्थिती दर्ज करवाई है. माओवादियों के कारण विकास काम ठप पड़ गए हैं...गोलामुंडा तक माओवादियों ने पांव पसार लिये हैं. इस से उनका डर साफ झलकता है कि माओवादी जनता को संगठित कर उनकी लूट पर पानी फेर देंगे. इसलिये छुरा पहाड़ पर कालाहांडी पुलिस विशेष नजर रख रही थी. उसने गांवों में अपने मुखबिर नेटवर्क को त्यार किया और इस बर्बर कार्रवाई को अंजाम दिया. लेकिन न तो कभी शहादतों से आंदोलन रुका है. और न ही रुकेगा. हमारी पीएलजीए इस का बदला जरूर लेगी.

*शेष पेज 34 पर...*

www.bannedthought.net/India/JanSangram/index.htm